



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 189]
No. 189]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अगस्त 27, 1998/ भाद्र 5, 1920
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 1998/BHADRA 5, 1920

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1998

अंतिम जांच-परिणाम

विषय : चीन जनवादी गणराज्य से धातुकर्मीय कोक के आयात के संबंध में पाटन-रोधी जांच—अंतिम जांच-परिणाम

सं. 8/2/97-एडीडी :—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए

क. प्रक्रिया

1 प्रारंभिक निष्कर्षों के पश्चात् नीचे वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया :

1.1 निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा जाएगा) ने चीन जनवादी गणराज्य से (जिसे इसके पश्चात् चीन तथा चीन पी. आर. कहा जाएगा) धातुकर्मीय कोक (जिसे इसके बाद मैट कोक तथा कोक कहा जाएगा) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के बारे में 20-3-98 की अधिसूचना द्वारा प्रारंभिक जांच-परिणाम अधिसूचित किए थे तथा हितबद्ध पार्टियों से इसके प्रकाशन की तारीख से 40 दिन के भीतर अपने विचार लिखित रूप में भिजवाने का अनुरोध किया था ।

1.2 प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति प्रेषित की, जिन्हें इस पत्र की तारीख से 40 दिन के भीतर प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने विचार, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया ।

1.3 प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच निष्कर्षों की एक प्रति चीन जनवादी गणराज्य के नई दिल्ली स्थित दूतावास को भी इस अनुरोध के साथ भेजी थी कि निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों को प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने-अपने विचार भिजवाने की सलाह दी जाए ।

1.4 प्राधिकारी ने सभी सम्बद्ध पक्षों को दिनांक 8-6-98 को मौखिक रूप से अपने विचार रखने का मौका दिया । मौखिक रूप से विचार रखने वाले सभी पक्षों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में देने का अनुरोध किया गया । उन्हें सलाह दी गई थी कि विरोधी पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां प्राप्त कर लें और यदि उनका कोई खंडन करना है, तो उसे प्रस्तुत किया जाए ।

1.5 प्राधिकारी ने वह सार्वजनिक फाइल सभी सम्बद्ध पक्षों को उपलब्ध कराई जिसमें विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों तथा विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों के अगोपनीय अंश रखे थे । जिन पक्षों ने लिखित रूप में इस फाइल के निरीक्षण का अनुरोध किया था, उन्हें सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई ।

1.6 प्रारंभिक जांच परिणाम घोषित करने से पूर्व हितबद्ध पक्षों द्वारा रखे गए तर्कों को, जिन्हें अधिसूचित प्रारंभिक जांच परिणाम में शामिल किया गया है, यहां संक्षिप्तता के प्रयोजन से नहीं दोहराया गया है । तथापि, हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर प्रारंभिक जांच परिणाम में और/या इन जांच परिणामों में समुचित रूप से विचार किया गया है ।

1.7 नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचार किए गए आवश्यक तथ्यों/आधारों की जानकारी हितबद्ध पक्षों को दी गई और उनके बारे में प्राप्त टिप्पणियों पर इन निष्कर्षों में विधिवत् विचार किया गया है ।

1.8 इस अधिसूचना में ***** का आशय ऐसी सूचना से है जो हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई है या, प्राधिकारी के नियमों के तहत इसे गोपनीय माना है ।

(1)

2. निम्नलिखित संकेताक्षरों का इस्तेमाल किया गया है :

पीआईएमए	मैट कोक/कोक	मैटालर्जीकल कोक
चीन पी आर/चीन	पिंग आयरन मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन	
प्राधिकारी	निर्दिष्ट प्राधिकारी	
एमबीएफ	मिनी ब्लैस्ट फर्नेस	
आईसीए	इंडस्ट्रीज एंड कामर्स एसोसिएशन, धनबाद	
एलएएमसी	लो एश मैटालर्जीकल कोक	
पीएमआई	दी परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया इन जेनेवा	

ख. विचाराधीन उत्पाद

3. मौजूदा जांच के कार्य क्षेत्र के तहत उत्पाद मैटालर्जीकल कोक (जिसका उल्लेख मैट कोक के नाम से भी किया गया है) ।

4. मैटालर्जीकल कोक का उत्पादन आक्सीजन के अभाव में सामान्यतया कोयले को जलाए बिना लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च ताप पर मैटालर्जीकल (कोकिंग कोक) के विनाशक आस्वन द्वारा किया जाता है । उत्पादित मैटालर्जीकल कोक कुछ खनिज तथा अवशिष्ट बोल्टाइल सामग्री सहित मुख्य रूप से कार्बन है । मैट कोक का इस्तेमाल ऐसे उद्योगों में प्राइमरी ईंधन के रूप में किया जाता है जहां भट्टों अथवा फर्नेसिस में समान तथा उच्च तापमान की आवश्यकता होती है ।

5. मैटालर्जीकल कोक को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 27 (34 शीर्ष 27.04 के तहत) वर्गीकृत किया गया है । लेकिन यहां इस उत्पाद का दिया गया वर्गीकरण, विनिर्माण प्रक्रिया तथा उपयोग केवल संकेतात्मक हैं और विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र में बाध्यकारी नहीं हैं ।

6. मैटकोक का उपयोग विभिन्न उद्योगों जैसे पिंग आयरन, फाउंडरीज लौह मिश्र धातु, रसायन, एकीकृत इस्पात संयंत्रों तथा अन्य कार्यों में किया जाता है ।

7. आयातकों द्वारा इस बात के लिए तर्क दिया गया है कि जांच की शुरुआत के समय जो विचाराधीन उत्पाद था वह लो एश कोल से निर्मित "मैटालर्जीकल कोक" था लेकिन प्रारंभिक निष्कर्षों में वर्णित उत्पाद "मैटालर्जीकल कोक" है अतः प्राधिकारी ने अपने जांच के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है । तथापि, यह देखा जा सकता है कि जांच के सभी हिनबद्ध पक्षों ने इस बात से सहमति जताई है कि भारत में कथित रूप से पाटित चीन के कोक में एश की मात्रा कम है । अतः प्राधिकारी का विचार है कि जांच के क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ है और चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी मैटालर्जीकल कोक को मौजूदा जांच के क्षेत्र में कवर किया गया है ।

ग. समान वस्तु

8. याचिकाकर्ताओं के विचार : "समान वस्तु" के मामले में याचिकाकर्ता के अनुरोध निम्नानुसार है :

8.1 मैट कोक और उद्योग विशिष्टियों के घरेलू उपयोग निम्नानुसार हैं :—

(क) पिंग आयरन	एश की मात्रा 18.30%
(ख) फाउंडरीज	40% तक एश की मात्रा
(ग) फैब्रो एलॉयस	लो सल्फर, लो फास्फोरस
(घ) रसायन	38% तक एश
(ङ) अन्य	एश की किसी भी मात्रा का कोक

8.2 विनिर्मित मैटकोक प्रत्यक्ष रूप से निविष्टि के रूप में प्रयुक्त कोयले की किस्म पर निर्भर करता है । प्रयोक्ता उद्योग की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए निर्माण की प्रक्रिया में निविष्टि के रूप में कोयले का उपयोग करने से पूर्व इसे समुचित रूप से मिश्रित किया जाता है । भारतीय कोयला जिसमें एश की मात्रा अधिक होती है, उसमें सल्फर तथा फास्फोरस बहुत कम होता है । दूसरी ओर आयातित कोयले में बहुत कम एश की मात्रा होती है । मैटकोक का प्रयोग इस्पात मिलों से लेकर गैर-औद्योगिक उपयोग तथा घरेलू उपयोग के लिए ऊष्मा पैदा करने तक अनेक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है । अंतिम उपयोग तथा प्रत्येक उपयोक्ता की विशेष आवश्यकता पर निर्भर करते हुए मैट कोक का विशेष रूप से निर्माण किया जा सकता है और किया जाता है । यद्यपि भारतीय कोयले में एश की प्रतिशतता बहुत अधिक है, तथापि भारत में लो एश कोयलों की मात्रा कई बिलियन टन है । चारी समिति की रिपोर्ट में कुल कोयले की मात्रा 27 बिलियन टन से अधिक बताई गई है ।

8.3 उच्च एश कोक अथवा लो एश कोक के उत्पादन की प्रक्रिया एक जैसी है भले ही उसमें प्रयुक्त किए गए कोयले की किस्म कोई भी हो । भारतीय कोक के विनिर्माता के अपने मौजूदा संयंत्रों में बिना कोई संशोधन किए विशिष्ट उद्योगों के लिए आयातित कोयले को परिवर्तित कर सकते हैं । आयातित कोयले का प्रयोग करते हुए भारत में कोक के विनिर्माण के लिए तकनीकी या अन्यथा कोई भी प्रतिबंध नहीं है । अतः प्रथम दृष्टया यह कहना गलत तथा भ्रामक होगा कि चीन में उत्पादित कोक भारत में उत्पादित कोक के समान नहीं है । याचिकाकर्ता ने एनबीआर के मामले को उद्धृत किया है, जहां यह कहा गया था कि यद्यपि एन बी आर के समान ग्रेड भारत में निर्मित नहीं किए जा रहे हैं फिर भी उसके निर्माण में कोई प्रतिबंध नहीं है । भारतीय संयंत्र आयातित कोयले से कोक का निर्माण करने में बिल्कुल सक्षम हैं और वास्तव में समस्त भारत में अनेक संयंत्रों में इसका निर्माण किया जा रहा है ।

8.4 भारतीय कोक तथा चीनी कोक का प्रयोग परस्पर एक दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है । पिंग आयरन मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन का यह तर्क कि भारतीय कोक उनके संयंत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, वास्तव में सही नहीं है । यहां तक कि इस्पात मंत्रालय ने भी यह कहा है कि देशीय कोक के विनिर्माताओं को सृजित घरेलू मांग को उन नई मिनी ब्लैस्ट फर्नेसिस द्वारा पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो कि भारत में शुरू हो रही है । अतः भारतीय कच्चे माल का उपयोग भारत में पिंग आयरन के निर्माण में किया जाना है ।

8.5 टाटा कोर्प भारत में लगभग 90% पिंग आयरन संयंत्रों द्वारा प्रयुक्त प्रमुख तकनीक है । 1989 में टाटा कोर्प ने यह बताते हुए एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था कि एम बी एफ 30% तक की एश वाले मध्यम ग्रेड कोकिंग कोल का उपयोग कर सकता है और 30% एश वाले कोकिंग कोल से 40% से 45% के बीच एश मात्रा वाले कोक का उत्पादन होगा । इस दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि कोक का आयात किया जा सकता है या आयातित कोयले का इस्तेमाल करते हुए भारत में कोक का उत्पादन किया जा सकता है । बारी-बारी से इस अच्छी क्वालिटी के कोक को भारतीय स्रोत से प्राप्त कोक के साथ मिश्रित किया जा सकता है । तथापि, आयातित कोयला/कोक की लागत अधिक महंगी होगी तथा पिंग आयरन के उत्पादन की समग्र लागत में वृद्धि होगी । भारतीय अयस्क में 66.5% लोहा होता है । पर्याप्त "स्लैग और फ्लो" प्राप्त करने के लिए लगभग

18% एश की आवश्यकता होती है। चूंकि चीन कोक में भारतीय कोक से कम एश होती है, इसलिए भारतीय पिग आयरन विनिर्माताओं को विनिर्माण की प्रक्रियायें, "क्वार्टाइट" (एक प्रकार की एश) मिलाने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

8.6 भारतीय मैट कोक की विशेषताएं चीन के मैटकोक से बिल्कुल मिलती-जुलती हैं और इस प्रकार चीन से आयातित कोक भारतीय मैट कोक की "समान वस्तु" है जो "वाणिज्यिक और तकनीकी रूप" में प्रतिस्थापन योग्य है।

8.7 याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि भारतीय कोक के साथ चीनी कोक की तुलना करने वाले कारक निम्नलिखित हैं :

- * भौतिक विशेषताएं (आकार, रसायनिक संरचना तथा कच्ची सामग्री)।
- * विनिर्माण-प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी
- * कार्य तथा उपयोग
- * उत्पाद विशिष्टता
- * कीमत निर्धारण, वितरण तथा विपणन
- * प्रतिस्थापन योग्यता

8.8 फाउंडरीज से अनेक उपभोक्ता, पिग आयरन उत्पादक, रसायन उत्पादक, लौह मिश्रधातु के उत्पादक तथा अन्य औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक उपभोक्ता विगत में आई सी ए (इंडस्ट्री एंड कामर्स एसोसिएशन) के सदस्यों से मैट कोक प्राप्त करते रहे हैं। वे चीनी कोक की ओर मुड़ गए हैं क्योंकि इसे पाटित किया जा रहा है। पी आई एम ए का यह तर्क सही नहीं है कि "ब्लास्ट फर्नेस" में उच्च एश कोक का उपयोग करना तकनीकी तथा वाणिज्यिक दोनों दृष्टियों से उपयुक्त नहीं है। क्योंकि सेल के इस्पात संयंत्रों में कोक में एश 20% से 25% तक होती है। "समान वस्तु का यथार्थ तथा सही कारक यह है कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु में पाटित वस्तु से बिल्कुल मिलती-जुलती विशेषताएं हैं" अर्थात् क्या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु "तकनीकी और वाणिज्यिक" दृष्टि से प्रतिस्थापन योग्य रही है तथा/अथवा हो सकती है तथा इसके विपरीत क्या पाटित वस्तु "तकनीकी और वाणिज्यिक" रूप से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं को प्रतिस्थापित कर सकती है। यह तर्क कि पाटित वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु से अच्छी क्वालिटी की है, संगत नहीं है और इस बात को निर्धारित करने का आधार नहीं बन सकती है कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु समान वस्तु है। मैट कोक का बदलाव और/या प्रतिस्थापन पाटन का ही परिणाम है और इसे क्वालिटी के प्रयोजन के लिए नहीं अपितु कीमत प्रयोजन के लिए ही किया गया है।

9. निर्यातकों/आयातकों के विचार : निर्यातकों/आयातकों तथा अन्य पक्षों के विचार निम्नानुसार हैं :

9.1 भारत में मैट कोक की दो किस्मों का उत्पादन किया जाता है:

- (1) आयातित कोकिंग कोल से बना मैट कोक;
- (2) भारतीय कोकिंग कोल से बना मैट कोक।

9.2 भारतीय कोकिंग कोल से उत्पादित मैट कोक की तुलना आयातित कोकिंग कोल से निर्मित मैट कोक अथवा आयातित मैट कोक से नहीं की जा सकती। भारतीय कोकिंग कोल से निर्मित मैट कोक तथा आयातित कोकिंग कोल या आयातित मैट कोक में विभेदकारी कारक एश की मात्रा का होना है। भारतीय कोकिंग कोल से उत्पादित कोक को

ठीक-ठीक हाई एश मैट कोक (एच ए एम सी) की संज्ञा दी गई है जबकि आयातित कोकिंग कोल से उत्पादित कोक अथवा आयातित मैट कोक को लो एश मैट कोक के नाम से पुकारा जाता है। उक्त दोनों प्रकार कोकिंग की भौतिक तथा रासायनिक विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

भारतीय कोकिंग कोल से उत्पादित मैट कोक की क्वालिटी	आयातित मैट कोक/आयातित कोकिंग कोल से बने मैट कोक की क्वालिटी
नमी	5-15% >5%
एश	29-40% 12-14%
बोलाटाईल मैटर	2-4.5% <1.6%
निर्धारित कार्बन	52-65% 84-88%
सल्फर	1% अधिकतम >0.6% अधिकतम
फास्फोरस	0.30% 0.03%
एम 40	70-75% 80% न्यूनतम
एम 10	10-15% 8% अधिकतम
एश प्यूजन टैम्प	1240° सी अधिकतम 1350° सी न्यूनतम

9.3 इन भिन्न-भिन्न रासायनिक गुणों के कारण कोक की इन दोनों किस्मों की तुलना नहीं की जा सकती और इस प्रकार इसे समान वस्तु की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

9.4 याचिकाकर्ता इस बात का दावा कर रहा है कि हालांकि चीन में तथा भारत में प्रयुक्त कोयला समान नहीं है, लेकिन आयातित कोयले का उपयोग करते हुए भारत में कोक का उत्पादन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, यह तर्क इस प्रश्न के संदर्भ में संगत नहीं है कि क्या चीन से आयातित 15% तक एश की मात्रा वाली मैट कोक 27-40% एश की मात्रा वाले आई सी ए द्वारा उत्पादित मैट कोक के समान वस्तु है अथवा नहीं। प्रश्न यह नहीं है कि क्या आई सी ए का सदस्य आयातित कोयले के कम एश की मात्रा वाले मैट कोक का उत्पादन कर सकता है अपितु प्रश्न यह है कि क्या उच्च एश वाले भारतीय कोक से उनके द्वारा विनिर्मित कोक मिनी ब्लास्ट फर्नेस में लो एश कोक के प्रतिस्थापक के रूप में प्रयुक्त है। याचिकाकर्ता ने सितंबर, 1989 में टाटा कोर्प इंजीनियरिंग सर्विसेज लि. द्वारा प्रस्तुत किए गए एक दस्तावेज पर निर्भर किया है, जिसमें कहा गया है कि एम बी एफ 30% की एश मात्रा वाले मध्यम ग्रेड के कोकिंग कोल का इतना स्तेमाल कर सकता है। तथापि, आयातकों ने उत्तर में टाटा कोर्प इंजीनियरिंग से एक पत्र प्रस्तुत किया है कि एम बी एफ में उपयोग के लिए कोक में एश की मात्रा लगभग 12% तक सीमित होनी चाहिए। मैसर्स टाटा कोर्प द्वारा उच्च एश कोश की अनुपयुक्तता के लिए 1989 और 1998 में दी गई राय में भेद होने के मुख्य कारणों में एक कारण यह है कि टाटा कोर्प के पास भारत में मिनी ब्लास्ट फर्नेस को संचालित करने का अनुभव नहीं था और अब वे लगभग 13% एश की मात्रा वाले कोक की सिफारिश कर रहे हैं। टाटा कोर्प इंजीनियरिंग सर्विसेज लि. ने और आगे कहा है कि उन्होंने कोक दर, उत्पादकता स्लैग वोल्यूम्स आदि के बारे में तकनीकी मानदंडों से संचालित करने के लिए अपने मिनी ब्लास्ट फर्नेसिज तैयार किए हैं जहां तक प्रक्रिया तकनीकी तथा आर्थिक

रूप से व्यवहार्य होगी तथा उचित ग्रेड के गरम धातु का उत्पादन कर सकेगी। इन संयंत्रों को मूल रूप से लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी के लिए ही तैयार किया गया है जिसके लिए निम्नलिखित पैरामीटरों वाले एल ए एम सी का उपयोग करना आवश्यक है :

- *कोक एश लगभग 13% तक सीमित होनी चाहिए।
- *कोक का बोलाटाईल मैटर लगभग 1% होना चाहिए।
- *सी आर आई मूल्य 20-29% के बीच होना चाहिए।
- *सी एफ आर 58-64% के बीच होना चाहिए।
- *एम. 10 मूल्य अधिक से अधिक 8% होना चाहिए।
- *एम 40 मूल्य अधिक से अधिक 80% तक होना चाहिए।
- *कोक में सल्फर की मात्रा 0.4 से 0.5% होनी चाहिए।
- *फास्फोरस की मात्रा 0.035% से कम होनी चाहिए।

9.5 मिनी ब्लास्ट फर्नेस में उच्च एश वाले देशीय कोक की अत्यधिक खपत के कारण, गरम धातु की लागत अधिक होगी। टाटा कोर्क ने अब सिफारिश की है कि टाटा कोर्क मिनी ब्लास्ट फर्नेस में केवल एल ए एम सी ही इस्तेमाल किया जाए। टाटा कोर्क ने आगे कहा है कि तकनीकी दस्तावेज जो 1989 में टाटा कोर्क द्वारा प्रस्तुत किया गया था और जिसमें पिग आयरन के विनिर्माण के लिए उच्च एश कांटेंट वाले देशीय कोकिंग कोयले से बने देशीय उच्च एश कोक की उपयुक्तता की बात कही गई है, तब प्रस्तुत किया गया था जब टाटा कोर्क को भारत में मिनी ब्लास्ट फर्नेस का प्रचालन करने का अनुभव नहीं था। पहला टाटा कोर्क मिनी ब्लास्ट फर्नेस ब्राजीलियन लौह अयस्क के साथ ब्राजील में बहुत कम पूंजीगत लागत वाले बहुत छोटे आकार के मिनी ब्लास्ट फर्नेस को प्रचालन पर आधारित था, जहां अधिकतर मिनी ब्लास्ट फर्नेस का प्रचालन चारकोल से हो रहा था। उस समय उच्च एश वाले देशीय कोक वाले एम बी ए एफ के निष्पादन के कोई प्रचालन आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। अभी तक, टाटा कोर्क ने भारत में 15 मिनी ब्लास्ट फर्नेस डिजाइन किए हैं जिनमें से 13 प्रचालन में हैं। 1992 से 1998 के दौरान प्राप्त किए गए अनुभव से टाटा कोर्क मिनी ब्लास्ट फर्नेस के लिए केवल लो एश मैटालर्जिकल कोक का उपयोग करने की सिफारिश की गई है क्योंकि देशीय उच्च एश कोक के उपयोग से स्लैग वोल्यूम की मात्रा इस हद तक बढ़ जाएगी कि हर्थ के डिजाइन को बदलने की आवश्यकता पड़ेगी और फालतू स्लैग को निकालने के लिए एक स्लैग नोट्स की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। स्लैग की बड़ी मात्रा गरम धातु के ताप को कम करेगी जो कि आगे उपचार के लिए और क्वालिटी उत्पादों में बदलने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, उच्च एश वाले देशीय कोक के उपयोग से फर्नेस की उत्पादकता काफी कम हो जायेगी। (प्रत्येक 1% एश की मात्रा के बढ़ने से 2% उत्पादकता में कमी आयेगी) और यह इस स्तर तक कम हो जाएगी जिसकी तुलना भारत में विभिन्न टाटा कोर्क मिनी ब्लास्ट फर्नेस द्वारा प्राप्त किए जा रहे 1.5-2.0 टो/एम 3/डी के मौजूदा कार्य निष्पादन से किसी भी तरह से नहीं की जा सकती है। उत्पादकता का यह स्तर तब और भी अधिक बढ़ जाएगा जब इनका प्रचालन सिल्टर अथवा पैलेट्स की सहायता से किया जाए। उच्च एश कोक भी ब्लास्ट फर्नेस में बहुत अधिक कोक दर हो जाएगी [एश की मात्रा प्रत्येक 1% की वृद्धि के लिए कोक दर में 2% की वृद्धि] अधिक एश उपयोग से हॉट मैटल की क्वालिटी ताप, फास्फोरस मात्रा के

संदर्भ में घटिया हो जाएगी। निर्धारित कार्बन आधार पर देशीय उच्च एश कोक की लागत निर्धारित कार्बन आधार पर भी आयातित लो एश कोक की लागत के समानुपातिक नहीं है। अतः मिनी ब्लास्ट फर्नेस में उच्च एश वाले देशीय कोक की अत्यधिक खपत के कारण हॉट मैटल की लागत बहुत ही अधिक होगी। यह भी नोट करने की बात है कि समेकित इस्पात संयंत्र भी ब्लास्ट फर्नेस कोक का उत्पादन करने के लिए बहुत ही कम एश की मात्रा वाले आयातित कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं और सीधे तौर पर 100% देशीय उच्च एश कोक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उपर्युक्त सभी कारक मिनी ब्लास्ट फर्नेस प्रचालन के लिए पूरी तरह से अव्यवहार्य हैं जिसके फलस्वरूप भारत में मिनी ब्लास्ट फर्नेस बंद हो जाएंगे। वास्तविक अनुभव के आधार पर भारत में डिजाइन की गई टाटा कोर्क मिनी ब्लास्ट फर्नेस की पूंजीगत लागत पूर्व अनुमानित लागत से काफी अधिक है और स्लैग ट्रेनूलेशन सिस्टम, पावर प्लांट्स आदि जैसी अतिरिक्त विशेषताओं के कारण ब्राजील के मिनी ब्लास्ट फर्नेस की तुलना में भी यह पूंजीगत लागत अधिक है। अतः टाटा कोर्क ने केवल आयातित कोक प्रचालन के लिए ही मिनी ब्लास्ट फर्नेस का निर्माण किया।

9.6 क्वार्टजाइट को आयातित कम एश वाले कोक पर चलने वाली लघु ब्लास्ट भट्टी और इस्पात बनाने के लिए मूल ग्रेड के कम सिलिकन लौह का उत्पादन करने वाले कोक के बर्डन में नहीं जोड़ा जा रहा है। उन एम बी एफ ऑपरेटरों द्वारा क्वार्टजाइट की कम मात्रा जोड़ी जाती है जो ढलान शालाओं के लिए अत्यधिक उच्च सिलिकन (2.0-3%) पिग आयरन का उत्पादन कर रहे हैं। यह उल्लेख करना उचित होगा कि क्वार्टजाइट एश का एक रूप नहीं है। और कार्य के अनुसार क्वार्टजाइट को कोक की एश में निहित सिलिका द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। क्वार्टजाइट में वृद्धि करना उच्च सिलिकन फाउंड्री ग्रेड लौह का उत्पादन करने के लिए आवश्यक है क्योंकि क्वार्टजाइट सिलिका का एक शुद्ध रूप है (उपरोक्त 97% एस आइ ओ 2) जिसमें ब्लास्ट भट्टी के भीतर गरम धातु में सिलिकन का अंतरण करने की बेहतर प्रक्रिया निहित होती है। क्वार्टजाइट बोश स्लैग (मूल स्लैग) क्षारकता के रख रखाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्वार्टजाइट के सिलिका में सी ए ओ शामिल होता है जो बोश क्षेत्र में मूल स्लैग का निर्माण करता है। जब कि यदि उच्च एश वाले कोक का प्रयोग किया जाता है तो कोक एश का एस आई ओ 2 टायर क्षेत्र में रिलीज होती है। इस प्रकार यह बोश धातु को चिपचिपा बना देता है जो बर्डन के जरिए झोंका प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है। उच्च एश वाले कोक के प्रयोग से गरम धातु में सिलिकन का अंतरण आसानी से नहीं किया जा सकता है। जो दूसरी तरफ उत्पादकता कोक दर स्लैग की मात्रा इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके अलावा, उच्च एश वाला कोक अधिक एल्यूमिना निविष्टि पैदा करेगा जिससे स्लैग चिपचिपी बन जाएगी। इस प्रकार की स्थिति का ध्यान रखने के लिए क्वार्टजाइट के रूप में अधिक सिलिका बढ़ाने की जरूरत होती है। इससे बहाव की अधिक जरूरत पड़ती है और परिणामस्वरूप अधिक स्लैग की आवश्यकता पड़ती है जिसे स्लैग को पिघलाए रखने के लिए कोक की अधिक मात्रा जलाकर पूरी की जा सकती है। स्पष्टतः इसका प्रतिकूल कोक दर, स्लैग मात्रा और उत्पादकता पर संयोजित प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त के मद्देनजर यह सिफारिश की गई है कि टाटा कोर्क लघु ब्लास्ट भट्टी में कम एश वाले धातु कर्मीय कोक का इस्तेमाल किया जाए।

9.7 इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि एम बी एफ में प्रयोग के लिए उत्पादित उच्च एश तत्व वाले कोक एश वाले चीनी कोक द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आई सी ए के कुछ सदस्यों द्वारा उत्पादित उच्च एश वाला कोक चीन से आयातित कम एश

वाले कोक के समान उत्पाद नहीं है। इस प्रकार उच्च एश वाले कोक के उत्पादकों को वास्तविक क्षति का मूल्यांकन करने और स्थिति का निर्धारण करने के लिए शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

9.8 याचिकाकर्ता का यह तर्क कि विनिर्माण प्रक्रिया में पर्याप्त "स्लैग और फ्लो" प्राप्त करने की दृष्टि से लगभग 10% एश जरूरी है। चूंकि चीनी कोक में भारतीय कोक से कम एश होती है इसलिए पिग आयरन विनिर्माताओं को अपने विनिर्माण प्रक्रिया में क्वार्टजाइट (एक किस्म की एश) का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है। तथापि, आयातकों ने तर्क किया है कि याचिकाकर्ता की इस दलील को गलत तरीके से लिया गया है क्योंकि क्वार्टजाइट की वृद्धि स्लैग और फ्लो बढ़ाने के प्रयोजन से नहीं की जाती है बल्कि भारत में खनिज लौह अयस्क का प्रयोग करते हुए पिग आयरन का उत्पादन करते समय ब्लास्ट भट्टी स्लैग में उच्च एल्यूमिना तत्व की कमी करने के प्रयोजन से किया जाता है।

9.9 याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि 20% से अधिक एश तत्व वाले मेटकोक की खरीद उनसे की गयी है जो पिग आयरन फेरो एलाय, रसायन और अन्य उद्योगों का निर्माण करते हैं। आयातक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ऐसी खरीद के आर्डर अगस्त 1993 और सितम्बर, 1995 के बीच दिए गए थे न कि 1996-97 के दौरान। जांच अवधि के दौरान कम एश वाले कोक के लिए केवल वैलमैन का आर्डर था, लेकिन जो चीन से कथित रूप से डम्प किए गए कोक के समान उत्पाद है। याचिकाकर्ता ने खरीद आर्डरों का हवाला दिया है और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इन आर्डरों को निष्पादित किया था अथवा नहीं। कुछेक ऐसी खरीद परीक्षण आधार पर थी और चूंकि परीक्षण के दौरान अधिक एश तत्व वाले मेट कोक को अनुपयुक्त पाया गया था, इसलिए इसे छोड़ दिया गया था। कम एश वाले कोक के आपूर्तिकर्ता वांछित मात्रा में आपूर्ति करने में समर्थ नहीं है। पिग आयरन मैन्ग्रैफ़ेक्चर्स एसोसिएशन, फेरो एलाय प्रोड्यूसर्स, स्टील फर्नेस एसोसिएशन के अनेक सदस्यों ने आई सी ए के सदस्यों से कम एश वाली कोक को प्राप्त करने की व्यवहार्यता का पता लगाया था। उनके सारे प्रयास व्यर्थ गए थे क्योंकि आई सी ए का कोई भी कोक उत्पादक अपेक्षित गुणवत्ता और विनिर्देशन के कोक की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं था। इस प्रकार 20% अपशिष्ट वाले कोक की खरीद परीक्षण आधार पर की गई थी और चूंकि उन्होंने अपेक्षित परिणाम नहीं दिए इसलिए उन्हें कम एश तत्व वाले कोक के साथ मिश्रित किया गया था। तथापि, अधिक एश तत्व वाले कोक की आगे की खरीद पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। इसलिए याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि अधिक एश वाले कोक का प्रयोग एम बी एफ में किया जा सकता है, तकनीकी और वास्तविक रूप से गलत है। साथ ही इस प्रकार की खरीद जांच अवधि से बहुत पहले कर ली गई थी। अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए आई सी ए से थोड़ी मात्रा प्राप्त कर ली गई थी और वह भी अधिकांशतः कम एश वाले कोयले को उपलब्ध कराकर परिवर्तन के आधार पर थी।

9.10 हिंदुस्तान जिंक लि. ने कहा है कि उनके संयंत्र के लिए कोक एक आवश्यक एवं निहायत महत्वपूर्ण निविष्टि है। प्रचालन के लिए कोक की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है और अधिक एश वाले कोक के मामले के बढ़े हुए स्लैग उत्पादन के कारण यह प्रत्यक्षतः संयंत्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।

9.11 पिग आयरन के उत्पादन (ब्लास्ट भट्टी रूट) के बारे में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित निविष्टि उत्पादन मानकों में एक निविष्टि कम एश वाले धातुकर्मीया कोक (15% से कम एश वाला) प्रदर्शित की

गयी है। इस प्रकार 27.40% एश तत्व वाला मेटकोक आयातित मेटकोक के समान वस्तु नहीं है। भारतीय कोक उत्पादकों द्वारा उत्पादित अधिक एश तत्व वाला कोक उत्पादकता को बाधित करता है, उत्पादन लागत पर प्रभावी प्रभाव के साथ खपत दर में वृद्धि करता है। एम बी एफ प्रचालन की व्यवहार्यता इस परिकल्पना पर आधारित है कि उच्च गुणवत्ता वाला चीनी कोक सस्ती कीमतों पर उपलब्ध होगा।

9.12 जब याचिकाकर्ता इन दोनों उत्पादों अर्थात् कम एश वाले मेटकोक और अधिक एश वाले मेट कोक के बीच स्वयं अंतर बता रहे हैं तो निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकता है कि ये उत्पाद तकनीकी और वाणिज्य दोनों रूप से प्रतिस्पर्धीय हैं। जब कोई समान वस्तु हर प्रकार से जांच की जा रही वस्तु के समान है और वह मौजूद है तो वह समान वस्तु बन जाती है। भारत में मेटकोक के ऐसे विनिर्माता हैं जो आयातित कोयले से एल ए एम सी का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार एल ए एम सी हर प्रकार से एक जैसी वस्तु है और इसमें एक समान वस्तु बनती है। यदि इस प्रकार की वस्तु का भारत में निर्माण नहीं किया जा रहा होता तो प्राधिकारी इस बात पर विचार करता है कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु में जांच की जा रही वस्तु की विशेषताएं मौजूद हैं अथवा नहीं। इस प्रकार आई सी ए ए, द्वारा धनबाद द्वारा उत्पादित वस्तु को छोड़ दिया जाए।

9.13 याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित घरेलू कोक में सल्फर और फास्फोरस की अधिक मात्रा होती है जो ब्लास्ट भट्टी के कारगर प्रचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। चीन से आयातित मेटकोक में लगभग 0.035% फास्फोरस निहित है जबकि भारतीय कोयले से निर्मित कोक में लगभग 0.26% ही फास्फोरस होता है। भारतीय कोयले से निर्मित कोक में फास्फोरस और एश की अत्यधिक प्रतिशतता होने के कारण वहां विभिन्न औद्योगिक कार्यों के लिए इसका उपयोग करना उचित नहीं है जहां कम फास्फोरस तत्व वाले एल ए एम सी की जरूरत पड़ती है।

9.14 ब्लास्ट भट्टी प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों की राय में डब्ल्यू 3 और डब्ल्यू 4 ग्रेड के कोयले से उत्पादित कोक की जो आपूर्ति धनबाद क्षेत्र को की गई है, वह निर्माण में विपमता, घटियापन और असंगत गुणवत्ता के कारण न तो उपयुक्त है और न ही मितव्ययी है। कार्यानीकरण के कम तापमान के कारण इस प्रकार के कोयले से उत्पादित कोक में ब्लास्ट भट्टी में प्रयोग के लिए अपेक्षित भौतिक शक्ति नहीं होती है। देशी कोयले की घटिया गुणवत्ता के कारण सेल और आर. आई. एन. एल. ने ब्लास्ट भट्टी में अपेक्षित गुणवत्ता कोक उत्पादित करने के लिए कम एश वाले कोयले का बड़ी मात्रा में आयात किया।

9.15 अधिक एश वाले मेटकोक की तुलना में एल ए एम सी एक भिन्न वाणिज्यिक वस्तु है और इन दोनों वस्तुओं को बाजार में एक भिन्न वाणिज्य उत्पाद के रूप में माना और समझा जाता है। वाणिज्य मंत्रालय ने भी लाइसेंस जारी करते समय एश तत्व को (15% को शामिल न करते हुए) एश तत्व के रूप में इंगित किया है। वित्त मंत्रालय ने भी एश तथा फास्फोरस की प्रतिशतता के संदर्भ में उक्त अंतर को माना है। जिन उद्योगों में इनका प्रयोग किया जाता है, वहां दोनों प्रकार के कोक में इनका कार्य भिन्न-भिन्न है। अतः इन्हें समान वस्तु का नाम नहीं दिया सकता है। आई सी ए द्वारा उत्पादित कोक में 28—40% एश तत्व होता है और 0.26% अथवा इससे अधिक फास्फोरस होता है। इसलिए चीन से आयातित एल ए एम सी के स्थान पर उक्त कोक प्रयोग किया जाना संभव और व्यवहार्य नहीं है। भारत में स्वदेशी कोयले से उत्पादित कोक की गुणवत्ता

घटिया है और पिग आयरन को स्वदेशी कोक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनकी प्रौद्योगिकी में उक्त प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है, क्योंकि इसमें आयातित चीनी कोक की तुलना में 20—40% एश तत्व होता है जबकि चीनी कोक में एश तत्व 12-15% होता है। यदि पिग आयरन के उत्पादकों को इस कोक का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है तो इसके फलस्वरूप आयातित कम एश वाले कोक के मामले में 800 किग्रा. प्रति टन के मानक मानदंड के तुलना में पिग आयरन की खपत 1000 किग्रा. प्रति टन तक बढ़ जाएगी। इस प्रकार इसमें अतिरिक्त उत्पादन लागत सम्मिलित हो जाएगी और जिसे उद्योग बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसके अलावा स्वदेशी कोक के प्रयोग से ब्लास्ट भट्टी की उत्पादकता बाधित होगी और उनकी क्षमता कम हो जाएगी।

9.16 फेरो एलॉय इन्डस्ट्री ने कहा है कि फेरो एलॉय उद्योग के लिए जिस कोक की जरूरत होती है उसका भिन्न विनिर्देशन होता है। उन्हें 10-30 सी मी के आकार वाले कोक की ही जरूरत है जिसमें फास्फोरस की मात्रा 0.0166% से अधिक न हो। भारतीय कोयले से उत्पादित कोक में 0.15% फास्फोरस तत्व होता है और इसका उपयोग उत्पादित फेरो एलॉयस में बिलकुल नहीं किया जा सकता है। आई सी ए, धनबाद द्वारा उत्पादित कोक एश तत्व के कारण पिग आयरन के विनिर्माताओं के लिए न तो उपयुक्त है और अधिक एश और फास्फोरस तत्व के कारण न ही फेरो एलॉय उत्पादकों के लिए ही उपयुक्त है। स्थानीय फेरो एलॉय इन्डस्ट्री को कम राख, कम फास्फोरस, कम सल्फर मेटकोक की जरूरत पड़ती है। जिसमें पर्याप्त ठोस विनिर्देशन हो लेकिन यह घरेलू स्रोतों से उपलब्ध नहीं है। फेरो एलॉय का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए संयंत्र को बिना किसी बाधा तथा रूकावट के निरन्तर चलाए रखना पड़ता है। इसके लिए इस उद्योग को कम फास्फोरस कम राख, कम सल्फर मेटकोक का आयात चीन से करना पड़ता है क्योंकि घरेलू मेटकोक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

“समान वस्तु” के बारे में उठाए गए मुद्दों की जांच

10. नियम 2(घ) के अनुसार “समान वस्तु” की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है :—

“समान वस्तु” का अर्थ एक ऐसी वस्तु है जो जांच की जा रही वस्तु से हर प्रकार से एक रूप हो अथवा समान है जिसको भारत में डम्प किया जा रहा है अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु जो यद्यपि हर प्रकार से समान नहीं है लेकिन जांच की जा रही वस्तुओं से मिलते जुलते सभी गुण उसमें मौजूद हैं।

11. “समान वस्तु” के मुद्दे के बारे में निर्यातकों और आयातकों ने दावा किया है कि उद्योग एवं वाणिज्य एसोसिएशन द्वारा उत्पादित मेटकोक में राख के अत्यधिक तत्व हैं और इसलिए इसे चीन से आयातित मेटकोक के समान वस्तु नहीं कह सकते हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि अन्य तकनीकी विनिर्देशन भी कुछ सीमा तक भिन्न हैं कि प्रयोक्त उद्योग आई सी ए द्वारा उत्पादित मेटकोक के साथ चीनी कोक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।

12. इसके विपरीत, याचिकाकर्ताओं ने व्यापक अभ्यावेदन दिए हैं कि वे दोनों उत्पाद प्रतिस्थापित हैं और इसलिए परिभाषा की परिधि के भीतर समान वस्तुएं हैं। तथापि प्राधिकारी का कहना है कि याचिकाकर्ता उद्योग और आयातक तथा निर्यातक दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि मेटकोक की एक मुख्य विशेषता इसमें राख का तत्व होना है। भारतीय

कोयले से निर्मित कोक में राख तत्व की मात्रा अधिक है जो 20% से 40% तक है जबकि आयातित कोयले से निर्मित कोक स्वयं आयातित कोक में राख तत्व की कम मात्रा है। अतः दोनों पक्षों से यह स्वीकृत स्थिति है कि मेटकोक को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है अर्थात् भारतीय कोयले से उत्पादित कोक और आयातित कोक/आयातित कोयले से उत्पादित कोक वस्तुतः प्राधिकारी का मानना है कि पिमा ने अपने एक लिखित अनुरोध में भी उपरोक्त वर्गीकरण किया है।

13. प्राधिकारी का यह भी मानना है कि उपरोक्त दोनों प्रेणिषों की उत्पादन प्रक्रिया एक जैसी है और मेटकोक में राख की मात्रा इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कोयले के मिश्रण पर निर्भर करता है। कोयले की विभिन्न प्रेणिषों का मिश्रण परिष्कृत उत्पाद अर्थात् मेटकोक में वांछित मात्रा में राख तत्व प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्राधिकारी मानते हैं कि ऐसे कुछ दृष्टांत हैं जहां झौं का भट्टी में अधिक राख की मात्रा वाले मेटकोक का प्रयोग किया गया है यद्यपि उन्होंने कम राख वाले आयातित चीनी कोक के प्रयोग को मुख्यतः बरीयता दी है। घरेलू उद्योग द्वारा किया गया यह दावा कि पिग आयरन विनिर्माता विगत में विशेषकर 1992 के पूर्ण की अवधि में भारतीय कोयले से निर्मित कोक का प्रयोग करते थे, अविवादास्पद है।

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह सुझाव देने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि तकनीकी बनावट में जो अंतर है खासकर राख तत्व का उससे सभी प्रयोक्त उद्योगों के लिए तकनीकी रूप से अधिक राख वाले मेटकोक का प्रयोग करना असंभव हो जाता है। यह दावा कि प्रयोक्ता उद्योग ने जांच अवधि के दौरान कोई आर्डर नहीं दिए थे, इसका चीनी मेटकोक के साथ भारतीय मेटकोक की तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीयता के पहलू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तकनीकी विशेषज्ञों की राय भी पूर्ण रूप से यह नहीं व्यक्त करती है कि दो प्रेणिषों के मेटकोक का प्रतिस्थापना संभव नहीं है। विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई राय से यही स्पष्ट होता है कि अधिक राख तत्व वाले मेटकोक का प्रयोग पिग आयरन का उत्पादन करने से अधिक स्लैग का सृजन होगा और एम बी एफ की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पूर्णतः कम राख तत्व वाले चीनी कोक के प्रयोग पर निर्भर करता है। प्राधिकारी मानते हैं कि “समान वस्तु” का निर्धारण करने के लिए प्रतिस्थापनीयता अत्यधिक महत्वपूर्ण है न कि वास्तविक प्रतिस्थापना, प्रतिस्थापन क्षति की दृष्टि से एक संगत कारक हो सकता है।

15. कुछेक प्रयोक्त उद्योग समूह जैसे ड्यूक्टाइल आयरन पाइप्स, फेरो एलॉय के विनिर्माताओं ने सूचित किया है कि उनको जिस मेटकोक की जरूरत है उसमें अन्य भौतिक और रसायन विशेषताएं होनी चाहिए। उदाहरणस्वरूप ड्यूक्टाइल आयरन पाइप्स इन्डस्ट्री ने सूचित किया है कि उनको मेटकोक में फास्फोरस की मात्रा 0.035% से कम की चाहिए। यद्यपि यह प्रशंसनीय है कि कतिपय उद्योगों की विशेष अपेक्षाएं हो सकती हैं तथापि पाटनरोधी नियम विशिष्ट आखरी प्रयोक्ता के आधार पर विश्लेषण की अनुमति नहीं देते हैं जबकि विभिन्न किस्म के प्रयोक्ता उद्योगों में अधिक मात्रा में प्रतिस्थापन संभव है। अतः प्राधिकारी विशेष अपेक्षाओं वाले प्रयोक्ताओं का पृथक श्रेणीकरण करने की स्थिति में नहीं हैं।

16. उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी का मानना है कि यद्यपि

आई सी ए के सदस्यों द्वारा ऐसा मेटकोक का उत्पादन किया जाता है जो कुछ प्रयोगों के लिए कम राख वाले मेटकोक का प्रतिस्थापन नहीं है। ये उत्पादक कम राखवाले मेटकोक का निर्माण करने के काबिल हैं जो उनके द्वारा प्रयुक्त कोयले की गुणवत्ता और स्रोत पर निर्भर करेगा। तथापि यह भी देखा गया है कि आई सी ए के सदस्यों ने उत्तम भारतीय कोयले अथवा आयातित कोयले से कम राख तत्व वाले मेटकोक का अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं किया था।

17. अतः प्राधिकारी का मानना है कि यह कम राख वाले मेटकोक का ही उत्पादन है जो आयातित चीनी कोक के "समान वस्तु" है निर्यातकों/आयातकों का यह दावा कि अधिक राख तत्व वाले मेटकोक को समान वस्तु के रूप में न समझा जाय, इसमें काफी बल है और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार किया जाता है।

18. उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि विदेश व्यापार महानिदेशालय के निविष्ट उत्पादन संबंधी मानदंडों में पिग आयरन उत्पादन के लिए (झोंक भट्टी) जो एक निविष्ट प्रदर्शित की है वह कम राख वाला मेटकोक है (15% के कम तत्व वाला राख) अतः प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस तथ्य के होने के बावजूद कि आई सी ए 15% से कम अथवा उससे अधिक राख तत्व वाले मेटकोक का उत्पादन कर सकता है, प्राधिकार निर्यातकों/आयातकों को भी इस बात पर सहमत होने के लिए इच्छुक हैं कि 15% और इससे कम राख तत्व वाला मेटकोक ही भारत में इसके उत्पादन होने के बावजूद आयातित चीनी कोक के "समान वस्तु" है।

(ब) घरेलू उद्योग

19. याचिकाकर्ता के विचार

याचिकाकर्ता के विचार निम्नलिखित हैं :—

19.1 याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि निम्नलिखित मेटकोक के घरेलू विनिर्माता हैं :—

- टाटा आयरन एंड स्टील क. लि. (टिस्को)
- भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल)
- भारत कोकिंग कोल लि. (बी सी सी एल)
- राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर आई एन एल)
- दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि. (डी पी एल)
- वैलमैन इन कानडेसेन्ट लि. (वैलमैन)
- बी एल ए इंडस्ट्रीज लि., (बी एल ए)
- साउदर्न फ्यूलस लि. (साउदर्न)
- भारतीय उर्वरक निगम (एफ सी आई)
- सेसा गोवा (सेसा)
- उषा उद्योग (उषा)
- गुजरात एन आर ई (गुजरात एन आर ई)
- उद्योग और वाणिज्य ऐसोसिएशन (आई सी ए)

19.2 टिस्को, सेसा गोवा, उषा उद्योग, सेल को इस आधार पर सम्मिलित किया जाना चाहिए कि इन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत में प्रत्यक्ष अथवा संबंधित कंपनियों के जरिए मेटकोक का आयात किया है। इसके अलावा, आर आई एन एल, सेल से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह इस्पात मंत्रालय के प्रशासन के नियंत्रणाधीन है और इस प्रकार, यह

पाटनरोधी शुल्क संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार के अनुसार "संबद्ध" की परिभाषा के तहत सेल से संबद्ध है। इन दोनों पर प्रत्यक्ष रूप से तीसरे व्यक्ति अर्थात् इस्पात मंत्रालय का नियंत्रण रहता है, इस लिए जुड़ा हुआ है। यह अनुरोध है कि आर आई एन एल को सेल से जुड़े रहने के आधार पर छोड़ दिया जाय। आर आई एन एल ने पहले याचिकाकर्ता का समर्थन किया फिर समर्थन वापस ले लिया और तटस्थ हो गया और बाद में पाटनरोधी शुल्क लगाने का विरोध किया। ये सभी परिवर्तन इस्पात मंत्रालय, के दबाव के तहत किए गए हैं। यदि इस्पात मंत्रालय सेल और आर आई एन एल के लिए प्रशासनिक नियंत्रण हेतु आम हिस्सेदार न होता तो, आर आई एन एल अपना समर्थन वापस नहीं लेता और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का विरोध शुरू कर देता।

19.3 आर आई एन एल को घरेलू उद्योग से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि इसके उत्पादन की खपत अपनी उत्पादन प्रक्रिया के भीतर ही आंतरिक रूप से हो जाती है और नगण्य मात्रा ही बाजार में पहुंच पाती है। नियम 11 (3) के साथ पठित नियम 2(ख) के परन्तुक के तहत जो उत्पादक मेटकोक का उत्पादन और विपणन करते हैं और जो उत्पादन करते हैं और सक्रिय रूप से खपत करते हैं, वे दो प्रतियोगी बाजार का निर्माण करते हैं और इनमें से प्रत्येक को एक पृथक घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए। चूंकि आर आई एन एल मेटकोक का एक उपभोक्ता है और यह कैप्टिव उपभोग के लिए मेटकोक का उत्पादन करता है, इसलिए यह मध्यवर्ती उत्पादन है न कि उत्पादन शुल्क अथवा बिक्री कर अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए एक आखरी उत्पाद है। इसके अलावा, विश्व भर में कैप्टिव उपभोग को अलग रखना गैट प्रथा में एक आम बात है।

19.4 उपरोक्त बिन्दु पर विचार करते हुए बी एल ए इंडस्ट्रीज एवं आई सी ए जांच शुरूआत के समय 45% का निर्माण करते हैं और इस समय याचिका के लिए सुस्पष्ट समर्थन 67.81% है। घरेलू उद्योग के बारे में कानूनी अधिकारिता की अपेक्षाओं का पूर्ण रूप से पालन किया गया है।

19.5 आयातक/निर्यातक द्वारा बार-बार यह तर्क दिया जाना कि डब्ल्यू टी ओ ने वाणिज्य मंत्रालय को यह स्पष्ट कर दिया है कि आधार प्रयोजन के लिए केवल कैप्टिव उत्पादन को ही घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए, प्रमाणित नहीं किया गया है। "कैप्टिव उत्पादन" से संबंधित तकनीकी पहलु के बारे में किसी पृष्ठछाह पर "डब्ल्यू टी ओ" द्वारा किसी स्पष्टीकरण के जारी किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है जब तक कि सभी सदस्य देश इस प्रकार के स्पष्टीकरण पर अपनी सहमति नहीं दे देते हैं।

20. आयातकों के विचार : घरेलू उद्योग की स्थिति पर आयातकों के विचार निम्नलिखित हैं :—

20.1 प्राधिकारी ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर आई एन एल) द्वारा उत्पादित मेटकोक को हिसाब में नहीं लिया है, यद्यपि प्राधिकारी के ध्यान में डब्ल्यू टी ओ द्वारा जारी किया गया यह स्पष्टीकरण लाया गया है कि उत्पादन जो सर्वाधिक कैप्टिव खपत के लिए हो, को याचिकाकर्ता की स्थिति का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाना चाहिए। डब्ल्यू टी ओ के स्पष्टीकरण के संदर्भ में स्थिति के निर्धारण के प्रयोजन के लिए उत्पादन महत्वपूर्ण है न कि खपत क्षति निर्धारण के लिए जो उत्पादक मुख्य रूप से कैप्टिव खपत के लिए उत्पादन करते हैं उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का यह दावा कि विश्व भर में कैप्टिव उत्पादन को अलग रखने की गैट की प्रथा है, जो ठीक नहीं

है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि यूएस और यूरोप में प्रचलित प्रथा उनके विचार का समर्थन करती है और कैप्टिव खपत को क्षति विरलेपण से अलग रखा जाय।

20.2 याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि नियम 2(ख) और नियम 11 (3) के परन्तुक का अर्थ होगा कि मेटकोक दो प्रतियोगी बाजार है और इनमें से प्रत्येक को एक पृथक उद्योग के रूप में माना जाय और जो उत्पादन कैप्टिव खपत के लिए मेटकोक का उत्पादन कर रहे हैं उन्हें एक पृथक उद्योग के रूप में माना जाय। और जो उत्पादक बिक्री के लिए मेटकोक का उत्पादन कर रहे हैं, उन्हें दूसरा उद्योग माना जाय। यह दलील गलत है और किसी कानूनी स्थिति पर विचार किए बिना दी गई है, क्योंकि इस प्रकार के पृथकीकरण की स्थिति केवल वहां आ सकती है जहां किसी निश्चित क्षेत्र में डम्प किए गए आयातों की मात्रा अधिक रही है और उस क्षेत्र के उत्पादक उस क्षेत्र में अपने सम्पूर्ण उत्पादन को बेच देते हैं और उस क्षेत्र की मांग की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति किसी दूसरे क्षेत्र में स्थित उत्पादकों द्वारा नहीं की जाती है।

20.3 याचिकाकर्ता की यह दलील कि आर आई एन एल को इस आधार पर घरेलू उद्योग के दायरे से अलग कर दिया जाय कि वह इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, गलत है। सेल भी इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है और उसे विश्वेव्यापारिता आयरन एवं स्टील लि. (बी आई एस एल) के रूप में अलग रखा गया है जो सेल की एक सहायक कंपनी है और उसने मेटकोक का आयात किया है। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि चूंकि आर आई एन एल और सेल इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है इसलिए वे एक दूसरे से जुड़े हैं। अनुच्छेद VI में यह उल्लेख किया गया है कि उत्पादक आयातकों से संबद्ध होंगे यदि उनमें से एक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर नियंत्रण रखता है, अथवा दोनों पर किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रहता है अथवा वे दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखते हैं।

20.4 यह तर्क दिया गया है कि यह प्रश्न कि क्या आर आई एन एल प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बी आई एस एल पर नियंत्रण रखता है इसका उत्तर नकारात्मक में दिया जाना है क्योंकि आर आई एन एल तो कानूनी रूप से न ही प्रचालन रूप से बी आई एस एल पर प्रतिबंध लगाने अथवा निर्देश का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है। यह बात भी सही है। आर आई एन एल न तो कानूनी रूप से नहीं प्रचालन रूप से सेल पर और विलोमतः प्रतिबंध अथवा निर्देश देने की स्थिति में नहीं है इसलिए आर आई एन एल और बी आई एस एल संबद्ध नहीं हैं। जांच शुरूआत की तारीख को आर आई एन एल को कोई स्पष्ट समर्थन नहीं था। यदि आर आई एन एल प्रश्नावली उत्तर को याचिका के समर्थन में मान लिया जाता है तो, पाटनरोधी शुल्क लगाने के बारे में उनके द्वारा किए गए विरोध पर भी विचार किया जाय। याचिकाकर्ता ने शुरूआत की तारीख को आर आई एन एल का समर्थन किया है, इसलिए नियम 5 (3) (क) के परन्तुक के तहत 25% की अपेक्षा पूरी नहीं की है और स्थिति का निर्धारण जांच शुरूआत की तारीख को मौजूद समर्थन के संदर्भ में करना पड़ा।

20.5 याचिकाकर्ता का यह दावा कि घरेलू उद्योग की स्थिति-निर्धारण का चरण जांच प्रारम्भ करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय से पूर्व का होता है न कि उसके बाद का, सही नहीं है।

20.6 पी आई एम ए ने बताया कि सेल और टिस्को, जिनकी

सहायक कम्पनियों ने कोक का आयात किया था, के उत्पादन को अलग करने के बाद भी याचिकाकर्ता, मैसर्स बी एल ए इण्डस्ट्रीज और आई सी ए का उत्पादन मेटकोक के कुल उत्पादन का 18.1% बैठता है और इस प्रकार वह याचिका दायर करने की स्थिति में नहीं है।

20.7 जिन याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की थी, उन्होंने मेटकोक के अन्य उत्पादनकर्ताओं के नाम नहीं बताए। इस हद तक याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना अपर्याप्त, गलत और भ्रामक थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह खुद को इस बात से संतुष्ट करे कि जिन याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया है, वे याचिका दायर करने की स्थिति संबंधी वैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। ये शर्तें जांच शुरू करने के समय पूरी की जानी होती हैं। यदि कोई उत्पादनकर्ता, जिसने जांच की शुरूआत के समय याचिका का समर्थन नहीं किया था किन्तु, बाद में जांच शुरू होने के पश्चात् उनका समर्थन करता है, तो उसे जांच की शुरूआत को अभिप्रेष्ट करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता यदि मूल शुरूआत सुव्यवस्थित नहीं हो। चूंकि, याचिकाकर्ता ने आरआईएनएल या बीसीसीएल के उत्पाद के व्यौरे नहीं दिए थे इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को भ्रमित किया गया था। वेलमेन इन्वेस्टेमेंट लि. ने 24-4-98 को प्राधिकारी से निवेदन किया कि उसे क्षति हो रही है। परन्तु, पत्र में वे याचिका के किसी समर्थन का स्पष्ट रूप से संकेत नहीं कर रहे हैं। पीसीसीएल ने 22-5-98 को याचिका का स्पष्ट रूप से समर्थन किया। आरआईएनएल ने 28-11-97 को उत्तर दाखिल किया है परन्तु, उसमें स्पष्ट समर्थन का कोई संकेत नहीं है। उक्त पत्र 15-5-98 को वापस ले लिया गया है और अपने दि. 1-6-98 के पत्र द्वारा वे याचिका का विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार यद्यपि बीसीसीएल के उस समर्थन को ध्यान में रखा गया है, जिसे ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, आवेदनों के समर्थकों और विरोधियों के उत्पादों की प्रतिशतता 25.28% है, जो 50% की वैधानिक अपेक्षा से कम है। अतः याचिकाकर्ता न तो याचिका दायर करने की स्थिति में हैं और न ही इसे बनाए रखने की स्थिति में हैं और परिणामस्वरूप निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास जांच शुरू करने या इसे जारी रखने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

20.8 प्राधिकारी ने इस आधार पर घरेलू उद्योग के निर्धारण के लिए सेल के उत्पादन को अलग रखा है कि यह कारखानागत खपत के लिए कोक का उत्पादन कर रहा है और इसकी एक सहायक कम्पनी विश्वेव्यापारिता आयरन एण्ड स्टील कम्पनी आयातक है। नियम 2(ख) के अन्तर्गत ऐसे उत्पादक के उत्पादन को अलग रखने का कोई प्रावधान नहीं है, जो कारखानागत खपत के लिए उत्पादन करता है। अलग रखी गयी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो "स्वयं" विचाराधीन वस्तुओं के आयातकर्ता होते हैं। "स्वयं" अभिव्यक्ति का अत्यधिक महत्व है और इसके विचाराधीन वस्तु के उत्पादनकर्ताओं/विनिर्माताओं का उल्लेख होता है। नियम 2(ख) में कहीं भी इस आधार पर उत्पादन के आंकड़ों को अलग रखने का प्रावधान नहीं है कि घरेलू विनिर्माता स्वयं आयातकर्ता नहीं है किन्तु, इसकी एक सहायक कम्पनी आयातकर्ता है। इस तरह याचिकाकर्ता और इसके समर्थक का घरेलू उत्पादन 4.2% बैठता है और इसकी कोई स्थिति नहीं बनती है। यहां तक कि यदि सेल के आंकड़ों को अलग रखा गया है, जिसका हिस्सा 18% बैठता है और वह याचिका दायर करने की स्थिति में नहीं हैं।

20.9 कोक के पाटन का आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ताओं में से केवल दो ही उत्पादनकर्ता वीएलए इण्डस्ट्रीज लि. और गुजरात एनआरई कोक लि. ऐसे हैं जिनके पास आयातित कोकिंग कोयले से 12-15% एश

वाले कम एश कोक का उत्पादन करने की सुविधाएं हैं। तथापि, वे कच्चे लोहे/इस्पात उत्पादकों की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं।

20.10 राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल) ने 28-11-97 को मेटकोक पर शुल्क लगाने संबंधी सम्भावनाओं की जांच करने का अनुरोध किया है। लेकिन 15-5-98 को यह पत्र वापस ले लिया गया था। 1-6-98 को उन्होंने एक अन्य पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने पाटनरोधी शुल्क के उद्ग्रहण के लिए याचिका का विरोध किया है। उन्होंने बताया है कि आरआईएनएल में कोक का उत्पादन प्राथमिक तौर पर अपनी कारखानागत खपत के लिए किया जाता है और केवल देशी मात्रा की बिक्री ही घरेलू बाजार में की जाती है। उन्होंने यह भी बताया है कि 28-11-97 के उनके पत्र पर प्रबंधन से कोई स्वीकृति नहीं मिली थी और इसे अप्राधिकृत रूप से दिया गया था। उन्होंने यह भी बताया है कि पत्र की विषयवस्तु में आरआईएनएल का नीति संबंधी दृष्टिकोण उजागर नहीं होता है और वे ऐसा अप्राधिकृत पत्र भेजने के लिए आन्तरिक रूप से उचित कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि 28-11-97 के पत्र को वापस लिया हुआ और बातिल एवं शून्य समझा जाय। इस प्रकार आरआईएनएल ने याचिकाकर्ता का विरोध किया है।

घरेलू उद्योग और स्थिति संबंधी मुद्दों की जांच

21. नियम 2(ख) में "घरेलू उद्योग" शब्द को परिभाषित किया गया है। इसका पाठ निम्नानुसार है:—

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य उस मामले को छोड़कर, जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तुओं के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा उसके स्वयं आयातक होते हैं, ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का अंग नहीं समझा जाएगा, समान, वस्तु के निर्माण और उससे जुड़ी किसी गतिविधि में लगे समग्र घरेलू उत्पादकों अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का सबसे बड़ा अनुपात होता है।

22. बशर्ते कि नियम 11 के उप-नियम (3) में उल्लिखित अपवादात्मक परिस्थितियों में विचाराधीन वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग में उस स्थिति में दो अथवा उससे अधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों को सम्मिलित किया हुआ समझा जाएगा और ऐसे प्रत्येक बाजार के भीतर उत्पादकों को एक पृथक् उद्योग समझा जाएगा यदि:—

(i) ऐसे किसी बाजार के भीतर उक्त उत्पादक विचाराधीन वस्तु के अपने समस्त अथवा लगभग समूचे उत्पादन की बिक्री उक्त बाजार में करते हैं; और

(ii) उक्त बाजार में मांग उस क्षेत्र में किसी भी स्थान पर स्थित बाजार में उक्त वस्तु के उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की गई किसी मात्रा से अधिक नहीं है।

23. नियम 11 (3) का पाठ निम्नानुसार है:—

"निर्दिष्ट प्राधिकारी अपवादात्मक मामलों में उस स्थिति में भी क्षति की मौजूदगी के बारे में निष्कर्ष दे सकता है, जहां घरेलू उद्योग के पर्याप्त भाग को क्षति न पहुंची हो, यदि:—

(i) किसी अकेले बाजार में पाटित आयात इकट्ठे हो गए हों; और

(ii) पाटित वस्तु से ऐसे बाजार के भीतर उत्पादन के समस्त अथवा लगभग सभी उत्पादकों को क्षति पहुंच रही हो।"

24. ऊपर यथा उल्लिखित घरेलू उद्योग की परिभाषा से निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित होता है कि वह ऐसे घरेलू उत्पादकों के संदर्भ में "घरेलू उद्योग" शब्द के क्षेत्र विस्तार का मूल्यांकन करे, जो

"समान वस्तु" के विनिर्माण और उससे जुड़ी किसी गतिविधि में लगे हुए हैं। नियम 5(क) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि प्राधिकारी के लिए "समान वस्तु" के घरेलू उत्पादकों द्वारा आवेदन के समर्थन अथवा विरोध में व्यक्त की गई सीमा की जांच करना अपेक्षित होता है। उक्त परन्तु में आगे यह उल्लेख है कि उस स्थिति में कोई जांच शुरू नहीं की जाएगी यदि आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का घरेलू उद्योग द्वारा किए गए "समान वस्तु" के कुल उत्पादन का 25% से कम भाग बैठता है।

25. उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग का निर्धारण करने के लिए केवल "समान वस्तु" के उत्पादकों को ही ध्यान में रखना होता है। उपरोक्त पैरा 18 में "समान वस्तु" शब्द के क्षेत्र-विस्तार का पहले ही निर्धारण करते हुए प्राधिकारी के लिए 25% और 50% की प्रारम्भिक सीमा का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ केवल "समान वस्तु" अर्थात् 15% तक और उससे कम की ऐश अन्तर्वस्तु के मेटकोक के कुल उत्पादन पर विचार करना अपेक्षित होता है। अतः प्राधिकारी वास्तविक आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि कौन-कौन से उत्पादक भारत के घरेलू उद्योग के भाग हैं।

कंपनी का नाम	एश अन्तर्वस्तु	जांच -अवधि के दौरान उत्पादन (मी. टन. में.)
बी एल ए इंडस्ट्रीज	15% से कम	119337
इंडस्ट्रीज और वाणिज्य एसो.	15% से अधिक	543603
सदर्नप्यूल लि.	15% से कम	10623
भारत कुकिंग कोल लि.	15% से अधिक	215500
भारत कुकिंग को लि.	15% से अधिक	215500
वैलमैन इनकंडेसेंट इंडिया लि.	15% से कम	59425
गुजरात एनआरई कोक लि.	15% से कम	50860
दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि.	15% से अधिक	323701
फर्टिलाइजर कोर्प ऑफ इंडिया	15% से अधिक	102000
राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	15% से अधिक	1895273
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	आयातक से संबंधित	9957431
टाटा आयरन एंड स्टील को. लि.	आयातक से संबंधित	2018800
सेसा कैम्बला कोक को. लि.	आयातक से संबंधित	160547
ऊषा उद्योग	आयातक से संबंधित	77283

टिप्पणी उपर्युक्त "***" से वे कम्पनियां निर्दिष्ट की गई हैं जो मेट कोक का उत्पादन प्राथमिक रूप से कारखानागत खपत के लिए करती हैं।

26. उपर्युक्त तालिका से मैसर्स सेल, टिस्को, सैसा गोवा और उषा उद्योग मेटकोक के आयातक/आयातकों से संबद्ध प्रतीत होते हैं और इसलिए उन्हें "घरेलू उद्योग" शब्द के क्षेत्र विस्तार से अलग रखा जाना है। यह तर्क दिया गया है कि अलग रखने के प्रयोजनार्थ उत्पादकों को "स्वयं" आयातक होना चाहिए। प्राधिकारी का विचार है कि नियम 2 (ख) के अन्तर्गत "घरेलू उद्योग" की परिभाषा में यह पूर्णतया स्पष्ट है कि न केवल ऐसे उत्पादकों को अलग रखना है जो स्वयं आयात करते हैं बल्कि, उन उत्पादकों को भी अलग रखना है जो ऐसे आयातकों से संबंधित होते

हैं। अतः सेल, टिस्को, सेसा और ऊया उद्योग के बारे में प्रारम्भिक अधिसूचना में दिए गए प्राधिकारी के निष्कर्षों की पुष्टि होती है कि इन जांचों के प्रयोजनार्थ वे "घरेलू उद्योग" का भाग नहीं बनते हैं।

27. इस बात का भी पता चला है कि आई सी ए और आर आई एन एल के सदस्यगण उपर्युक्त 15% एश वाले मेटकोक के उत्पादनकर्ता हैं। इसलिए ये इकाइयां इन जांचों की प्रयोजनार्थ समान वस्तुओं की उत्पादनकर्ता नहीं हैं। अनिवार्य तथ्यों के प्रकटन के पश्चात् आयातकों द्वारा यह कहा गया है कि यह कहना सही नहीं होगा कि आर आई एन एल इस तथ्य की दृष्टि से कि 15% के उक्त आंकड़ों में कुछ उदारता की अनुमति दी जानी है, उपर्युक्त 15% एश तत्व से अधिक के कोक का उत्पादन कर रही है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आर आई एन एल के उत्पादन संबंधी आंकड़े तथा उनका औसत एश तत्व आर आई एन एल द्वारा स्वयं मासिक आधार पर उपलब्ध करवाया गया था। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट करते हैं कि आरआईएनएल ने स्वयं अपनी स्वीकृति से 15% तक या उससे कम का मेटकोक कभी उत्पादित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, प्रकटन विवरण में बताए गए तथ्यों पर स्वयं आर आई एन एल द्वारा विवाद नहीं किया गया है। इसलिए आयातक की उक्त दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है। प्राधिकारी के निष्कर्ष के लिए इस बात पर कोई पूर्वाग्रह नहीं है कि आर आई एन एल के उत्पादन जो कि कारखानागत खपत के लिए है, को न तो घरेलू उद्योग के निर्धारण के प्रयोजनार्थ और न ही स्थिति के प्रयोजनार्थ सम्मिलित किया जाना है।

28. प्राधिकारी समझते हैं कि बी सी सी एल, डी पी एल और एफ सी आई अधिक एश तत्व वाले कोक के उत्पादक हैं। प्राधिकारी के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि वे एल ए एम सी (15% एश तत्व तक) का उत्पादन करते हैं जो कि इस मामले में समान-वस्तु है। इस प्रकार प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि बी सी सी एल, डी पी एल और एफ सी आई घरेलू उद्योग का भाग नहीं बनते हैं।

29. प्राधिकारकर्ताओं का यह तर्क कि आर आई एन एल और सेल को उतना ही संबद्ध माना जाना चाहिए जितना कि उन्हें इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में माना जाता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। आवश्यक पूछताछ करने के बाद प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि ये दोनों कम्पनियां स्वतंत्र निदेशक मण्डलों द्वारा संचालित की जाती हैं और इस्पात मंत्रालय ने खासकर मेटकोक के मामले में, किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा है।

30. उन उत्पादनकर्ताओं की अन्तिम स्थिति जिन्हें "घरेलू उद्योग" के एक भाग के रूप में माना जा रहा है, इस प्रकार है :

बी एल ए	119337 एम टी
सदर्न फ्यूल्स	10623 एम टी
वैलमेन	59425 एम टी
गुजरात एनआरई	50860 एम टी
योग	240245 एम टी

31. इस आशय का एक मुद्दा उठाया गया है कि कारखानागत खपत के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किये गये उत्पादन को भी कुल घरेलू उत्पादन का एक भाग बनना चाहिए क्योंकि, भारतीय कानून के अन्तर्गत इसे अलग रखने का कोई प्रावधान नहीं है। इस संदर्भ में निर्यातकों के विद्वान काउंसिल ने भी बार-बार इस बात का उल्लेख किया है कि डब्ल्यू

टी ओ ने मंत्रालय को यह संकेत करते हुए परामर्श दिया है कि "घरेलू उद्योग" के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कारखानागत खपत के लिए किए गए उत्पादन की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

32. इस प्रकटन के बाद अनेक आयातकों ने स्थिति के प्रयोजनार्थ कारखानागत खपत के आशय से किए गए उत्पादन को शामिल करने के मुद्दे के संबंध में जिनेवा (पी एम आई) में भारत के स्थायी मिशन से प्राप्त पत्र की एक प्रति संलग्न की है। परन्तु, किसी भी पार्टी ने पी एम आई से मांगे गए स्पष्टीकरण के संबंध में 10 जून, 1998 के पत्र की प्रतियां नहीं लगाई हैं। दिनांक 20-7-98 का उक्त पत्र, जो प्राधिकारी को 10-8-98 (प्रकटन विवरण का प्रत्युत्तर देने की अन्तिम तिथि) को प्रस्तुत किया गया था, उसका पाठ इस प्रकार है :

"भारतीय स्थायी मिशन

जिनेवा

सं. जीईअन/पी एम आई/डब्ल्यू टी ओ/ ...

20 जुलाई, 1998

सेवा में,

श्री आर. पार्थसारथी,
पूर्व आईए एण्डएएस,
लक्ष्मी कुमार एण्ड श्री धरन
फैक्स : 00-91-11-6197578

प्रेषक : एस प्रियदर्शी, काउंसिलर

कृपया पाटनरोधी उपायों के कार्यान्वयन पर करार के कतिपय उपबंधों के संबंध में राजदूत नारायणन को भेजे अपने दिनांक 10 जून, 1998 के पत्र को देखें।

राजदूत की इच्छानुसार मैंने डब्ल्यूटीओ सचिवालय में संबद्ध अधिकारी से चर्चा की थी जिसने स्पष्ट किया है कि हालांकि, करार में यह बात स्पष्ट नहीं है कि क्या घरेलू उत्पादनकर्ताओं, जो केवल कारखानागत खपत के लिए ही उत्पादन करते हैं, को कोई भी पाटनरोधी उपाय लागू करते समय सम्मिलित किया जाना चाहिए अथवा नहीं, तथापि, यह माना जाता रहा है कि अन्तिम प्रयोग का ध्यान रखे बिना समूचे उत्पादन को समर्थन की किसी विशिष्ट प्रतिशतता की गणना करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

सादर,

हस्ताक्षरित,

(एस. प्रियदर्शी काउंसिलर)

33. प्राधिकारी ने पीएमआई में राजदूत से ऐसे स्पष्टीकरण के स्रोत और इस मुद्दे पर कानूनी आधार, आर्थिक युक्ति संगतता और विधि-शास्त्र के बारे में भी ब्यौरे और कतिपय स्पष्टीकरण मांगे हैं। पीएमआई से दिनांक 11-3-98 का उत्तर मिला था और उक्त पत्र के संगत उद्धरण पुनः नीचे प्रस्तुत किए गए हैं :

"यह आपके कल के फैक्स सन्देश के जवाब में हैं।"

मैं यह समझता हूँ कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.4 में उपबंधित 25% मानदण्ड का निर्धारण करने में कारखानागत खपत के आशय से किए गए उत्पादन को सम्मिलित करने या न करने का प्रश्न उक्त पाटनरोधी करार में एक "ग्रे एरिया" है। डब्ल्यू टी ओ सचिवालय के एक अधिकारी और एक प्रमुख विधि-व्यावसायिक, जिनसे मैंने आज इस मामले में सलाह-मशविरा किया था, ने इस बात की पुष्टि की है कि करार के इस

पहलू पर पाटनरोधी करार बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। मैं यह भी समझता हूँ कि यह मुद्दा किसी भी समय पुराने गैट या वर्तमान डब्ल्यूटीओ के अन्तर्गत विवाद निपटान प्रक्रिया में विचारणीय विषय नहीं रहा है। इसलिए यह स्पष्ट है कि यह मुद्दा व्यापक है और अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकारी करार के उक्त उपबंधों का अपने ढंग से अर्थनिरूपण करने के हकदार हैं, जब तक कि ऐसा अर्थनिरूपण औचित्य, सुसंगतता और सद्भावना का मापदण्ड पूरा न करे।

डब्ल्यूटीओ मिशन में काउंसेलर द्वारा भेजे गए संदेश के संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि स्पष्टीकरण के लिए किए गए विशिष्ट अनुरोध के प्रत्युत्तर में उन्होंने उन अनौपचारिक परामर्शों के आधार पर यह संदेश भेजा है, जो उन्होंने डब्ल्यूटीओ के एक विशिष्ट अधिकारी के साथ किए हैं। कल्पना के किसी भी आयाम द्वारा यह दलील नहीं दी जा सकती है कि डब्ल्यूटीओ मिशन के काउंसेलर का यह संदेश एक प्रमाणिक अर्थ निरूपण है और यह बाध्यकारी है। वास्तव में, मैं समझता हूँ कि श्री प्रियदर्शी ने स्पष्ट तौर पर यह संकेत दिया है कि डब्ल्यूटीओ सचिवालय ने यह माना कि करार में स्वयं यह बात स्पष्ट नहीं है कि क्या ऐसे घरेलू उत्पादकों, जो केवल कारखानागत खपत के लिए उत्पादन करते हैं, को किसी पाटनरोधी उपाय को लागू करते समय सम्मिलित किया जाना चाहिए या नहीं। "उपयुक्त" को देखते हुए यह स्पष्ट है कि डब्ल्यूटीओ सचिवालय के एक अधिकारी के अनुमान को सूचित करते हुए उक्त काउंसेलर (डब्ल्यूटीओ) का संदेश और वह भी इस प्रस्तावना के साथ कि करार में स्पष्टता का अभाव है, बाध्यकारी प्रभाव नहीं रख सकता।

अतः आप इस आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं कि पाटनरोधी उपाय लागू करते समय कारखानागत खपत को शामिल करने अथवा उसे अलग रखने के प्रश्न पर कोई बाध्यकारी निर्णय/विधिशास्त्र नहीं है।"

34. इस तथ्य के होते हुए भी कि प्राधिकारी पर डब्ल्यूटीओ सचिवालय की व्यक्तिगत या आधिकारिक राय बाध्यकारी नहीं है, उक्त राय देने के लिए कोई कानूनी या आर्थिक विश्लेषण, तर्क या निर्णीतबाद उद्धृत नहीं किए गए हैं। इस सम्बन्ध में उक्त स्पष्टीकरण को न तो कोई महत्व दिया जा सकता है और न ही उसका कोई विश्वासोत्पादक मूल्य ही होना कहा जा सकता है। हालांकि, कारखानागत खपत के मुद्दे से घरेलू उद्योग के निर्धारण या "समान वस्तु" शब्द के क्षेत्र-विस्तार की दृष्टि से याचिकाकर्ताओं की स्थिति के प्रयोजनार्थ किसी परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सकता है तथापि, प्राधिकारी मानते हैं कि इसकी सुसंगत क्रियाविधि के अनुसार कारखानागत खपत के लिए किए गए उत्पादन को "घरेलू उद्योग" की परिभाषा अथवा याचिकाकर्ताओं की स्थिति के प्रयोजनार्थ सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी का विचार है कि कारखानागत खपत का माल वहां पर बाजार में प्रवेश नहीं करता जहां व्यापारिक माल कथित पाटित माल के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि किसी भी स्थिति में इस मामले में 15% तक कि एश वाले कोक का ऐसा कोई उत्पादनकर्ता नहीं है, जो "घरेलू उद्योग" की सम्भावना के अन्तर्गत अन्यथा शामिल करने के योग्य हो। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि निर्यातकों के काउंसेलर द्वारा उद्धृत यूरोपीय आयोग और अमरीकी अधिकारियों का यह अभिमत कि कारखानागत खपत के लिए माल को अलग नहीं रखा जाता है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।

35. प्राधिकारी मानते हैं कि "घरेलू उद्योग" द्वारा जांच अवधि के दौरान 15% तक के एश तत्व वाले मेटकोक (समान वस्तु) का कुल उत्पादन 240245 मी० टन है। याचिका का उन सभी उत्पादनकर्ताओं ने

समर्थन किया है जिनका हिस्सा "घरेलू उद्योग" द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन का 100 प्रतिशत बैठता है। इसलिए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि याचिका को अपेक्षित समर्थन प्राप्त है जैसाकि कानून में निहित है।

36. एक मुद्दा यह उठाया गया है कि प्राधिकारी को जांच प्रारम्भ करने की तिथि को स्थिति निर्धारित करनी होती है तथा याचिका के किसी भी अनुवर्ती समर्थन को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। प्राधिकारी मानते हैं कि हालांकि, जांच की शुरुआत के समय किसी याचिका के समर्थन अथवा विरोध का निर्धारण करना अपेक्षित है फिर भी ऐसा निर्धारण उसी समय उपलब्ध साक्ष्य की जांच पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त जांच शुरू होने के बाद ही प्राधिकारी को "घरेलू उद्योग" और "समान वस्तु" के क्षेत्र विस्तार के मुद्दों पर विचार करना चाहिए और वह इन पर विचार कर सकता है। उन व्यौरों की क्या कोई उत्पादनकर्ता कथित पाटित माल का आयातकर्ता भी है की जांच विधि की उचित क्रिया विधि का पालन करते हुए उपयुक्त ढंग से जांच शुरू करने के बाद ही की जा सकती है। इसी तरह "समान वस्तु" शब्द के सुस्पष्ट क्षेत्र विस्तार का भी प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जांच करने का अवसर प्राप्त करने और सभी हितबद्ध पार्टियों को अवसर दिए जाने के बाद ही निर्धारण किया जा सकता है। विस्तृत सूचना और गहन विश्लेषण के आधार पर "घरेलू उद्योग" और "समान वस्तु" शब्द का क्षेत्र-विस्तार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसका सीधा सम्बन्ध स्थिति संबंधी मुद्दे से होता है। इसलिए स्वयं जांच-पूर्व चरण में किसी भी पहलू का अन्तिम निर्धारण न तो भारतीय कानून या गैट करार में निहित है और न ही ऐसी क्रियाविधि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सुसंगत होगी।

37. उपरोक्त विचार-विमर्शों को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू करने के समय प्राधिकारी की पास उपलब्ध सूचना के आधार पर वह यह भी अवधारित करता है कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने की स्थिति में थे। जैसाकि पहले कहा गया है, "समान वस्तु" के क्षेत्र विस्तार की पुनर्परिभाषा करने और आयातकों/निर्यातकों के इस तर्क को मानने के बाद कि हाई एंश कन्टेंट मेटकोक के उत्पादनकर्ताओं को अलग रखा जाना चाहिए, प्राधिकारी यह अवधारित करते हैं कि याचिका पर "समान वस्तु" के उत्पादन का 100% हिस्सा रखने वाले उत्पादकों का समर्थन प्राप्त है। जांच शुरुआत की तिथि को मैं बीएलए इण्डस्ट्रीज लि० और आईसीए द्वारा याचिक दायर की गई थी और उसका सदर्न फ्यूल्स लि० द्वारा समर्थन किया गया था। उत्पादनकर्ताओं का सामूहिक रूप से "घरेलू उद्योग" के 25% से अधिक का हिस्सा बनता है जो उस समय धातुकर्मीय कोक के उत्पादनकर्ता के रूप में जाने जाते थे। अतः याचिकाकर्ता जांच-प्रारम्भ करने की तिथि को भारतीय "घरेलू उद्योग" की ओर से याचिका दायर करने की स्थिति में थे।

च. सामान्य मूल्य

यह खण्ड निम्नलिखित में विभाजित किया गया है:—

- * निर्यातकों के दावे
- * याचिकाकर्ताओं के विचार
- * निर्यातकों/आयातकों के विचार
- * प्राधिकारी द्वारा जांच

निर्यातकों के दावे

38. शांक्सी कोल इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट ग्रुप कारपोरेशन

उक्त निर्यातक ने प्रारंभिक निष्कर्षों की अधिसूचना जारी होने के बाद कोई अन्य सूचना प्रस्तुत नहीं की है। अतः प्रारंभिक निष्कर्षों में उपरोक्त निर्यातक का दावा वही है तथा इसमें कोई परिवर्तन नहीं है।

39. निगजिया जियावेग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन

उक्त निर्यातक ने प्रारंभिक निष्कर्षों की अधिसूचना जारी होने के बाद कोई अन्य सूचना प्रस्तुत नहीं की है। अतः प्रारंभिक निष्कर्षों में उपरोक्त निर्यातक का दावा वही है तथा इसमें कोई परिवर्तन नहीं है।

40. चाइना नेशनल इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट/हेबई कम्पनी

40.1 यह कहा गया है कि उनकी निर्यात बिक्री व्यापारियों के लिए है। उनकी घरेलू बिक्री उन विनिर्माताओं की है जिन्होंने भारत को निर्यात कार्गो की आपूर्ति की है। उक्त विनिर्माता शिजिआझांग है। यह भी कहा गया है कि वे इस श्रेणी के कोक की बिक्री किसी अन्य देश को नहीं कर रहे हैं।

40.2 छूट (बीजक में किए गए गुणवत्ता विचलन के लिए जुर्माना) कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा तथा हैंडलिंग प्रभारों के कारण भारत के लिए निर्यात कीमत में कीमत-समायोजन का दावा किया गया है। निर्यातक ने एजेंसी करार प्रस्तुत किया है जिसमें दावा किए गए अनुसार कमीशन का प्रतिशत दर्शाया गया है। अंतर्देशीय भाड़े के समर्थन में निर्यातक ने रेल से बीजक तथा रेलवे ब्यूरो ऑफ बीजिंग, शिजिआझांग स्टेशन से दिनांक 9-7-1998 का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि अप्रैल, 1996 से अप्रैल, 1997 की अवधि के दौरान भाड़ा दर में परिवर्तन नहीं हुआ है। हैंडलिंग प्रभारों के संबंध में निर्यातक ने हैंडलिंग एजेंट द्वारा जारी किए गए बीजक को प्रस्तुत किया है। निर्यातक ने हैंडलिंग प्रभारों के संबंध में अपना दावा xxx से बदल कर दिया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू कीमत xxx दर्शाया गया है। निर्यातक ने कारखाना कीमत निकालने के लिए किसी कटौती का दावा नहीं किया है क्योंकि उन्होंने यह कहा है कि घरेलू ग्राहक फैक्ट्री के गेट पर डिलीवरी लेते हैं तथा अन्य सभी खर्च उठाते हैं और सूची कीमत केवल आधार कीमत होती है, कर तथा अन्य व्यय इसके अतिरिक्त होते हैं।

40.3 दावा की गयी घरेलू कीमत के समर्थन में, निर्यातक ने संगत अवधि के लिए बिक्री लेजर की प्रति प्रस्तुत की है। निर्यातक ने प्रचलित घरेलू कीमत दर्शाने के लिए जुलाई, 1996, अक्टूबर 1996 तथा नवम्बर 1996, फरवरी 1997 के बीजक प्रस्तुत किए हैं। यह दावा करते हुए उत्पादक ने लागत विवरण भी प्रस्तुत किया है कि घरेलू बिक्रियां लाभप्रद थीं जिन्हें सी पी ए द्वारा यह दर्शाते हुए प्रमाणित किया गया है कि संबंधित आकार के कोक का उत्पादन और बिक्रियां लाभदायक हैं।

41. चाइना नेशनल कोल इंडस्ट्री

41.1 निर्यातक ने कहा है कि कोई घरेलू बिक्री नहीं हुई है तथा वह मेटकोक की इस श्रेणी का किसी अन्य देश को निर्यात नहीं कर रहा है। यह भी अंगित किया गया है कि कम्पनी अपने ग्राहकों को कोई अन्य वित्तीय सहायता नहीं प्रदान कर रही है तथा भुगतान सामान्यतः एक अप्रत्यादेय/शाख पत्र के द्वारा स्थल भुगतान की शर्त पर होता है। अतः कोई ब्याज लागत नहीं आती है।

41.2 कम्पनी ने आगे यह कहा है कि इसने जांच अवधि के दौरान भारत को चार परेषणों का निर्यात किया है। चार परेषणों में से, तीन निर्यात परेषण मै० कम्पनी अ से खरीदे गए थे तथा एक मै० कम्पनी ब से खरीदा गया था। कम्पनी अ के माध्यम से निर्यात

42. चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कारपोरेशन

42.1 निर्यातक ने कहा है कि उसने भारत को फरवरी 1997 में मेटकोक के केवल एक परेषण का निर्यात किया था। मै० शाक्सी लिनफेक्स

पिंग यांग कोकरी फैक्ट्री इसकी उत्पादक है। निर्यातक ने दावा किया है कि उसने परेषण का सी एंड एफ आधार पर निर्यात किया है तथा भारत के लिए निर्यात कीमत में छूट/कमीशन, अंतर्देशीय भाड़े, भण्डारण, लोडिंग लागत, एस जी एस जांच प्रभार तथा समुद्रीय भाड़े के कारण कीमत समायोजन का दावा किया है। उसने कमीशन का दावा करने के लिए करार की प्रति प्रस्तुत की है। उसने दावा किए गए अंतर्देशीय भाड़े को दर्शाते हुए एक बीजक प्रस्तुत किया है। निर्यातक ने दावा किये गए समुद्री भाड़े को दर्शाते हुए करार की प्रति प्रस्तुत की है। भण्डारण तथा लोडिंग लागत के कारण उक्त दावे को दर्शाते हुए साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं। दावा की गयी कारखानागत निर्यात कीमत xxx यू एस डालर की है। घरेलू कीमत के संबंध में, निर्यातक ने घरेलू कीमत को दर्शाते हुए फरवरी 1997 का एक बीजक प्रस्तुत किया है। निर्यातक ने आगे यह कहा है कि वह घरेलू बिक्री का ब्यौरा उपलब्ध करवाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उत्पादन का रिकार्ड जांच के लिए सरकार द्वारा ले लिया गया है। निर्यातक ने इस संबंध में शाक्सी पीपल उच्च न्यायालय से एक पत्र प्रस्तुत किया है इस बीजक के आधार पर, दावा की गयी घरेलू कीमत xxx की है। अतः निर्यातक ने न्यूनतम डम्पिंग मार्जिन का दावा किया है। यह भी दावा किया गया है कि उत्पादन की लागत xxx है तथा बिक्री इस लागत तक अधिक कीमत पर है। दावा की गयी लागत के समर्थन में निर्यातक ने उत्पादन लागत दर्शाते हुए सी पी ए से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

43. चाइना नेशनल मिनरल्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन (मिनमेटल ग्रुप)

43.1 निर्यातक ने दावा किया है कि जेग यांग कोकिंग प्लांट कोक का उत्पादन करता है तथा अपने समूचे उत्पादन की मिनमेटल को आपूर्ति करता है जिसका तत्पश्चात् भारत अथवा अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। यह भी दावा किया गया है कि उत्पादनकर्ता ने चीन के अंदर संबंध वस्तु की बिक्री नहीं की थी तथा अन्य देशों को निर्यात उस उत्पादनकर्ता द्वारा नहीं किया गया था जिसका उत्पादन के संबंध में, निर्यातक ने अंतर्देशीय भाड़े तथा लोडिंग प्रभार पर अपना दावा परिवर्तित कर दिया है। कम्पनी ब के माध्यम से निर्यात के संबंध में किसी कटौती का दावा नहीं किया गया है क्योंकि पत्तन को कोकरी के बैकयार्ड में स्थित बताया गया है।

41.3 निर्यात ने अंतर्देशीय भाड़े तथा लोडिंग प्रभारों के संबंध में बीजक प्रस्तुत किए हैं। अतः निर्यातों के संबंध में कारखाना कीमत निम्नानुसार है :—

(यू एस डालर में)	कम्पनी अ से निर्यात	कम्पनी ब से निर्यात
कीमत	xxx	xxx
अंतर्देशीय भाड़ा	xxx	xxx
लोडिंग लागत	xxx	xxx

41.4 निर्यातक ने कम्पनी अ के संबंध में घरेलू बीजक प्रस्तुत किया है। निर्यातक ने अप्रैल, 1996 दिसम्बर, 1996 तथा मार्च, 1997 के महीने के बीजक प्रस्तुत किए हैं तथा अन्य महीनों के लिए दिए गए कम समय के कारण बीजक उपलब्ध करवाने में असमर्थता जाहिर की है। निर्यातक ने लाभ तथा हानि का विवरण भी प्रस्तुत किया है। यह देखा गया है कि वे हमदाद पा रहे हैं तथा घाटा भी उठा रहे हैं। तथापि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या निर्यातक ने हमदाद के प्रभावों को समायोजित किया है अथवा नहीं। तथापि, निर्यातक ने यह कहा है कि कोक ओवन गैस सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेची जाती है तथा चीन सरकार इस संबंध में हुए

घाटे पर इमदाद देती है। इस इमदाद का मेटकोक से कोई लेना-देना नहीं है। निर्यातक ने दावा किया है कि उसने कोक की सभी श्रेणियों में लाभ कमाया है। इसने कम्पनी अ की घरेलू कीमत होने का भी दावा किया है जिससे कोई पाटन होने की पुष्टि नहीं होती है। आगे यह भी दावा किया गया है कि कम्पनी ब के संबंध में घरेलू कीमत $\times\times\times$ की है और इसलिए कोई डम्पिंग नहीं हुई है। भारत को बेचा गया था। अतः निर्यातक ने अन्य देशों की निर्यात के ब्यौरे निकाल देने का प्रस्ताव किया है। निर्यातक ने आगे यह अनुरोध किया है कि घरेलू कीमत के रूप में अथवा अन्य देश की निर्यात कीमत के रूप में सामान्य मूल्य उपलब्ध नहीं है और इसलिए इसका उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारण किया जाए। निर्यातक ने भारत के लिए निर्यात कीमत पर अंतर्देशीय भाड़े, भण्डारण (भण्डारगृह) हैंडलिंग (भण्डारगृह से बर्थ तक लोडिंग) तथा एस जी एस जांच प्रभारों के कारण कीमत समायोजन का दावा किया है। निर्यातक ने यह भी दावा किया है कि बिक्री लागत से अधिक कीमत पर की गई है। उसने सी पी ए द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि लागत $\times\times\times$ है, वर्ष 1996 के लिए लागत गणना दर्शाते हुए एक शीट प्रस्तुत की है। यह दावा किया गया है कि उत्पादनकर्ता ने मिनमेटल को आर $\times\times\times$ पर सामान बेचा जिसने बाद में भारत को $\times\times\times$ पर निर्यात किया और इसलिए कोई डम्पिंग नहीं हुई है। निर्यातक ने निर्यातों से दावा की गयी कटौतियों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

44. शंघाई पैसिफिक कैमिकल्स कारपोरेशन

निर्यातक ने दावा किया है कि वह कोक का उत्पादन करता है। यह दावा किया गया है कि उनकी कोकरी पतन के बैकयार्ड में है तथा उत्पादित कोक सीधे बेल्ट द्वारा पतन स्थल पर भेजा जाता है जहां पर यह स्टोर किया जाता है। तथा जहाज में लादा जाता है। अतः कोई अंतर्देशीय भाड़ा शामिल नहीं है। निर्यातक ने भारत के लिए निर्यात कीमत में भण्डारण प्रभारों के कारण कीमत समायोजन का दावा किया है तथा भण्डार प्रभारों का दावा करते हुए कुछ बीजक प्रस्तुत किए हैं। कारखानागत आधार पर निर्यात कीमत $\times\times\times$ की है। निर्यातक ने दावा किया है कि वह चीन के अंदर उत्पाद की बिक्री कर रहा है तथा 17% की दर से वी ए टी की कटौती का दावा किया है जिसे बीजक में भी दर्शाया गया है। यह दावा किया गया है कि घरेलू बिक्री के लिए कोक की डिलीवरी कारखानागत लागत के आधार पर होती है तथा फैक्ट्री से विनिर्माता के परिसर तक की तुलना का खर्च ग्राहक उठाता है। घरेलू बिक्री के मामले में पैकेजिंग, भण्डारण तथा हैंडलिंग के कारण अलग से कोई खर्च नहीं किया जाता है। निर्यातक ने $\times\times\times$ की घरेलू कीमत की तुलना में वी ए टी के पश्चात् कारखानागत आधार पर $\times\times\times$ की घरेलू कीमत का दावा किया है। अतः निर्यातक ने न्यूनमत डम्पिंग मार्जिन का दावा किया है। निर्यातक ने कहा है कि घरेलू बीजकों की संख्या 20,000 से भी अधिक है अतः बीजकों की इतनी बड़ी संख्या तथा उसके पास उपलब्ध थोड़े समय को देखते हुए वह सभी बीजकों को बूढ़े तथा उनकी फोटोप्रतियां करवाने में असमर्थ रहा है। निर्यातक ने मई, जून, अगस्त, अक्टूबर तथा नवम्बर 1996 तथा जनवरी एवं मार्च, 1997 (उन आठ महीनों के तदनु रूप जिनमें निर्यात सौदे हुए थे) के लिए कोक की बीजक चार बिक्री दर्शाते हुए अपने लेजर की एक प्रति प्रस्तुत की है। निर्यातक ने अक्टूबर 96 के महीने के लिए सभी बीजक प्रस्तुत किए हैं और अन्य महीनों के संबंध में नमूना बीजक प्रस्तुत किए हैं। कम्पनी ने शंघाई क्षेत्र के प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार द्वारा प्रमाणित वर्ष 1996 तथा 1997 के लिए अपने लागत विवरण प्रस्तुत किए

हैं तथा यह दावा किया है कि उसने वर्ष 1996 तथा 1997 दोनों में कोक के उत्पादन तथा बिक्री पर लाभ कमाया था और इसलिए चीन के अंदर सूचित की गई घरेलू बिक्री कीमत व्यवहार्य मानी जानी चाहिए तथा सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए।

45. कुछ निर्यातकों ने कोयले के क्रय बीजकों की कुछ प्रतियां प्रस्तुत की हैं। इन बीजकों का अंग्रेजी अनुवाद दुर्भाग्य से अपर्याप्त है और यहां तक कि इनमें कोयले की एश मात्रा भी नहीं दी गई है। अन्य वाणिज्यिक ब्यौरों का भी अनुवाद नहीं किया गया है। यदि किसी मामले में प्राधिकारी इस स्तर पर कोई नया साक्ष्य स्वीकार करने से मनाही करते हैं तो यह दूसरे पक्ष को प्राकृतिक न्याय से वंचित करना होगा जिसके पास इतने समय बाद किसी अतिरिक्त साक्ष्य का खंडन करने का अवसर उपलब्ध नहीं होगा। जैसा कि पहले कहा गया है निर्यातक कई अवसरों के बावजूद अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध करवाने में विफल रहे हैं।

46. याचिकाकर्ताओं के विचार

सामान्य मूल्य के निर्धारण के बारे में याचिकाकर्ताओं के विचार निम्नानुसार हैं :—

46.1 चीन में कोयला खनन उद्योग को राज्य द्वारा रोजगार पैदा करने के साधन के रूप में प्राथमिक तौर पर सहायता प्रदान की जाती है। यह व्यापक स्तर पर अनियंत्रित तथा गैरकानूनी भी होता है। कोयले की लागत अवास्तविक रूप से कम है क्योंकि श्रमिक तथा अन्य सामाजिक कारकों की पूरी तरह से उपेक्षा की गयी है। इस प्रकार इससे कोक की मौलिक लागत अविश्वसनीय हो जाती है। चुनिंदा लेख यह उद्धाटित करते हैं कि कोयला खनन क्रियाकलापों में एक वर्ष में कई हजार जानें चली जाती हैं।

46.2 लाइसेंसिंग अपेक्षाओं की एक जटिल प्रक्रिया है और इसलिए ये सब कम्पनियां संबद्ध हैं तथा सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर पाटन में शामिल हैं।

46.3 चीन में एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है तथा भारत में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अनेक पाटनरोधी मामलों में चीन की एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान की है। घरेलू लेनदेन में कुछेक बीजक प्रस्तुत किए जाने मात्र से यह सिद्ध नहीं होता है कि चीन के अंदर घरेलू तौर पर मुक्त बाजार दर पर कोक बेचा जाता है। चीन में राज्य अब भी अधिकांश उद्यमों के मालिक बने हुए हैं तथा लाइसेंसिंग अपेक्षाओं की एक जटिल प्रक्रिया का संपूर्ण नियंत्रण रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अतः सामान्य मूल्य घरेलू बिक्री के आधार पर नहीं लिया जा सकता है। चीनी मेटकोक के विनिर्माताओं ने कोयले की घरेलू कीमत उपलब्ध करवाने में लापरवाही की है तथा वे "सामान्य मूल्य" की विपरीत गणना पर निर्भर करते हुए प्रतीत होते हैं। चूंकि सामान्य मूल्य को घरेलू कीमतों के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है इसलिए, इसका निर्धारण करना होता है।

46.4 कोयले का हिस्सा कोक की लागत के 70% से अधिक बैठता है और इसलिए कोक की किसी भी कीमत के निर्धारण के लिए कोयले की लागत मूलभूत होती है। ऐसा करने का सर्वोत्तम तथा सही तरीका वह है जब भरपूर प्राकृतिक संसाधनों वाला कोई देश दूसरे देशों से उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के लिए कीमत चुकाएगा। अतः चीन द्वारा आयातित कोयले की सी आई एफ कीमत को कोयले की लागत के रूप में लिया जाना चाहिए।

46.5 निर्यातकों की प्रतिक्रियाओं के अनुसार विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा चीन में कोक की कीमतों में 100% की भिन्नता रही है। यदि वे 33.8

यू एस डालर प्रति मी. टन की दर से कोक की बिक्री कर रहे हैं तो कोयले की कीमत को मुक्त होना चाहिए। किसी भी निर्यातक की अपनी घरेलू बिक्री नहीं है परन्तु उन्होंने दूसरे उत्पादकों से घरेलू बिक्री की जानकारी उपलब्ध की है। कुछ उत्पादकों ने बी ए टी पर कटौती का दावा किया है जबकि दूसरों ने नहीं। अतः निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना गलत है तथा इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी निर्यातक ने कोयले की कीमत प्रस्तुत नहीं है। दूसरी तरफ, विपरीत गणना से कोयले की लागत निकालने के कई प्रयास किए गए थे। इससे इस विचार को मजबूती मिलती है कि कोयले की कीमत, उस कीमत के रूप में ली जाए जिस पर चीनियों द्वारा आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात किया जा रहा है। चीन में कोयला कंपनियां लागत से कम पर कोयले की बिक्री कर रही हैं और इसलिए चीन में कोयले की घरेलू कीमत से उचित लागत का पता नहीं चलता है तथा विभिन्न मामलों में सरकार द्वारा प्रति-इमदाद दी जाती है।

46.6 आयातकों ने यह विवाद नहीं किया है कि सामान्य मूल्य की संगणना उत्पादन लागत का निर्धारण करके की जाए। उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध की गई कार्यप्रणाली का विरोध किया है और अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने चीन में आयातित आस्ट्रेलियायी कोयले की उतराई कीमत के रूप में कोयले की लागत का विरोध किया है। याचिकाकर्ता ने यह दावा कभी नहीं किया है कि चीन में कोक को बनाने के लिए उपयोग में लाए गए कोयले का आस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है। आयातकों ने इस बात से इंकार नहीं किया है कि चीन ने आस्ट्रेलिया से कोकिंग कोयले का आयात किया है और आयातों में आवश्यक रूप से मितव्ययिता होनी चाहिए और इस प्रकार चीन में आस्ट्रेलियायी कोयले की लागत पर चीन में कोक संयंत्रों में कोयले की लागत के रूप में विचार किया जा सकता है।

46.7 याचिकाकर्ता ने इस बात से इंकार किया है कि चीन में विनिर्माण लागत बड़ी हुई है। चीन में इसका आकलन भारत में प्रतिस्पर्धात्मक लागत के आधार पर किया जाता है। चीन के गणना करने वाले मानक यथोचित स्तर के नहीं हैं। इस प्रकार चीन के निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई उत्पादन लागत पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस तरह से चीन के निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई न तो उत्पाद लागत पर और न ही घरेलू मूल्य पर विश्वास किया जा सकता है।

46.8 "कोयले की तुलना में कोक के विनिर्दिष्ट घनत्व" की गणना करने में आयातक असफल रहा है। आम बोलचाल की भाषा में, इसका तात्पर्य यह है कि एक ही आकार की बकेट में कोक की तुलना में ज्यादा कोयले को रखा जा सकता है और इस प्रकार एक टन कोयले की परिवहन लागत एक टन कोक की परिवहन लागत से कम होगी। इन आधारों पर कोक और कोयले का अनुपात 1:1.81 है, भारत में उत्पादित कोक का मूल्य चीनी कोक की तुलना में कम होगा।

47. निर्यातकों/आयातकों के विचार

47.1 प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में यह निष्कर्ष निकाला था कि चीन के सात सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों में से किसी ने भी छूट या घरेलू मूल्य की संरचना के संबंध में कोई साक्ष्य/स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं किया था। तथापि, यह गलत है। प्राधिकारी के निष्कर्ष निर्यातकों द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध किए गए विस्तृत बयानों और साक्ष्य के विपरीत थे। प्राधिकारी ने किसी भी निर्यातक के संबंध में कोई आगे साक्ष्य/स्पष्ट साक्ष्य मांगते हुए कोई कमी संबंधी पत्र जारी नहीं किया था। निर्यातकों ने स्पष्ट किया था कि चीन में स्थल पर अपने दावों के सत्यापन के लिए उन्हें

कोई आपत्ति नहीं है। साक्ष्य/स्पष्ट साक्ष्य के अभाव के आधार पर सभी जवाबों को अलग रखने का निष्कर्ष निकालना और अनन्तिम शुल्कों की सिफारिश करने के पूर्व विचारित निर्णय को प्रदर्शित करता है।

47.2 118.53% की पाटन मार्जिन की गणना और 1800 रु. प्रति मी. टन की पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना तथ्यों के अनुसार नहीं है और यह मनमाना और अवैध है।

47.3 याचिकाकर्ता के अनुसार वर्ष 1996-97 में चीन ने 1280 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है और 80 मिलियन टन कोक का उत्पादन किया है। इस प्रकार इस कोक का उत्पादन करने के लिए 120 मिलियन टन कोकिंग कोयला अपेक्षित है जिसका चीन ने घरेलू उत्पादन किया है। चीन ने परीक्षण के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्रोत से 2.51 लाख टन कोकिंग कोयले को आयात किया जो चीन द्वारा उपयोग में लाए गए कोकिंग कोयले का 0.2% बैठता है। अतः वर्ष 1996-97 के दौरान चीन द्वारा कोकिंग कोयले का आयात कोकिंग कोयले के घरेलू उत्पादन की तुलना में नगण्य रहा है। 0.2% कोकिंग कोयले के आयात को चीनी कोक के सामान्य मूल्य की गणना करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है, जैसा कि आवेदक ने दर्शाया है।

47.4 आस्ट्रेलिया और जापान से आयातित एल ए एम सी का मूल्य भारत को निर्यातित चीनी कोक के मूल्य के भी समान है। जब इनका पाटित नहीं किए जाने का दावा किया जाता है, तब चीन से हुआ कथित पाटन न्यायसंगत नहीं है। तथाकथित पाटन रहित स्रोतों से किए गए आयातों की मात्रा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।

47.5 याचिकाकर्ता ने इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि चीन के भीतर की गयी घरेलू बिक्री सामान्य बिक्री के रूप में नहीं की गयी है। इसलिए यह अनुरोध अस्वीकार्य है।

47.6 निर्यातक ने अपने प्रत्युत्तर में कोयले की लागत, विभिन्न खर्चों, जिन्हें कोक का मूल्य निकालते समय लिया जाना चाहिए, को दर्शाने वाली अपनी लागत शीट प्रस्तुत की है। याचिकाकर्ता का यह दावा कि कोयले का मूल्य अवास्तविक रूप से कम है क्योंकि इसमें प्रमिक एवं अन्य सामाजिक लागत को नजरअंदाज किया गया है, गलत है।

47.7 याचिकाकर्ता का यह दावा कि चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, गलत है। चीन काफी समय से बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो चुका है। चीन के निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य इसका समर्थन करते हैं। भारतीय पाटनरोधी विधान में "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश" के रूप में किसी देश की व्यवहार प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है। याचिकाकर्ता का यह कथन कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कई पाटनरोधी मामलों में चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना है, वास्तविक तौर पर गलत है। जहां कहीं चीन के निर्यातकों से कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था वहां प्राधिकारी ने अपने पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार कार्रवाई की थी और उक्त सर्वोत्तम सूचना या तो भारत में या कुछेक अन्य देशों में प्रचलित कीमतों से निर्धारित की गयी लागत पर आधारित हो सकती है।

47.8 इस बात पर दो राय नहीं हो सकती कि घरेलू बीजक ही घरेलू बिक्री सौदों के सबसे पुष्टा साक्ष्य होते हैं। अगर बीजक किए गए सौदों को सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो काफी असंभव होता है कि किसी अन्य दस्तावेजों पर विश्वास किया जाए। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि केवल घरेलू सौदों के कुछ बीजकों को प्रस्तुत कर देने से यह तथ्य सिद्ध नहीं होगा कि कोक को चीन में मुक्त बाजार दर पर घरेलू तौर पर बेचा गया

है, सही नहीं है। इसलिए, कोक के घरेलू मूल्य पर सामान्य मूल्य निकालते समय विचार किया जाना चाहिए।

47.9 वर्तमान में, सहयोगी निर्यातकों ने सामान्य मूल्य, जिस पर चीन में घरेलू बाजार में बिक्री हुई है, और घरेलू कीमतों की व्यवहारिकता प्रदर्शित करने के लिए उत्पादन लागत के भी ब्यौरे उपलब्ध किए हैं। ऐसा मामला होने के कारण निर्धारित की गयी लागत का सहारा लेना अथवा किसी अन्य काल्पनिक पहलू का संदर्भ लेकर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना वांछित नहीं है।

47.10 पी आई एम ए ने संकेत दिया है कि याचिका में दिए आंकड़ों पर विचार करके भी यह स्थापित किया जा सकता है कि चीन के निर्यातकों द्वारा पाटन नहीं किया गया है। यह भागते हुए कि चीन के कोयले की एफ ओ बी लागत आस्ट्रेलिया में एफ ओ बी लागत के समान है (वास्तव में यह काफी कम है), फैक्टरी गेट पर चीन के कोकिंग संयंत्र के लिए कोयले का लागत 18.02 अमरीकी डालर होगी। (एफ ओ बी से 51.02 अमरीकी डालर की कटौती, स्टीबडोरिंग के कारण 8 अमरीकी डालर और आंतरिक ढुलाई के लिए 25 अमरीकी डालर)। कोक की लागत 1.5 गुणा की परिवर्तन दर पर 27.03 अमरीकी डालर की बैठेगी। अगर याचिका में दर्शाई गई 29.17 अमरीकी डालर की विनिर्माण लागत को जोड़ दिया जाए तो चीन में कोक की लागत 56.20 अमरीकी डालर प्रति मी. टन बैठेगी। निर्यात मूल्य इस घरेलू मूल्य से ज्यादा रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा दर्शाई गई 206 अमरीकी डालर प्रति मी. टन की लागत काफी बढ़ा-चढ़ा कर दी गई है। एक आयातक ने यह भी संकेत दिया है कि कोक में कोयले की परिवर्तन लागत सामान्यतः लगभग 400 रु. प्रति मी. टन बैठती है और विनिर्माण लागत को 1050 रु. प्रति मी. टन लिए जाने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। याचिकाकर्ता ने 22 अमरीकी डालर के समुद्री भाड़े का दावा किया है, जो कि वास्तव में 17 अमरीकी डालर होना चाहिए। अतः मैटकोक का सी आई एफ मूल्य 87 अमरीकी डालर प्रति मी. टन होना चाहिए और यह याचिकाकर्ता के अपने तथ्यों पर आधारित है। निर्यात मूल्य सी आई एफ आधार पर लगभग 97 अमरीकी डालर है और इस प्रकार कोई पाटन नहीं हुआ है।

47.11 तथापि, कुछ आयातकों ने यह अनुरोध किया है कि याचिका में उपलब्ध सूचना के आधार पर पाटन मार्जिन 502 रु. निकलता है और इसलिए शुल्क को घटाकर 502 रु. कर देना चाहिए। तथापि, यह अनुरोध किया गया है कि यह कुछ कल्पनाओं पर आधारित है और यह स्वीकार किए बिना कि चीन के निर्यातकों द्वारा कोई पाटन किया जा रहा है। यह भी अनुरोध किया गया है कि पहुंच मूल्य की गणना सही नहीं की गई है और इसमें संशोधन की आवश्यकता है।

47.12 निर्यातकों ने यह अनुरोध किया है कि उन्होंने जांच की शुरुआत के पश्चात् भेजे गए प्रश्नावली के उनके जवाबों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाएं निहित हैं ताकि वह प्रथमदृष्टया इस तथ्य पर पहुंच सके कि ऐसे निर्यातकों द्वारा भारत में मैटकोक का पाटन नहीं किया जा रहा है। प्राधिकारी अपने इस प्रथमदृष्टया विचार की निर्यातक और उत्पादक के स्थल का सत्यापन करके पुष्टि कर सकते हैं क्योंकि निर्यातक/उत्पादक ने ऐसे सत्यापन के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी। प्राधिकारी ने इस सूचना को इस आधार पर त्याग दिया था कि कोई भी साक्ष्य/स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने यह भी माना था कि ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त वस्तु की बिक्री निर्यातकों द्वारा की गयी है, जिन्होंने वस्तु का उत्पादन नहीं किया था और यह स्पष्ट नहीं

था कि क्या किया गया दावा निर्यातक से संबंधित है या उत्पादक से/और इस प्रकार प्राधिकारी निर्यात मूल्य का निर्धारण नहीं कर सका क्योंकि निर्यातकों के लिए उत्पादकों की कीमत उपलब्ध नहीं थी और उत्पादकों के सामान्य मूल्य की तुलना निर्यातक की निर्यात कीमत से नहीं की जा सकती। निर्यातकों द्वारा अब यह अनुरोध किया गया है कि चीन से वस्तु का निर्यात केवल उस संगठन द्वारा किया जाता है जिसके पास निर्यात लाइसेंस हों। सभी उत्पादक निर्यात लाइसेंसधारी नहीं होते हैं और इसीलिए अपनी वस्तु को उन निर्यात कम्पनियों को बेच देते हैं जिनके पास निर्यात लाइसेंस होता है। जो तत्पश्चात् विभिन्न देशों को वस्तु का निर्यात करते हैं। इस प्रकार निर्यातकों ने प्रश्नावली का जवाब दिया था और उसी समय उत्पादन लागत और उत्पादक की घरेलू बिक्री के ब्यौरे भी दिए थे ताकि प्राधिकारी निर्यात सहयोग और संबद्ध उत्पादक के लिए पाटन मार्जिन की गणना करने में सक्षम हो सके। चूंकि, सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं था। इसलिए निर्यातकों ने दावा किया कि उन्होंने नमूना बीजकों को प्रस्तुत किया था और यह माना गया था कि जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा सभी अन्य बीजकों और साक्ष्य को देखा जाएगा। लागत विवरण के लिए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के संबंध में निर्यातक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रश्नावली में लागत विवरण के समर्थन में कोई और साक्ष्य देना अपेक्षित नहीं था। उत्पादन लागत सत्यापन स्थल का मामला होता है अतः निर्यातकों ने तर्क दिया कि पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने से उनके हित के प्रति गंभीर भेदभाव हुआ है।

48. प्राधिकारी द्वारा जांच

48.1 प्राधिकारी ने नोट किया है कि यद्यपि चीन में सभी उत्पादकों ने समान विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी को अपनाया है तथापि मैटकोक की उत्पादन लागत के संबंध में किये गये उनके दावे काफी हद तक भिन्न-भिन्न हैं। 100 के राष्ट्रीय बिन्दु पर शंघाई पैसेफिक के लिए निविष्टि के प्रत्येक घटक की लागत पर विचार करते हुए अन्य तीन उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा, जिन्होंने प्राधिकारी के अनुरोध पर प्रपत्र में आंकड़े/सूचनाएं दी हैं; दावा की गयी लागतों को सूचीबद्ध किया गया है जो निम्नानुसार प्रदर्शित होती है :—

	शंघाई पैसेफिक	चीन नार्थ	चीन नेशनल	चीन नेशनल आई/ई
कच्ची सामग्री	100	31.17	52.39	35.57
प्रत्यक्ष श्रम	100	63.33	63.33	80.33
उपयोगिता	100	12.91	13.17	22.29
ऊपरी खर्च				
— विनिर्माण	100	1.51	10.54	0.00
— मूल्य ह्रास	100	5.80	16.91	17.51
— ब्याज	100	6.74	157.87	21.91
— पैकिंग लागत	100	0.00	0.00	0.00
— एस जी ए	100	48.25	24.56	354.39
— घटाएं : सह-उत्पाद	100	0.00	0.00	0.00
उत्पादन की कुल लागत निवल	100	58.79	89.49	66.19

नोट : 1. विशेष कर को सूचीबद्ध नहीं किया गया क्योंकि केवल एक निर्यातक द्वारा इसका दावा किया गया है।

2. उपरोक्त सारणी में निर्धारित प्रपत्र में उपर्युक्तानुसार सूचना न देने वालों से संबंधित सूचना शामिल नहीं है।

48.2 उपरोक्त से यह देखा जाता है कि प्राधिकारी द्वारा विश्लेषित चारों निर्यातकों के निविष्टि की किसी मद की लागत तुलनीय नहीं है। इसके अलावा, भिन्नताएं भी काफी अधिक हैं। यह भी नोट किया गया कि हालांकि एक निर्यात (मैसर्स चीन नार्थ ने) "विशेष कर" की तरफ काफी अधिक लागत का दावा किया है तथापि, किसी अन्य निर्यातक ने इस बारे में किसी लागत का दावा नहीं किया है। निर्यातकों द्वारा किया गया दावा सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों पर आधारित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए, प्राधिकारी ने उत्पादन लागत पर विस्तृत सूचना देने का अनुरोध किया था, जिसके लिए निर्यातकों को प्रोफार्मा भी उपलब्ध किया गया था ताकि निर्यातक संगत सूचना दे सकें। तथापि, प्राधिकारी द्वारा किए गए अनुरोध पर किसी भी निर्यातक ने लागत निर्धारण संबंधी विस्तृत सूचना प्रस्तुत नहीं की है। निर्यातकों का यह तर्क कि घरेलू बाजार में उनकी बिक्री लागत मूल्य से ज्यादा दर पर की गयी थी जो कि उनके द्वारा कमाए गए लाभों से स्पष्ट हो जाता है (इसके लिए निर्यातकों ने कुछ साक्ष्य भी दिए हैं) भी भ्रामक हैं। प्राधिकारी ने नोट किया है कि एक निर्यातक ने ऐसी सूचना प्रस्तुत की है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि उक्त निर्यातक ने घरेलू बाजार में बिक्रियों पर लाभ का दावा किया है जबकि सह-उत्पादों की बिक्रियों में काफी घाटा होने का दावा किया है। प्राधिकारी ने निम्नलिखित मुद्दों पर विशिष्ट सूचना देने का अनुरोध किया था।

- * चीन में की गई सभी बिक्रियों की सौदे-वार सूची, जिसमें सभी बिक्रियां शामिल हों और इनके साथ संगत बीजक होने चाहिए।
 - * भारत को किए गए सभी निर्यातों की सौदे-वार सूची, जिसमें सभी बिक्रियां शामिल हों और संगत बीजक संलग्न किए गए हों। यदि, निर्यातक द्वारा माल का निर्यात सीधे न किया गया हो उसे मूल्य के साथ, जिस पर माल का निर्यात किया गया है निर्यातक को जोड़ने वाली अनुकूल सूचना भारतीय आयातकों को जारी किए गए संगत बीजकों के साथ दी जानी चाहिए।
 - * भारत को छोड़कर अन्य देशों को किए गए सभी निर्यातों की सौदे-वार सूची (देश-वार), जिसमें सभी बिक्रियां शामिल हों और संगत बीजक संलग्न किए गए हों।
 - * प्रश्नावली को परिशिष्ट 3क और 3ख के संदर्भ में घरेलू बाजार में की गई बिक्रियां अथवा भारत को किए निर्यातों में से संगत साक्ष्य द्वारा समर्थित दावा किए गए समायोजनों का आधार।
 - * निर्यातकों को भेजे गए पत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा "1" के अनुसार मेटकोक की उत्पादन लागत का ब्यौरा यदि मेटकोक के उत्पादन के दौरान कोई सह-उत्पाद शामिल किया जा रहा है तो संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार सूचना मांगी गयी थी, जिसमें निम्नलिखित के बारे में सूचना शामिल थी :—
- सह-उत्पाद का नाम
 - उत्पादित सह-उत्पाद की कुल मात्रा
 - उत्पादित सह-उत्पाद की उपयोगिता जिसमें अलग से (मात्रा और मूल्य में) सह-उत्पादन की कारखानागत खपत और बाहर की गयी बिक्री का उल्लेख किया जाए।
 - * मेटकोक का कुल उत्पादन

* आंच अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के लिए कंपनी के प्रचालनों और वित्तीय निष्पादन का संकेत देने के लिए हानि एवं लाभ खाता, तुलन पत्र और अन्य कोई वित्तीय विवरण की एक प्रति।

48.3 यह उल्लेख किया गया कि सारी सूचना या तो अंग्रेजी में दी हो अथवा अंग्रेजी रूपान्तर के साथ हो। सभी दस्तावेज सम्बंधित कंपनी के प्रमुख अधिशासी द्वारा यथार्थ, पूर्ण, सही रूप में तथा सत्य एवं उचित तस्वीर प्रस्तुत करते हुए प्रमाणित होने चाहिए। सभी सूचना और दस्तावेज एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा भी यथार्थ, पूर्ण और सही रूप में प्रमाणित होने चाहिए।

49. प्राधिकारी यह नोट करता है कि किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा किए गए विशेष अनुरोध के बावजूद उपर्युक्त सूचना प्रस्तुत नहीं की। इसलिए प्राधिकारी स्वयं को संतुष्ट करने की स्थिति में नहीं है कि क्या सह-उत्पाद के बारे में समायोजन के संबंध में निर्यातक द्वारा किया गया दावा न्यायसंगत है। सह-उत्पाद वसूली के लिए निर्यातक का दावा अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि याचिकाकर्ता ने ऐसी जानकारी दी है जिसमें यह सुझाया गया है कि सह-उत्पाद के कारण की जाने वाली वसूली 8 यू.एस. डालर से अधिक नहीं होनी चाहिए, सूचना प्रस्तुत की है (भारत में मेटकोक के एक ऐसे सबसे बड़े उत्पाद द्वारा की गई वसूली पर आधारित जिसके पास विनिर्माण प्रक्रिया की सह-उत्पाद वसूली प्रणाली है), लेकिन एक आयातक ने स्वीकार किया है कि वसूली 3 अमरीकी डालर से ऊपर नहीं हो सकती है। निर्यातक द्वारा किया गया दावा अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए दावों से किसी भी तरह से मेल नहीं खाता है और निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन से मांगी गई विशेष जानकारी को दबा दिया है। जहां तक प्राधिकारी द्वारा मांगी गई वास्तविक जानकारी का प्रश्न है वह प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार निर्यातक ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है।

50. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी प्रारंभिक जांच निष्कर्षों को अधिसूचित करने से पहले वांछित सूचना की मांग कर सकते थे। या प्राधिकारी निर्यातकों के परिसर में सूचना की जांच कर सकते थे। प्राधिकारी का मत है कि हितबद्ध पक्षों को प्रश्नावली भेजने का प्रयोजन उन्हें निर्धारित तौर-तरीके से उत्तर देने की अनुमति देना है। प्राधिकारी पर यह दायित्व नहीं है कि वे प्रस्तुत किए गए उत्तर की कमियों को निकालें, खासकर तब, जबकि प्राधिकारी को निर्धारित समयावधि के भीतर प्रारंभिक या अंतिम आंच निष्कर्ष अधिसूचित करने होते हैं।

51. निर्यातक के इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि प्राधिकारी निर्यातक द्वारा किए गए दावे की जांच कर सकते थे क्योंकि स्थल जांच का उद्देश्य किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच करना है न कि सूचना एकत्रित करना। वास्तव में पाटनरोधी करार के अनुबंध 1 में व्यवस्था है कि सूचना जांच के पहले एकत्र की जानी चाहिए। प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों के परिसर में सूचना की जांच हितबद्ध पार्टियों द्वारा सूचना दिए जाने का विकल्प नहीं हो सकती है। वास्तव में, जब मांगी गई सूचना निर्धारित तौर-तरीके से नहीं प्रस्तुत की जाती है तो जांच दौरे का कोई व्यावहारिक प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता है।

52. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी को सह-उत्पाद वसूली संबंधी निर्यातक के दावे की अपेक्षा करने के लिए विवश होना पड़ा है। सह-उत्पाद वसूली प्राधिकारी को उपलब्ध सूचना के आधार पर मुहैया कराई गई जो भारत के एक बड़े मेटकोक उत्पादक द्वारा वसूली किस्म की

प्रक्रिया को लागू करते हुए की गई वसूली पर आधारित है। वसूली के लिए समायोजन करने के बाद यह पाया गया कि निर्यातक की उत्पादन लागत घरेलू बाजार में बिक्री मूल्य से बहुत अधिक है। इसलिए घरेलू बाजार में यह बिक्री मूल्य कीमत के रूप में सामान्य व्यापार के अनुरूप नहीं है और इसलिए इसकी उपेक्षा करनी पड़ी।

53. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने धारा 9क (1) ग के अनुसार उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। निर्यातक द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत की गणना सह-उत्पाद वसूलियों का समायोजन करने के बाद पुनः की गई है। निर्यातक द्वारा किए गए व्यय के आधार पर बिक्री सामान्य और प्रशासनिक व्यय के लिए उचित छूट दी गई है। उचित प्रक्रिया के अनुसार और चीन जन.गण. से निर्यातक से प्राप्त अपर्याप्त सूचना के परिप्रेक्ष्य में 5% की दर से एक उचित आमदनी प्रदान की गई है।

54. उपरोक्त पैराग्राफों से प्राधिकारी ने नोट किया है कि निर्यातकों से प्रश्नावली का उत्तर देते समय निर्यात कीमतों, घरेलू कीमतों और लागत पर पर्याप्त और समुचित सूचना देने के कहा गया था। यह सूचना सामान्य मूल्य निर्यात कीमत और डिंपिंग मार्जिन के निर्धारण के लिए आवश्यक है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच निष्कर्षों में पाया कि निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना अधूरी और अपर्याप्त थी और प्राधिकारी इस सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारण करने की स्थिति में नहीं थे।

55. प्रारंभिक जांच निष्कर्षों के जारी होने के बाद सात निर्यातकों में से पांच निर्यातकों ने घरेलू कीमत, निर्यात मूल्य और लागत आंकड़ों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत की। प्राधिकारी ने पाया कि नियमानुसार सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए यह सूचना भी अपर्याप्त थी। इसलिए दिनांक 30-6-98 के पत्र के द्वारा (पैरा 48.2 में ब्यौरा पहले ही दिया जा चुका है) प्राधिकारी ने निर्यातकों से पत्र में मांगी गई आवश्यक विस्तृत सूचना मुहैया कराने का अनुरोध किया। प्राधिकारी ने बाद के एक पत्र में पुनः ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्यातकों से अपनी आवश्यकता जतायी। इस प्रकार अनेक मौकों पर आवश्यक सूचना देने के लिए निर्यातकों को पर्याप्त अवसर दिया गया था।

56. प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिनांक 30-6-98 के पत्र के जबाब में दिनांक 20-7-98 को पांच निर्यातकों ने जानकारी प्रस्तुत की। जांच के बाद, प्राधिकारी ने पाया कि कीमत के बारे में यथोपेक्षित जानकारी नहीं दी गई है। प्राधिकारी ने पाया कि लागत आंकड़ों के बारे में भी विवेचनात्मक जानकारी नहीं दी गई है, जैसाकि दिनांक 30-6-98 के पत्र में बताया गया है निर्यातकों से कच्चे माल की कीमत, उपयोगिता विनियोग और विविध उत्पादों के लिए ऊपरी खर्चों के आबंटन, लागत पत्र, संतुलन पत्र और लाभ एवं हानि लेखा सह-उत्पादों की लागत जानकारी देने की अपेक्षा की गई थी। प्राधिकारी ने पाया कि निर्यातकों द्वारा दावा की गई लागत की जांच के लिए किसी भी निर्यातक ने पर्याप्त ब्यौरा/साक्ष्य नहीं दिए हैं। यह ब्यौरा/साक्ष्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विविध मदों पर लागत जैसे कि कच्चे माल, श्रम, ऊपरी व्यय, और अन्य व्यय के बारे में निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए लागत आंकड़ों में काफी अंतर है और इसे पैरा 48.1 में दर्शाया गया है। यह निर्धारित करने में कि क्या घरेलू कीमत लागत से अधिक है या नहीं लागत आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। नियमों के अंतर्गत, अगर घरेलू कीमत लागत से कम है तो इस घरेलू कीमत को सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

प्राधिकारी ने यह भी पाया कि निर्यातकों/उत्पादकों ने दावा किया है कि उन्हें मुनाफा कोक की बिक्री के कारण हुआ है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसे निर्यातकों को गैस जैसे सह-उत्पादों की बिक्री में काफी हानि हो रही है। कोक और ऐसे अन्य सह-उत्पादों के बीच लागत वर्गीकरण को अलग करने का आधार स्पष्ट नहीं है और इनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया है हालांकि यह विशेष रूप से मांगा गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रति इकाई कोक से उत्पादित सह-उत्पादों और ऐसे सह-उत्पादों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

57. इस तरह प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि :

(क) विभिन्न निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत लागत आंकड़े तुलनीय नहीं हैं और इसलिए इन पर निर्भर नहीं किया जा सका।

(ख) लागत आंकड़ों के बारे में पूरी जानकारी नहीं प्रस्तुत की गई है। इस प्रयोजन से, जैसाकि उपर्युक्त पैरा 48.2 में ब्यौरा दिया गया है प्राधिकारी ने निर्धारित प्रोफार्मा में आंकड़े देने का अनुरोध किया था जिस पर न तो ध्यान दिया गया और न ही अपेक्षित जानकारी दी गई है।

(ग) सह-उत्पादों के विषय में, जैसा कि दिनांक 30-6-98 के पत्र में बताया गया है, किसी भी निर्यातक ने अपेक्षित जानकारी नहीं दी है। निर्यातकों ने कोक की बिक्री से लाभ होने का दावा किया किन्तु अन्य सह-उत्पादों पर काफी हानि हुई है और लागत के वर्गीकरण का आधार नहीं दिया गया है।

58. तथापि प्राधिकारी ने मै. संधाई पैसिफिक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर चीन में कोक की लागत निर्धारित करने का प्रयास किया है जोकि प्रश्नावली का उत्तर देने वालों में से चीन में मैटकोक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि हलांकि मै. संधाई ने पर्याप्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की है फिर भी उन्होंने अन्य निर्यातकों के मुकाबले बेहतर जानकारी प्रस्तुत की है। उनके सबसे बड़े उत्पादक होने के नाते भी उन्हें चीन की लागत का प्रतिनिधि माना जा सकता है। इस तरह प्राधिकारी मानते हैं कि संधाई पैसिफिक द्वारा प्रस्तुत की गई लागत जानकारी मौजूदा मामले में "सबसे बड़िया उपलब्ध जानकारी" है और इसलिए आंकी गई उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजन से इस पर विचार किया जा सकता है। इस तरह चीन में उत्पादन लागत तैयार करते समय प्राधिकारी ने मै. संधाई पैसिफिक द्वारा प्रस्तुत की गई कच्चे माल, श्रम और ऊपरी खर्चों पर आई लागत को स्वीकार किया है। तथापि यह पाया गया कि मै. संधाई जिन सह-उत्पादों की वसूली कर रहा है उनमें से अधिकांश घाटे पर बेचे जा रहे हैं। लागत वर्गीकरण का आधार और साक्ष्य/ब्यौरे के अभाव में सह-उत्पादों के लागत वर्गीकरण को निर्यातकों के दावों के अनुरूप स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी ने सह-उत्पादों की वसूली के मानदंडों का पता लगाने का प्रयास किया और नोट किया कि सकल लागत 100 के रूप में मानते हुए सह-उत्पादों पर वसूली निम्नानुसार है :

	सेल संधाई द्वारा दावाकृत	आयातक	किर्क	आयमर*
सकल लागत	100	100	100	100
सह-उत्पादों की				
कटौती	47.54	19.44	6.23	17.51
कोक	52.46	80.56	93.77	82.49

* रसायनिक प्रौद्योगिकी पर किर्क आ मर इन्क्लोपीडिया

59. प्राधिकारी ने विचार किया है कि सेल के मामले में वसूली प्रतिशत पर्याप्त है और विश्वसनीय है, और संधाई द्वारा किए गए दावों के

अनुसार लागत में सह-उत्पादों की वसूली की अनुमति दी गई है। इस तरह निष्कली गई लागत की गणना निम्नानुसार की गई है:—

अमरीकी डालर में	
कच्चा माल, उपयोगिता, ऊपरी खर्च और व्यय	***
जैसाकि संघाई द्वारा दावा किया गया है	
कटौती : सह-उत्पाद 19.44% की दर से	***

सकल लागत	***
5% की दर से उचित लाभ जोड़ा गया है	***
सामान्य मूल्य	***

60. इस तरह प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि चीन में मेटकोक का सामान्य मूल्य *** है।

61. कुछ हितवद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी द्वारा आयातित आस्ट्रेलियाई कोयले के आधार पर कोक की लागत की गणना करना न्यायोचित नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकारी ने भी आस्ट्रेलियाई कोक के आधार पर लागत की गणना नहीं की है।

62. प्राधिकारी ने भारत की निर्यात कीमत में समायोजन के साथ-साथ कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत में भी समायोजन की अनुमति दी है जैसा कि निर्यातक द्वारा दावा किया गया है।

*सभी वाणिज्य लागतों की गणना में एकरूपता बनाये रखने के लिये

63. डमिंग मार्जिन: सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना से 28.95 डमिंग मार्जिन दिखाई देता है:—

(घ) क्षति का विश्लेषण

64. याचिकाकर्ता के विचार

64.1 बी एल ए कोक की कुल खरीद में कमी आई है, बिक्री कीमत पर दबाव है, स्टॉक में वृद्धि हुई है और क्षमता बंद है। सी से अधिक श्रमिकों की छटनी कर दी गई है। धनबाद में हजारों श्रमिकों ने अपनी जीविका खो दी है और कई एककों में उत्पादन बंद हो गया है। चेलमैन के मामले में, समूचे संयंत्र को बंद कर दिया गया है और कंपनी को बी आई एफ आर ने रुग्ण एकक के रूप में दर्ज कर लिया है। दुर्गापुर परियोजना, संदर्न फ्यूल्स और गुजरात एन आर ई ने भी अपने संयंत्रों को अंशतः बंद कर दिया है। कुछ कंपनियों ने अपनी विस्तार योजनाओं को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है।

64.2 घरेलू उद्योग के पास वृद्धि और मांग को पूरा करने के लिए क्षमता भंडार और गुणवत्ता उपलब्ध है। तथापि उनकी वृद्धि लगभग 4 वर्षों से स्थिर है जबकि चीन से आयात में 93-94 से 96-97 तक 916% वृद्धि हुई है। दूसरे देशों से हुए आयात में वृद्धि अपेक्षाकृत कम अर्थात् 173% हुई है। चीन से आयातों में वृद्धि पाटन के कारण हुई है। घरेलू उपयोक्ता भारतीय मेटकोक के स्थान पर चीन के मेटकोक पर निर्भर हो गए हैं।

64.3 प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क निम्न दर पर लगाया है। यह शुल्क 1800/-रु. प्रति मी. टन की जगह 4147 रु. होना चाहिए अर्थात् 3499 रु. (सी आई एफ निर्यात मूल्य) का 118.53% (प्रारंभिक जांच निष्कर्षों में पाटन सीमा)।

64.4 प्राधिकारी को पिछली तारीख से शुल्क लगाना चाहिए। चीन से पाटन होने का स्पष्ट इतिहास है क्योंकि चीन पाटन रोधी जांच के ऐसे कई मामलों में प्रकाश में आया है, जिनसे घरेलू उद्योग की क्षति हो रही है।

64.5 चीन से आयात के कारण क्षति हुई है। गैर-पाटन स्तरों से कोक के आयात से क्षति नहीं हो रही है जैसाकि ऐसे कई आयात टिस्को द्वारा किए गए हैं जो एक बड़ा उपभोक्ता है। टिस्को द्वारा बाजार से "व्यापारिक कोक" की खरीद न्यूनतम हुई। जहां अन्य देशों से आयात स्थिर रहा है, वहीं चीन से आयातों में महत्वपूर्ण ढंग से वृद्धि हुई है।

65. क्षति के बारे में आयातकों और निर्यातकों के विचार

65.1 क्षति का विश्लेषण निष्पक्ष ढंग से नहीं किया गया है। आई.सी.ए. (धनबाद) घरेलू उद्योग नहीं है और उसे क्षति के विश्लेषण में से भी निकाला जाना चाहिए। प्रारंभिक जांच-परिणामों में से ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ये घरेलू विनिर्माता कौन-कौन हैं जिनके आर्थिक संकेतकों को ध्यान में रखा गया था।

65.2 याचिकाकर्ता की क्षति के मार्जिन की गणना सही नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई लागत की सावधानीपूर्वक जांच होनी चाहिए और अन्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के कोयले का सर्वोत्तम सम्मिश्रण करने से जो बचत होगी, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर ऐसी लागत बचत को भी हिसाब में लिया जाता है, जैसा कि किया जाना चाहिए, तो क्षति की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी। प्रारंभिक जांच-परिणाम में जिस क्षति की गुंजाइश का आकलन किया गया है, वह कुछ ज्यादा है।

65.3 मेटकोक का उपभोक्ता उद्योग अत्यधिक दबाव में है और इस समय स्थापित क्षमता का 50% से भी कम का प्रचालन कर रहा है। पिग आयरन उद्योग ने कीमतों में कमी कर दी है। मेटकोक की लागत का हिस्सा पिग आयरन की उत्पादन लागत में करीब 40% होता है। एल ए एम सी की लागत में किसी भी तरह की वृद्धि से पिग आयरन की अन्तिम लागत में वृद्धि होगी, जिससे पिग आयरन के विनिर्माता अपने उत्पादों को नहीं बेच पाएंगे। एल ए एम सी पर किसी भी प्रकार के पाटन-रोधी शुल्क के लगाए जाने से सभी पिग आयरन एकक बंद हो जाएंगे और इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार की हानि होगी।

65.4 घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत अन्य की तुलना में ज्यादा है जो कि सह-उत्पाद को काम में लाने एवं बिजली तथा भाप का उत्पादन करने में सक्षम हैं। याचिकाकर्ता बहुमूल्य सह-उत्पाद का उत्पादन करने के लिए परिवर्तनशील पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर रहे हैं। क्षति उठाने का यही प्रमुख कारण है न कि चीन से कथित पाटन।

65.5 आयातित कोयले में से एल.ए.एम.सी. की कुल उपलब्धता 5 लाख मी. टन से कम है जबकि आवश्यकता 2 मिलियन मी. टन से ज्यादा है। पिग आयरन के विनिर्माताओं को आवश्यक रूप से आयात करना होता है तथा इतनी बड़ी मात्रा पर शुल्क लगाना विवेकपूर्ण नहीं है। एल ए एम सी के घरेलू विनिर्माताओं को किसी भी प्रकार का संरक्षण देने से पिग आयरन के विनिर्माताओं को गंभीर क्षति होगी।

65.6 ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं जिनसे यह पता चलता हो या प्रमाणित होता हो कि मेटकोक के किसी कथित पाटन से भारत में एककों को बंद करना पड़ा। याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और उन्हें किसी भी तरह से प्रमाणित नहीं किया गया है।

65.7 चीन के कोक के आयात में वृद्धि कई वर्षों से मेटकोक की आवश्यकता में वृद्धि के कारण थी। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और क्षमता उपयोग के आरोप पूर्णतया भ्रान्त धारणा हैं।

65.8 1800 रु. प्रति मी. टन की दर से लगाया गया अनन्तिम पाटन रोधी शुल्क एम बी एफ उद्योग के अस्तित्व को जोखिम में डालता

है। प्रति वर्ष 3 मिलियन मी. टन से ज्यादा एम बी एफ क्षमता पिछले 5 वर्षों के दौरान स्थापित की गई है जिसमें 3000 करोड़ रु. का निवेश और एक लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार शामिल है। पिंग आयरन/स्टील की लागत पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 1400 रु. बैठता है। इस स्तर पर, पिंग आयरन का आयात ज्यादा आकर्षक है। इसका अर्थ होगा पिंग आयरन के उत्पादकों के लिए बन्दी एवं पिंग आयरन का आयात के लिए विदेशी मुद्रा का हास। एम बी एफ द्वारा गुणवत्ता कारणों से घरेलू मेटकोक का उपयोग नहीं किया जा सकता और इस प्रकार वास्तव में पाटन-रोधी शुल्क से घरेलू कोक उत्पादकों को सहायता नहीं मिलती है।

65.9 आयातक द्वारा यह बताया गया है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है। उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है और विन्हा वर्षों में एल ए एम सी की मांग में भी वृद्धि हुई है। वास्तव में, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन और बिक्री अपर्याप्त है। मांग को पूरा करने के लिए स्थापित क्षमता अपर्याप्त है। जिन कंपनियों को घरेलू उद्योग के प्रयोजन के लिए शामिल नहीं किया गया है, उन कंपनियों द्वारा किए गए एल ए एम सी के आयात को क्षति के प्रयोजनार्थ शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह तर्क भी दिया गया है कि एल ए एम सी के बाजार हिस्से में गिरावट और आयात के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। घरेलू विनिर्माता यथोचित लाभ के साथ अपने उत्पादन की पूरी लागत की वसूली करने में समर्थ हैं और इस उत्पाद की उचित बिक्री-कीमत से ज्यादा प्राप्त करने में समर्थ हैं।

प्राधिकारी द्वारा क्षति का विश्लेषण

66. ऊपर के नियम 11, अनुबंध-II के अनुसार जब क्षति का जांच-परिणाम प्राप्त होता है तब ऐसे जांच-परिणाम में घरेलू उद्योग की क्षति का निर्धारण करना होता है और "इसमें सभी सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है जिसमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का बाद में पड़ने वाला प्रभाव शामिल है " कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण महत्वपूर्ण रूप से कीमतों में कमी हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव महत्वपूर्ण स्तर तक कीमतों को दबाने का है या कीमतों की ऐसे वृद्धि को रोकने का है, जो कि अन्यथा, हुई होती।

67. ऊपर के नियम 11 के अनुच्छेद II (iii) में आगे यह व्यवस्था है कि ऐसे मामले में जहां एक से ज्यादा देश से किसी उत्पाद के आयात पर एक साथ ही पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तब निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन तभी करेंगे जब वह यह निर्धारण करेंगे कि प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में निर्धारित डम्पिंग मार्जिन निर्यात कीमत की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से ज्यादा है तथा प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत है या जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, तब संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयातों का सात प्रतिशत से ज्यादा है तथा आयातित वस्तु एवं सामान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के संदर्भ में आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उपयुक्त है।

68. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि डम्पिंग मार्जिन और संदर्भाधीन देश से आयातों की मात्रा ऊपर निर्धारित सीमाओं से ज्यादा

है। आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन उपयुक्त है क्योंकि संदर्भाधीन देश से निर्यात कीमतें भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा मांगी जा रही कीमतों के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा कर रही थीं।

69. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने और ऐसे संकेतकों पर विचार किया है जिनका प्रभाव उद्योग की दशा पर पड़ता है, जैसे कि उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, उक्त नियमों के अनुबंध II (IV) के अनुसार पाटन का विस्तार और मार्जिन इत्यादि।

69.1 पाटित आयातों की मात्रा और बाजार हिस्सा

समग्र रूप से पाटित चीनी कोक की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई। निम्नांकित सारणी से यह स्पष्ट होगा:—

वर्ष	मी. टन
1993-94	79452
1994-95	562451
1995-96	964936
1996-97	741100

69.2 उपर्युक्त से यह देखा गया है कि भारतीय बाजार में चीनी कोक का आयात 93-94 के 79452 मी. टन से बढ़कर 96-97 में 741100 मी. टन हो गया जो कि 834% की वृद्धि दर्शाता है। किन्तु, पिछले वर्ष की तुलना में 1996-97 में गिरावट हुई है। प्राधिकारी का विचार यह है कि यद्यपि 96-97 में सकल बाजार में गिरावट आई है, लेकिन सभी निर्यातक देशों से कुल आयात मात्रा में वृद्धि हुई है।

69.3 बाजार हिस्सा : निम्नांकित सारणी से पाटित चीनी वस्तुओं की तुलना में एल ए एम सी के घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से का संक्षेप में पता चलता है :

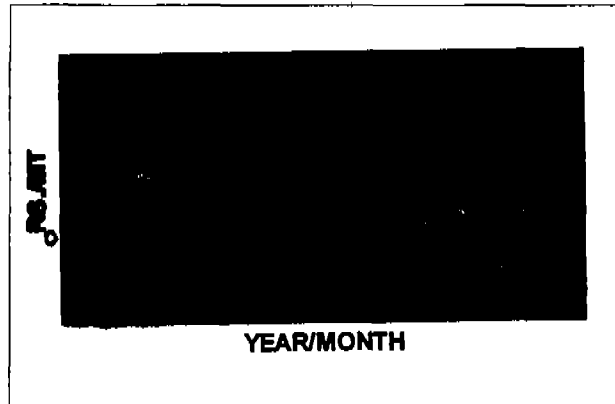
वर्ष	96-97	95-96	94-95
भारत में मेटकोक का कुल बाजार (मी. टन)	1244818	1415391	796922
याचिकाकर्ताओं का उत्पादन (बीएलए)	119337	115862	87512
अन्य का उत्पादन	120908	122026	41345
घरेलू उद्योग का कुल उत्पादन	240245	237888	128857
घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा	19.30%	16.8%	16.2%
चीन से आयात	741100	964936	562451
चीन से आयात का बाजार हिस्सा	59.5%	68.2%	70.6%
देशों से आयात (चीन को छोड़कर)	263473	212567	105614
अन्य देशों का बाजार हिस्सा	21.2%	15.0%	13.2%

69.4 याचिकाकर्ताओं की लाभप्रदता : यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता के नीचे दिखाए गए सकल योगदान में गिरावट आई है:

वर्ष	बिक्री लागत रु. प्रति मी. टन	बिक्री-मूल्य रु. प्रति मी. टन	योगदान रु. प्रति मी. टन
1994-95	***	***	***
1995-96	***	***	***
1996-97	***	***	***

यह भी देखा गया है कि जनवरी-97 की अन्तिम तिमाही में याचिकाकर्ता ने अपनी बिक्री कीमत को कम करके *** कर दिया जबकि उनकी उत्पाद लागत *** थी। इस प्रकार इस अवधि के दौरान उन्हें *** की हानि हुई।

जाँच अवधि के दौरान लाभ/हानि और औसत बिक्री कीमत का विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है।



69.5 मैसर्स वेलमैन इनकैडेसंट इण्डिया ने कहा है कि चीन से आयात के कारण मजबूर होकर उन्हें औद्योगिक वित्त एवं पुनर्गठन ब्यूरो (बी.आई.एफ.आर.) के पास पंजीकरण की मांग करनी पड़ी है, क्योंकि सकल हानि के कारण उनकी निवल पूंजी में हास हो गया है। बी.आई.एफ.आर. ने 5-5-98 को एक आदेश निकाला है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि कम्पनी द्वारा दिए गए कारणों में से एक कारण चीन से वस्तुओं का पाटन किया जाना है। यह भी देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने अप्रैल, 1997 से अपनी क्षमता का 1/3 भाग बंद कर दिया है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि मै. गुजरात एन आर ई कोक का क्षमता उपयोग 1996-97 में केवल 50.8 % था। इसी प्रकार मै. वेलमैन इनकैडेसंट इण्डिया ने अपने क्षमता उपयोग में गिरावट दर्शाई है, जो वर्ष 1995-96 के 63.65% से घटकर 1996-97 में 61.90% रह गया। इसके अलावा, ग्राहकों द्वारा आर्डर वापस ले लिए जाने के कारण उन्हें अपने संयंत्र को फिर बंद करना पड़ा जिससे भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

69.6 क्लोजिंग स्टॉक में वृद्धि :—याचिकाकर्ता के मेटकोक के क्लोजिंग स्टॉक में काफी वृद्धि हुई है जो कि निम्नानुसार है:—

वर्ष	कोक का स्टॉक(एम.टी)
1993-94	1215
1994-95	3051
1995-96	13861
1996-97	13150

69.7 घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग:—यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता का क्षमता उपयोग निम्नानुसार है:—

वर्ष	क्षमता उपयोग
1994-95	62.51%
1995-96	82.76%
1996-97	85.24%

69.8 कार्मिकों की छंटनी—रोजगार में लगे लोगों की संख्या में कमी हुई है और उद्योग ने अपनी उत्पादन क्षमता के बंद होने के कारण 1996-97 में 296 कार्मिकों तथा 1997-98 में 295 कार्मिकों की छंटनी की है।

ज. क्षति के संबंध में निष्कर्ष और कारणात्मक संबंध

70. परिस्थितियों की मांग है कि चीन से कोक के आयात के बारे में क्षति पर विचार किया जाए। पिछले वर्षों में समग्र रूप में चीन से

मेटकोक के आयात में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। चीन से मेटकोक के निर्यात के कारण घरेलू उद्योग को अपने मेटकोक की कीमत गैरलाभप्रद स्तर पर रखनी पड़ी और घरेलू उद्योग को अपनी उचित बिक्री कीमत की वसूली करने से रोका जिसके परिणामस्वरूप लाभ में गिरावट आई/हानि हुई। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न संकेतक जैसे औसत बिक्री प्राप्ति स्टॉक, लाभ में गिरावट/हानि सामूहिक तथा संचयी रूप से यह दर्शाते हैं कि “घरेलू उद्योग” को वास्तविक क्षति हुई है।

71. यह प्रमाणित करने के लिए कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति चीन से आयातों के कारण हुई है प्राधिकारी ने विचार किया है कि चीन से मेटकोक के निर्यात के कारण घरेलू उद्योग को अपनी कीमत को अलाभकारी स्तर पर रखना पड़ा और इसकी उचित कीमत वसूल करने से रोका, जिसके परिणामस्वरूप लाभ में कमी हुई/हानि हुई।

झ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

72. पाटन-रोधी शुल्क ऐसे पाटन को रोकने के लिए लगाए जाते हैं, जो कि घरेलू उद्योग की क्षति पहुँचाते हैं, जिससे कि घरेलू बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनः स्थापना हो सके। इसका उद्देश्य पाटन की प्रक्रिया की अवन्ति को रोकना है। ऐसे शुल्कों के लगाए जाने से संदर्भाधीन देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और न ही उनसे उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा। सामान्यतः, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में पाटन रोधी उपायों के कारण कमी नहीं आएगी, विशेषकर तब जब पाटनरोधी शुल्क को ऐसी राशि तक सीमित रखा जाए जो कि घरेलू उद्योग की क्षति में सुधार लाने के लिए आवश्यक है।

73. किन्तु, इस बात को स्वीकार किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संदर्भाधीन वस्तुओं का उपयोग करके उत्पादित किए गए उत्पादों के मूल्य, स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है तथा उसके परिणाम स्वरूप ऐसे उत्पादों का उत्पादन करने वाले उद्योगों की या ऐसे उत्पादों की सापेक्षिक प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव पड़ सकता है।

74. पाटनरोधी जाँच में प्राधिकारी को स्पष्ट रूप से पाटन के अस्तित्व, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और संदर्भाधीन देश से किए गए आयातों के साथ ऐसी क्षति का कारणात्मक संबंध प्रमाणित करने के लिए जाँच करनी होती है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर किसी अन्य उद्योग की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाला प्रभाव प्राधिकारी की जाँच के दायरे से बाहर है।

75. इसलिए, चीन जनवादी गणराज्य से मेटकोक के आयात के बारे में ऐसी जाँच के दौरान प्राधिकारी के ध्यान में लायी गई कुछ सूचना जो कि कथित रूप से भारतीय लोहा और इस्पात उद्योग को प्रभावित करती है, उस पर प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से टिप्पणी नहीं की गई है या ध्यान नहीं दिया गया है। प्राधिकारी ने केवल चीन पी आर से मेटकोक के आयात और पाटन पर इसके प्रभाव, समान वस्तु के भारतीय उत्पादकों को वास्तविक क्षति पर ध्यान दिया है और तदनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

76. उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों और अन्य के द्वारा प्राधिकारी के समक्ष रखी गई सूचना का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(अ) “घरेलू उद्योग” में समान वस्तु के उत्पादक भारत में प्रयोक्ता उद्योग की एलएएमसी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे।

(ब) एलएएमसी ऐसा मूल कच्चा माल है जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विस्तृत उपभोग पिंग आयरन उद्योग, एसएस आयरन कास्टिंग

उद्योग, फैरी एलायज उद्योग गुम्बज वाले ढलाई चरों तथा मूल धातु उद्योग विशेषकर जिंक द्वारा किया जाता है। ये उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के अभ्यन्तर क्षेत्र में बुनियादी कच्चे माल का महत्वपूर्ण रूप से मूल्यवर्धन करते हैं, निर्यात आय में योगदान करते हैं, काफी मात्रा में रोजगार प्रदान करते हैं और विभिन्न प्रकार की अवस्थापना एवं टिकाऊ उपभोग्यता सामग्री के लिए निविष्टियों की आवश्यकता पूरी करते हैं। उच्च शुल्क लगाए जाने से ये उद्योग और संबद्ध उद्योग क्षेत्र मंहगे और गैर-प्रतिस्पर्धी हो जायेंगे। इस्पात मंत्रालय भारत सरकार ने भी इस विचार का समर्थन किया है।

(स) पिग आयरन उद्योग का अपने आप में 3000 करोड़ रुपये का निवेश है और 1140 करोड़ रु० का निवेश करने की प्रक्रिया चल रही है। आई०डी०बी०आई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई और यूटीआई से बहुत ज्यादा निवेश किया गया है। इस्पात मंत्रालय ने पिग आयरन उद्योग की स्थापना का समर्थन किया है और पिग आयरन के निवल आयातकों की स्थिति से भारत इस समय 3 मिलियन मी०टन पिग आयरन का उत्पादन करता है और 1997-98 में इसने 140 मिलियन यू०एस डालर मूल्य के 1 मिलियन मी०टन पिग आयरन का निर्यात किया है। यह उद्योग सीधे ही 30,000 लोगों को रोजगार देता है।

(द) एसएस लोहा ढलाई उद्योग ने 1997-98 में 160 मिलियन यूएस डालर मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया है।

(च) लगाए गए अनन्तिम शुल्कों के कारण लघु धमन भट्टियां बंद हो गईं और ऐसे शुल्कों से पिग आयरन उद्योग को अपूरणीय क्षति होगी। इसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग को मेटकोक के बदले पिग आयरन का आयात करना होगा।

77. प्राधिकारी ने पहले ही यह टिप्पणी की है कि लोहा और इस्पात उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिवेदनों के बारे में जाँच करना चीन जनवादी गणराज्य से एलएएमसी से संबंधित पाटनरोधी जाँच के दायरे में नहीं है।

78. किन्तु, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत की मेटकोक की पूरी आवश्यकता निम्नांकित हद तक आयातों (डीजीसीआई एण्ड एस के आंकड़ों के अनुसार) से पूरी की गई :-

1996-97 में	10,04,573 मी० टन
1997-98 में	20,15,169 मी० टन

79. इस आदेश के पैरा 30 के अनुसार परिभाषित घरेलू उद्योग 1996-97 में 2,40,245 मी० टन का उत्पादन करके इस आवश्यकता का 19.42% पूरा कर सका। घरेलू उद्योग की कुल स्थापित क्षमता 4,08,000 मी० टन है और पूर्ण क्षमता उपयोग होने पर भी ये आयात के 1997-98 के आंकड़ों के अनुसार उद्योग की आवश्यकता का 20.25% ही पूरा कर पाएंगे। कोयले का आयात एलएएमसी के उत्पादन के लिए आस्ट्रेलिया, चीन जनवादी गणराज्य तथा अन्य देशों से किया जाता है। इस उद्योग में कुल निवेश करीब-करीब 100 करोड़ रु० से थोड़ा ज्यादा है और इसमें करीब 2100 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यह उद्योग केवल घरेलू बाजार की मांग को पूरा करता है और अपने उत्पाद का निर्यात नहीं करता है। उत्पादन जो कि प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है और 1996-97 में स्थापित क्षमता का करीब 60% रहा।

80. अन्तिम जाँच-परिणाम

उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि आई०सी०ए० के सदस्य 15% से कम राख की मात्रा वाले मेटकोक का उत्पादन कर सकते हैं, प्राधिकारी निर्यातकों/आयातकों के साथ सहमत होने के लिए प्रवृत्त हैं कि 15% या उससे कम राख की मात्रा वाला मेटकोक ही चीन जनवादी गणराज्य से आयातित मेटकोक के समान वस्तु है।

* प्रारम्भिक कार्रवाई शुरू करने के समय प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रारम्भिक कार्रवाई शुरू करने के समय याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायार करने का पात्र था। "समान वस्तु", जैसा कि प्रारम्भिक जाँच-परिणाम से परिभाषित किया गया है, उसके क्षेत्र पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता ने प्रारम्भिक जाँच-परिणाम के साथ पात्रता के मानदण्ड को पूरा किया। अब याचिकाकर्ता को ऐसे 100% उत्पादकों का समर्थन प्राप्त है, जिनका उत्पादन "समान वस्तु" की श्रेणी में आता है।

* प्राधिकारी ने सूचना के लिए विशेष अनुरोध करने के बावजूद चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा अपूर्ण तथा अपर्याप्त उत्तर को देखते हुए चीन जनवादी गणराज्य में मेटकोक के सामान्य मूल्य का निर्धारण सहयोगी निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया है।

* चीन जनवादी गणराज्य के उद्गम वाले या वहाँ से निर्यात किए गए मेटकोक का भारत में निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है।

* घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

* संदर्भाधीन देशों के उद्गम वाले या वहाँ से निर्यातित निर्यात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

81. प्राधिकारी, पाटन-रोधी शुल्क लगाने के संबंध में प्रारम्भिक जाँच-परिणाम की पुष्टि करते हैं और चीन जनवादी गणराज्य के उद्गम वाले या वहाँ से निर्यात किए गए धातुकर्मीय कोक के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। यह पाटन-रोधी शुल्क और प्रति मी० टन आयात की पहुँच कीमत का अन्तर होगा।

82. इस प्रयोजन के लिए आपातों की पहुँच कीमत वह आकलन योग्य कीमत होगी जिसका निर्धारण सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत किया जाएगा तथा जिसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 और 3ए के अन्तर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क शामिल होंगे।

83. उपर्युक्त शर्तों के अधीन प्राधिकारी 20-3-1998 के प्रारम्भिक जाँच-परिणाम की पुष्टि करते हैं।

84. इस आदेश के खिलाफ अपील उक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, आबकारी एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपील ट्रिब्यूनल के पास की जा सकेगी।

रति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th August, 1998

FINAL FINDINGS

Sub: Anti-dumping investigation concerning import of Metallurgical Coke from the People's Republic of China – Final Findings

8/2/97-ADD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for determination of Injury) Rules, 1995 thereof.

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed subsequent to the preliminary findings:
 - 1.1. The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified preliminary findings vide notification dated the 20.3.98 with regard to anti-dumping investigations concerning imports of metallurgical coke (also referred to as metcoke and coke hereinafter) from the People's Republic of China (also referred to as China and China PR hereinafter), and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;
 - 1.2. The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to the known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days of the date of the letter;
 - 1.3. The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassy of the People's Republic of China in New Delhi with a request that the exporters and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings;
 - 1.4. The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 8.6.98. All parties presenting views orally were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any;
 - 1.5. The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted and arguments made by various interested parties. All parties who made request for inspection, in writing, were allowed to inspect the public file;
 - 1.6. Arguments raised by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated herein for sake of brevity. However, the arguments raised by the interested parties have been appropriately dealt in the preliminary findings and/or these findings;
 - 1.7. In accordance with Rule 16 of the Rules Supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on same has been duly considered in these findings;
 - 1.8. **** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
2. The following abbreviations have been used:

Metcoke/Coke	Metallurgical coke
PIMA	Pig Iron Manufacturers Association
China PR/China	The People's Republic of China
Authority	Designated Authority
MBF	Mini Blast Furnace
ICA	Industries and Commerce Association, Dhanbad
LAMC	Low Ash Metallurgical Coke
PMI	the Permanent Mission of India In Geneva
CPA	Certified Public Accountant

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

- The product under the scope of the present investigation is Metallurgical Coke (also referred to as metcoke).
- Metallurgical Coke is produced by destructive distillation of Metallurgical (coking coal) in the absence of oxygen at high temperature generally ranging around 1000 degrees centigrade without burning the coal. The Metallurgical Coke produced is mainly carbon along with some mineral and residual volatile material. The metcoke is used as a primary fuel in industries where a uniform and high temperature is required in kilns or furnaces.
- Metallurgical Coke is classified under Chapter 27 (under sub-heading 27.04) of the Customs Tariff Act 1975. The classification, manufacturing process and usage of the product indicated herein are, however, indicative only and are in no way binding on the scope of the product under consideration.
- Metcoke is used in various industries including pig iron, foundries, ferro alloys, chemical, integrated steel plants and others.
- It has been argued by the importers that the product under consideration at the time of initiation of investigation was "Metallurgical coke made out of low ash coal" but the product described in preliminary findings is "Metallurgical Coke" and thus the Authority has enlarged the scope of investigation. However, it can be seen that all interested parties to the investigation have all throughout agreed that the Chinese coke alleged to have been dumped into India has low ash content. The Authority, therefore, considers that there is no enlargement of the scope of the investigations and all metallurgical coke originating in or exported from China PR is covered under the scope of the present investigations.

C. LIKE ARTICLE

- Views of the Petitioners: The submissions of the petitioners with regard to the issue of "like article" are as follows:

8.1. The domestic uses of metcoke and industry specifications are as under:-

(a) Pig Iron	Ash content 18-30%
(b) Foundries	Upto 40% ash
(c) Ferro Alloys	Low sulphur, low phosphorous
(d) Chemicals	Upto 38% ash
(e) Other	Coke of any ash content

- The metcoke manufactured is directly dependent on the type of coal used as input. Depending on the requirement of user industry coal is suitably blended prior to using it as an input in the process of manufacture. Indian coal which typically has a higher ash content, is very low in sulphur and phosphorous. On the other hand, imported coal has very low ash content. Metcoke is used in several industries ranging from the steel mills to non-industrial use and domestic use for generation of heat. Depending on the eventual use and the special requirement of each individual user metcoke can be and is specifically manufactured. Although Indian coal, contain high percentage of ash,

there are several billion tonnes of low ash coal in India. Chari Committee report states the total coal reserves are in excess of 27 billion tonnes.

- 8.3. The production process for high ash coke or low ash coke is identical notwithstanding the type of coal used. Indian coke manufacturers can even convert imported coal for specific industry in their existing plants without any modification. There is no restriction, technical or otherwise to manufacture coke in India using imported coal. Therefore, prima-facie, it is erroneous and misleading to state that coke produced in China is not identical to coke produced in India. The petitioner has quoted the case of NBR wherein it was held that although identical grades of NBR were not being manufactured in India, there were no restrictions in manufacturing the same. Indian plants are fully capable of manufacturing coke with imported coal and this is in fact being done at several plants all over India.
- 8.4. Indian coke and Chinese coke are used interchangeably. The argument of the pig iron manufacturing association that Indian coke is unsuitable for their plants is factually incorrect. Even Steel Ministry has stated that indigenous coke manufactures will need to be encouraged to meet the domestic demand generated by new Mini Blast Furnaces (MBF) which are coming up in India. Thus Indian raw material is to be used in the manufacture of pig iron in India.
- 8.5. Tata Korf is the pre-dominant technology used by nearly 90% of pig iron plants in India. In 1989, Tata Korf presented a paper stating that MBF can use medium grade coking coal with ash content up to 30% and coking coal with ash content of 30% will produce coke with ash content between 40% to 45%. The paper also states that coke can be imported or could be produced in India using imported coal. Alternatively, this better quality coke can be mixed with coke from Indian source. However the cost of imported coal/coke is more expensive and will increase the overall cost of production of pig iron. Indian ore contain 66.5% iron. In order to obtain sufficient 'slag and flow' approximately 18% ash is required. Since Chinese coke has less ash than Indian coke, Indian pig iron manufactures are compelled to add quartzite (a form of ash) in the process of manufacture.
- 8.6. Indian met coke is having characteristics closely resembling to the metcoke from China and hence coke imported from China is a "like article" to Indian metcoke and it is "commercially and technically" substitutable.
- 8.7. The petitioner has argued that factors which compare Indian coke with Chinese coke are:
 - Physical Characteristics (size, chemical composition and raw material)
 - Manufacturing process and technology
 - Function and uses
 - Product specification
 - Pricing, distribution and marketing
 - Substitutability
- 8.8. Many of the consumers from foundries, pig iron producers, chemical producers, ferro-alloy producers, and other industrial and non-industrial users have been procuring metcoke from ICA (Industries and Commerce Association) members in the past. They have shifted to Chinese coke because it is being dumped. The argument of PIMA that "it is technologically and commercially not suitable to use high ash coke in the blast furnace" is incorrect as the ash in the coke of the steel plants of SAIL ranges from 20-25%. The true and correct determining factor of the "like article" is as to whether the article produced by domestic industry "has characteristics closely resembling to the dumped article" i.e. whether the article produced by domestic industry has been and/or can "technically and commercially substitutable" to the dumped article and, conversely, whether the dumped article has "technically and commercially substituted" the articles produced by the domestic industry. The fact that the dumped article is of better quality than the one produced by domestic industry is not relevant and can not be the basis for

determining whether the produce of the domestic industry is "like article". The replacement and/or substitution of metcoke is a result of dumping and is not done for quality purpose but for price purpose.

9. Views of the Exporters/Importers: The views of the exporters/importers and other parties are as under:

9.1. Two qualities of Metcoke are produced in India:

- (i) Metcoke made of imported coking coal, and
- (ii) Metcoke made of Indian coking coal.

9.2. Metcoke produced from Indian coking coal is not comparable to metcoke produced from imported coking coal or imported metcoke. The distinguishing factor in the metcoke manufactured from Indian coking coal and imported coking coal or imported metcoke is the ash content. The coke produced out of Indian coking coal is appropriately termed as High Ash Metcoke (HAMC) whereas the coke produced out of imported coking coal or imported metcoke is termed as Low Ash Metcoke (LAMC). The physical and chemical properties of the two types of coke are as under:-

	Quality of metcoke produced from Indian coking coal	Quality of imported metcoke/metcoke made from imported coking coal
Moisture	5-15%	< 5%
Ash	29-40%	12-14%
Volatile matter	2-4.5%	<1.6%
Fixed Carbon	52-65%	84-88%
Sulphur	1% Max	< 0.6% Max
Phosphorus	0.30%	0.03%
M 40	70-75%	80% Minimum
M 10	10-15%	8% Maximum
Ash fusion temp	1240 °C Max	1350 °C Minimum

9.3. Due to these different chemical properties the two type of coke are not comparable and hence can not be termed as like articles.

9.4. The petitioner is claiming that while the coal used in China and that used in India are not identical, there is no restriction to manufacture coke in India using imported coal. However, this argument has no relevance whatsoever to the question whether the metcoke with ash content up to 15% imported from China is a like or not like article to metcoke produced by ICA, which has an ash content of 27-40%. The issue is not whether the ICA member could manufacture metcoke with low ash content from imported coal but whether the coke manufactured by them from high ash Indian coke could be used as a substitute to low ash coke in Mini Blast Furnaces (MBFs). The petitioner had relied on a paper presented by Tata Korf Engg. Services Ltd. in Sept 1989 stating that MBF can use medium grade coking coal with ash content up to 30%. However, the importers in response have submitted a letter from Tata Korf Engineering Services Ltd. that ash content in the coke for use in MBF should be limited to about 12%. One of the reasons for difference in opinion in 1989 and in 1998 given by M/s Tata Korf for non-suitability of high ash coke is that Tata Korf had no experience of operating Mini Blast Furnace in India and now they are recommending coke with ash content of about 13%. Tata Korf Engineering Services Ltd., has further stated that they have designed its mini blast furnaces to operate with technical parameters with respect to coke rate, productivity, slag volumes etc. whereby the process will be technically and economically viable and can produce hot metal of suitable grade. These plants are designed basically for cost effective technology for which it is essential to use LAMC having the following parameters:-

- The coke ash should be limited to about 13%.
- The volatile matter of coke should be around 1%.
- CRI value should be between 20-29%.

- CSR should be between 58-64%.
- M¹⁰ value should be 8% Maximum.
- M⁴⁰ value should be 80% Minimum.
- Sulphur content of coke should be around 0.4 to 0.5%
- Phosphorous content should be less than 0.035%.

9.5. Due to extremely high consumption of high ash indigenous coke in the mini blast furnace, the cost of hot metal will be high. Tata Korf has now recommended that only LAMC be used in Tata Korf mini blast furnace. Tata Korf has further stated that the technical paper which was presented by Tata Korf in 1989 and which talks of suitability of indigenous high ash coke made from indigenous coking coal having high ash content for pig iron manufacture, was presented when Tata Korf had no experience of an operating mini blast furnace in India. The first Tata Korf mini blast furnace was based on operation of the mini blast furnaces of very small sizes having very low capital cost in Brazil with Brazilian iron ore where most of the mini blast furnaces were operating on charcoal. There were no operating data available at that time on the performance of MBFs with high ash indigenous coke. Till date, Tata Korf has designed 15 mini blast furnaces in India, 13 of which are under operation. With the experience gained during 1992 to 1998, it is recommended use of only low ash metallurgical coke for Tata Korf mini blast furnaces as the use of indigenous high ash coke will increase the slag volume to such an extent that hearth design will require change and a slag notch will also have to be provided to drain only extra slag. The heavy amount of slag will bring down the hot metal temperature which may not be suitable for further treatment and subsequent conversion into quality products. Further, the productivity of the furnace with the use of high ash indigenous coke will come down substantially (reduction of productivity of 2% for every 1% increase in ash content) to a level which in no way can be compared with the present productivity levels of 1.5 – 2.0 t/m³/d being achieved by the various Tata Korf mini blast furnaces in India. The productivity levels would be even higher when operating with agglomerates like sinter or pellets. Also the high ash coke will lead to very high coke rate (increase of 2% coke rate for every 1% increase in ash content) in the blast furnace. The quality of hot metal will be poorer with the use of high ash coke with regard to temperature, phosphorous content. Cost of indigenous high ash coke on fixed carbon basis is not proportionate to the cost of imported low ash coke also on fixed carbon basis. Therefore, due to extremely high consumption of high ash indigenous coke in the mini blast furnace, the cost of hot metal will be exorbitantly high. It may be noted that the integrated steel plants are also using imported coal with much lower ash content to produce blast furnace coke and not directly using 100% indigenous high ash coke in their burden. All the above factors will result in a totally unviable mini blast furnace operation leading to closure of the mini blast furnaces in India. The capital cost of Tata Korf mini blast furnaces designed in India, based on actual experience, is much higher than anticipated earlier and as compared to the Brazilian mini blast furnaces due to additional features such as slag granulation system, power plants, etc. Therefore, Tata Korf built the mini blast furnaces only for imported coke operation.

9.6. Quartzite is not being added in the burden in the mini blast furnace operating on low ash imported coke and producing basic grade low silicon iron for steel making. Small amount of quartzite is added by these MBF operators who are producing very high silicon (2.0 – 3.0%) pig iron for foundries. It would be appropriate to mention here that quartzite is not 'a form of ash' and function wise quartzite cannot be substituted by the silica contained in the ash of the coke. The addition of quartzite is necessary to produce high silicon foundry grade iron since quartzite is pure form of silica (above 97% SiO₂) which has better mechanism of silicon transfer to hot metal inside the blast furnace. Quartzite plays an important role in maintaining the bosh slag (primary slag) basicity. The silica of quartzite combines with CaO to form the primary slag at the bosh region. Whereas, if high ash coke is used, the SiO₂ of coke ash is released only in the tuyere region, thus making the bosh slag viscous, which hinders in blast flow through the burden. Silicon transfer to hot metal cannot be easily achieved through the use of high ash coke which on the other hand brings adverse effects on productivity, coke rate, slag volume, etc. Moreover, high ash coke will lead to higher alumina input,

thereby making the slag viscous. To take care of such a situation, more silica in the form of quartzite needs to be added. This calls for high requirement of fluxes and consequently higher slag volume, which can be encountered by combustion of more coke to keep the slag molten. Obviously this has compounding effect on unfavourable coke rate, slag volume and productivity. In view of the above it has been recommended that only low ash metallurgical coke is used in Tata Korf mini blast furnaces.

- 9.7. Thus it is argued that for use in MBFs, the high ash content coke produced by is not substitutable with Chinese low ash coke. Thus high ash coke produced by some members of ICA is not a like product to low ash coke imported from China and hence the producers of high ash coke should be excluded for evaluating material injury and for determination of standing.
- 9.8. The petitioner argument that in order to obtain sufficient "slag and flow" in the manufacturing process, approximately 18% ash is required. Since Chinese coke has less ash than Indian coke, pig iron manufacturers are compelled to use quartzite (a form of ash) in their manufacturing process. However the importers have argued that this assertion of the petitioner is misconceived and erroneous as quartzite is added not for the purpose of increasing the slag and flow but for the purpose of reduction of high alumina content in the blast furnace slag while producing pig iron using iron ore mined in India.
- 9.9. The petitioner has argued that metcoke with ash content higher than 20% has been purchased from them by those who produce pig iron, ferro-alloys, chemical and other industries. It is argued by the importer that such purchase orders were placed between August 1993 and Sep '95 and not during 1996-97. The only order during the period of investigation was of Wellman for low ash coke which, however, is a like product to the allegedly dumped coke from China. Petitioner has given reference to purchase orders and it is not clear whether such purchase orders were executed or not. Some of such purchases were on trial basis and since high ash content metcoke was found unsuitable during trial, it was given up. The supplier of low ash coke are not able to supply in the desired quantities. A number of members of Pig Iron Manufacturers Association, ferro alloy producers, steel furnace association had explored the feasibility of obtaining low ash coke from members of ICA. All their efforts have failed as none of the coke producers of ICA was in a position to supply coke of the required quality and specifications. Thus the purchases of coke with 20% wastage were on trial basis and as they did not yield the required results, they were blended with coke of low ash. However, further purchases of high ash content coke have completely stopped. The contention of the petitioners that high ash content coke can be used in MBFs is therefore technically and factually incorrect. Also such purchases were much prior to the period of investigation. Some small quantities were taken from ICA to meet exigencies and that too mostly on conversions basis by making available low ash content coal.
- 9.10. Hindustan Zinc Ltd. has stated that for their plant, coke is an essential & most critical input. Quality of coke is very important for the operation and it directly affects economics of plant due to increased slag production in case of high ash coke.
- 9.11. In the input output norms published by Ministry of Commerce for production of pig iron (blast furnace route) one of the input shown is low ash metallurgical coke (with ash content below 15%). Thus metcoke with ash content of 27-40% is not a like article to metcoke imported. The high ash content coke produced by Indian coke producers hampers productivity, increases the rate of consumption with cascading effect on cost of production. The viability of MBF operation is based on the presumption that high quality of Chinese coke would be available at economic prices.
- 9.12. When the petitioner themselves are distinguishing these two products i.e., low ash metcoke and high ash metcoke, how the Designated Authority has come to the conclusion that the products are substitutable both technically and commercially. Where an identical article which is alike in all respect with the article under investigation

exists, it will constitute like article. There are manufacturers of metcoke in India who produce LAMC out of imported coal. Such LAMC is identical in all respect and thus it will constitute a like article. If such article was not being manufactured in India, then the Authority should look for whether the article produced by domestic industry is having characteristics closely resembling those under investigation. Thus the product produced by ICA, Dhanbad should be excluded.

- 9.13. Also the domestic coke produced by petitioners have high level of sulphur and phosphorous content which are not suitable for efficient blast furnace operations. The metcoke imported from China contain about 0.035% of phosphorus whereas the coke out of Indian coal contains about 0.26%. Due to extremely high percentage of ash and phosphorous in the coke manufactured in India out of Indian coal, it is not all capable of being used for various industrial applications where LAMC with very low phosphorous content is required.
- 9.14. In the opinion of experts in blast furnace technology, the coke produced from W3 & W4 grades of coal supplied to the cokeries in Dhanbad region is neither suitable nor economical due to heterogeneous in composition, inferiority and inconsistent quality. Due to lower temperature of carbonisation, the coke produced from such coal does not possess the required physical strength for use in blast furnace. Due to poor quality of indigenous coal, SAIL & RINL went in for large scale import of low ash coal to produce the desired quality of coke in blast furnace.
- 9.15. LAMC is a different commercial commodity as compared to high ash metcoke and these two are known dealt, treated and regarded in the market as distinct commercial product. Even Ministry of Commerce has indicated while issuing licence regarding the Ash content as "ash content not excluding 15%". Ministry of Finance has also all along recognised the said difference with reference to the percentage of ash as well as with percentage of phosphorous. The function, industries in which there are used, are different in both type of coke and hence they can not be termed as like article. The coke manufactured by ICA has ash content of 28-40% and 0.26% or more of phosphorous and it is simply not possible and feasible to use the said coke as a substitute to LAMC imported from China. The coke produced in India from indigenous coal is of poor quality and pig iron can not use indigenous coke as their technologies do not permit it as it has ash content of 20-40% as against imported Chinese coke which has ash content of 12-15%. If pig iron producers are forced to use this coke, it will result in increased consumption at 1000 kg per tonne of pig iron as against the standard norm of 800 kg per tonne in the case of low ash imported coke. Thus it involves an extra cost of production and the industry can not afford it. Besides use of indigenous coke will hamper productivity of blast furnace and erode their efficiency.
- 9.16. The ferro alloys industry has stated that the coke required for ferro alloys industry has a different specification. They require coke only in the size range of 10-30 mm and with a phosphorus content not exceeding 0.0166%. The coke produced from Indian coal has a phosphorous content of 0.15% and it can not at all be used by the ferro alloys produced. The coke produced by ICA Dhanbad is neither suitable for pig iron manufacturers because of ash content nor suitable for ferro alloys producers because of high ash and phosphorus content. The local ferro alloys industry require low ash, low phosphorous, low sulphur metcoke having stringent sufficient specification which is not available from indigenous sources. Manufacture of ferro alloys is a continuous process and as such the plant has to be operated continuously without any interruption and stoppage. For this, the industry has to import low phosphorus, low ash low sulphur metcoke from China as the indigenous metcoke can not be used.

EXAMINATION OF THE ISSUES RAISED ON "LIKE ARTICLE"

10. As per Rule 2(d), "Like Article" has been defined as under:-

"Like article" means an article which is identical or alike in all respect to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article

which although not alike in all respect, has characteristics closely resembling to those articles under investigation."

11. With regard to the issue of "like article", it has been contended by the exporters and the importers that the metcoke produced by the Industries and Commerce Association (ICA) has very high ash content and, therefore, the same cannot be called as a like article to the metcoke imported from China. It has also been mentioned that the other technical specifications are also different to an extent that the user industries cannot substitute the Chinese coke with the metcoke produced by ICA.
12. On the other hand, detailed representations have been made by the petitioners that the two products are technically and commercially substitutable and therefore like articles within the scope of the definition. The Authority, however, observes that both the petitioner industries as well as the importers and exporters have agreed that one of the main features of metcoke is its ash content. Coke made out of Indian coal has high ash content ranging from 20% to 40%, while the coke made out of imported coal and the imported coke by themselves have low ash content. Therefore, it is the admitted position from both sides that metcoke can be broadly divided into two categories namely, coke produced from Indian coal and imported coke/coke produced from imported coal. In fact, the Authority observes that PIMA has, in its written submissions, also made the above categorisation.
13. The Authority also observes that the production process for both the above categories is same and the ash content of the metcoke depends upon the blend of the coal used for the purpose. Blending of different varieties of coal is done to arrive at the desired level of ash content in the finished product i.e. metcoke. The Authority observes that there have been instances where the blast furnaces have used the high ash content metcoke also even though they have mainly preferred to use the imported Chinese coke with low ash content. The claims made by the domestic industry that the pig iron manufacturers were using coke made from Indian coal in the past, particularly in the period prior to 1992, remains uncontroverted.
14. In view of the above, the Authority concludes that there is considerable evidence to suggest that the variation in the technical composition, particularly the ash content, does not make it technically impossible for all the user industries to use the high ash content metcoke. The argument that the user industry has not placed any orders during the period of investigation does not have any bearing on the aspect of technical substitutability of the Indian metcoke with the Chinese metcoke. Even the opinion of the technical experts does not categorically state that the substitution of the two categories of metcoke is not possible. The opinions expressed by the experts merely indicate that use of high ash content metcoke in the production of pig iron will lead to high slag generation etc., and that the commercial viability of the MBFs is entirely dependant upon the use of low ash content Chinese metcoke. The Authority observes that for determining the "like article", it is the substitutability which is of paramount importance and not the actual substitution, the latter may be a relevant factor from the injury point of view.
15. Some user industry groups like manufacturers of ductile iron pipes, ferro alloys have indicated that the metcoke required by them has to have some other physical as well as chemical properties. For instance, it has been indicated by the ductile iron pipes industry that the phosphorus content in the metcoke required by them should be less than 0.035%. While it is appreciated that certain industries may have special requirements, anti-dumping rules do not permit analysis on the basis of specific end users when there is a high degree of substitution possible among different types of user industries. The Authority therefore is not in a position to make any separate categorisation for users with special requirements.
16. In view of the above, the Authority holds that even though the members of ICA mainly produce metcoke which is not substitutable to the low ash content metcoke for some uses, these producers are capable of manufacturing low ash content metcoke depending upon the quality and source of coal used by them. However, it is also observed that the members of ICA had not produced significant quantities of low ash content metcoke either from good quality Indian coal or from imported coal. However, the petitioner BLA Industries Ltd. has

produced significant quantities of Low Ash Content Metcoke for a specific segment of end users in the domestic market.

17. The Authority, therefore, holds that it is only the production of low ash content metcoke which is "like article" to the imported Chinese coke. The contention of the exporter/importers that high ash content metcoke should not be considered as like articles, has considerable force and is accepted in view of the facts and circumstances of the case.
18. In addition to the above, the Authority also observes that the standard input-output norms of the Directorate General of Foreign Trade wherein for production of pig iron (blast furnaces), one of the inputs shown is low ash content metcoke (with ash content below 15%). The Authority is inclined to agree with the exporters/importers that only metcoke with ash content of 15% and below, irrespective of its producer in India, is a "like article" to the imported Chinese coke. The Authority, therefore, concludes that metcoke with an ash content of 15% and below, irrespective of its producer in India is a "like article" to the imported Chinese coke.

D. DOMESTIC INDUSTRY

19. Petitioners' Views

The views of the petitioners are as follows:

- 19.1. The petitioner has submitted that domestic manufacturer of metcoke comprises of the following:
 - Tata Iron and Steel Co Ltd. (TISCO)
 - Steel Authority of India (SAIL)
 - Bharat coking coal Ltd., (BCCL)
 - Rashtriya Ispat Nigam Ltd., (RINL)
 - Durgapur Project Ltd., (DPL)
 - Wellman Incandescent Ltd. (Wellman)
 - BLA Industries Ltd., (BLA)
 - Southern Fuels Ltd. (Southern)
 - Fertilizer Corpn. of India (FCI)
 - Sesa Goa (Sesa)
 - Usha Udyog (Usha)
 - Gujarat NRE Coke (Gujarat NRE)
 - Industries and Commerce Association (ICA)
- 19.2. TISCO, Sesa Goa, Usha Udyog, SAIL should be excluded on the ground that they either directly or through related companies have imported metcoke to India during period of investigation. Further RINL is related to SAIL as it is under the administrative control of Steel Ministry and thus is "related to SAIL under the definition of "Related" as contained in the WTO agreement on anti-dumping duty. Both of them are directly controlled by a third person i.e., Ministry of Steel and hence related. It is submitted that RINL be excluded on the basis of relationship with SAIL. RINL first supported the petition, then withdrew their support and remained neutral, and subsequently opposed the imposition of anti-dumping duty. These changes has been brought about by the pressure exerted by the Steel Ministry. Had the Steel Ministry not been the common shareholder with administrative control of SAIL and RINL, RINL would not have withdrawn their support and begun to oppose the imposition of anti-dumping duty.
- 19.3. RINL must also be excluded from the domestic industry as their production is consumed internally within their process of production and negligible amount reaches the merchant market. Under the proviso to Rule 2(b) read with Rule 11(3); the producers who produce and market metcoke and those who produce and captive consume, constitute two competitive markets and each one of them must be treated as a separate domestic industry. Since RINL is a consumer of metcoke and its produces metcoke for its captive consumption it is an intermediary product and not as an end product for the purpose of excise duty or sales tax or any other

purpose. Further the exclusion of captive consumption is common in GATT practice world over.

- 19.4. Considering above point, BLA Industries Ltd. and ICA constitute 45% at the time of initiation and at present express support for the petition is 67.81%. The statutory requirement of locus standi in respect of Domestic Industry have been fully complied with.
- 19.5. The repeated argument of the importer/exporter that WTO has clarified to the Ministry of Commerce in 1994, that for standing purpose only captive production must be included in the purview of domestic industry has never been substantiated. There is no question of "WTO" having issued any clarification to any query pertaining to the technical aspect of dealing with "captive production" unless all member states give assent to such a clarification.
20. Views of the Importers: The views of importers on Standing of Domestic Industry are as follows:
 - 20.1. The Authority has not taken into account the production of metcoke by Rashtriya Ispat Nigam Ltd. (RINL) even though it had been brought to the notice of Authority about the clarification issued by WTO that production, predominately for captive consumption should be taken into account for the purpose of determining the standing of petitioner. With reference to WTO clarification, for the purpose of determination of standing, production is important and not consumption. For the purpose of determination of injury, those producers who produce mainly for captive consumption should get little attention. The argument of the petitioner that GATT practice world over to exclude captive consumption is incorrect. It is claimed by importer that practice in US & Europe supports their views and captive consumption be excluded in injury analysis.
 - 20.2. The petitioner has argued that as per proviso to Rule 2(b) and Rule 11(3) would imply that there are two competitive market of Metcoke and each one of them must be treated as a separate domestic industry and those producer producing the Metcoke for captive consumption be treated as separate industry and those producing Metcoke for sale in the market must be treated as another industry. This argument is erroneous and has been made without proper appreciation of the legal position because such separation can be invoked only where there has been a concentration of dumped imports into a certain area and the producers within that area sell all their production in that area and the demand in that area is not supplied by producers located elsewhere in the territory to any substantial degree.
 - 20.3. The argument of petitioner that RINL should be excluded from the purview of domestic industry on the basis that RINL is under the administrative control of Ministry of Steel is not correct. SAIL is also under the administrative control of Ministry of Steel and has been excluded as Visvesvaraya Iron & Steel Ltd. (VISL), which is a subsidiary of SAIL, has imported the Metcoke. The petitioner has argued that since RINL and SAIL are under the administrative control of Ministry of Steel and thus related to each other. It is stated in Article VI that producers shall be related to importers if one of them directly or indirectly controls the other, or both of them are directly or indirectly controlled by a third person or together they directly or indirectly controls a third person.
 - 20.4. It is argued that the question whether RINL directly or indirectly controls VISL has to be answered in negative as RINL is neither legally nor operationally in a position to exercise restraint or direction over VISL. The converse is also true. RINL is not legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over SAIL and vice versa hence RINL and VISL are not related. On the date of initiation of investigation, there was no express support from RINL. If RINL questionnaire response is to be treated as support to the petition, then their subsequent opposition to imposition of anti-dumping duty are also to be considered. The petitioner did not

have the express support of RINL on the date of initiation and hence did not satisfy the 25% requirement under the proviso to Rule 5(3)(a) and the standing had to be determined only with reference to the support existing on the date of initiation.

- 20.5. The claim of the petitioner that the stage for determining the standing of the domestic industry is, before the Designated Authority decided to initiate the investigation, and not thereafter, is not correct.
- 20.6. PIMA has pointed out that even after excluding the production of SAIL & TISCO whose subsidiaries had imported the Coke, the petitioner, M/s BLA Industries & ICA account for 18.1% of the total production of Metcoke and hence do not have standing to file petition.
- 20.7. The petitioners who filed the petition did not indicate the names of other producers of Metcoke. To this extent the information furnished by petitioner was insufficient, incorrect and misleading. It is the duty of Designated Authority to satisfy itself that the petitioners who made the application satisfy the statutory requirements on standing to file petition. These conditions have to be satisfied at the time of initiation of the investigation. If a producer who at the time of initiation of investigation did not support the petition but later on support the petition after initiation of investigation, that can not be taken into account to validate the initiation of the investigations, if the original initiation was not in order. Since the petitioner had not given the details of production of RINL or BCCL, the Designated authority was misled. Wellman Incandescent Ltd. on 24.4.98 submitted to Authority that it is suffering injury. However in the letter they are not expressly indicating any support to petition. BCCL expressly supported the petition on 22.5.98. RINL has filed response on 28.11.97 however there is no indication about the express support. The said letter has been withdrawn on 15.5.98 and vide their letter dated 1.6.98, they are opposing the petitions. Thus even if BCCL support is taken into account which should not be taken into account, the percentage of productions of supporter and opponents of applications is 25.28% which is less than the statutory requirement of 50%. Thus the petitioners have no standing to file the petition nor maintain it and consequently the Designated Authority has no jurisdiction to initiate or continue the investigations.
- 20.8. The Authority has excluded the production of SAIL for determination of domestic industry on the ground that it is producing the coke for captive consumption and one of the subsidiary namely Visvesvaraya Iron & Steel is an importer. Under Rule 2(b) there is no provision to exclude the production of producing who produce for captive consumption. The excluded category covers the persons who are "themselves" the importers of the articles in question. The expression "themselves" is of utmost importance and refers to the producers/manufacturers of article in question. There is no provision anywhere in Rule 2(b) for excluding the figures of production on the ground that the domestic manufacturer itself is not an importer but one of its subsidiary company is an importer. Hence the petitioner and its supporter accounts for 4.2% domestic production and have no standing. Even if the figures of SAIL is excluded their share is 18% and they do not have standing to file petition.
- 20.9. There are only two producers BLA Industries Ltd. and Gujarat NRE Coke Ltd., among petitioners alleging dumping of coke, who have facilities to produce low ash coke with 12-15% Ash from imported coking coal. However they can not cater to the requirement of Pig Iron/Steel producers.
- 20.10. Rashtriya Ispat Nigam Ltd., (RINL) has requested to examine the possibilities of imposing duty on Metcoke on 28.11.97. However this letter was withdrawn on 15.5.98. On 1.6.98 they submitted another letter wherein they have opposed the petition to levy anti-dumping duty. They have stated that the coke production at RINL is primarily for its captive consumption and only surplus quantities have been sold in domestic market. They have also stated that their letter dated 28.11.97 had no clearance from the management and it was given unauthorised. It is also stated that content of the letter do not reflect the philosophy of Policy of RINL and they are

taking suitable action internally for sending such an unauthorised letter. They requested to treat the letter dated 28.11.97 as withdrawn and as null and void. Thus RINL has opposed the petitioner.

EXAMINATION OF THE ISSUES OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

21. The term "Domestic Industry" is defined under Rule 2(b). It reads as under:

"Domestic Industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to exporters or importers of the alleged dumped articles or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry

22. Provided that in exceptional circumstances referred to in sub Rule (3) of Rule 11, the domestic industry in relation to the article in question shall be deemed to comprise two or more competitive markets and the producers within each such market a separate industry if

- (i) the producers within such a market sell all or almost all of their production of the article in question in that market and
- (ii) the demand in the market is not in any substantial degree supplied by producers of the said article located elsewhere in the territory.

23. Rule 11(3) reads as under:-

"The Designated Authority may, in exceptional cases, give a finding as to the existence of injury even where substantial portion of the domestic industry is not injured if --

- (i) there is a concentration of dumped imports into an isolated market, and
- (ii) the dumped article are causing injury to the producers of all or almost all of the production within such market."

24. From the definition of domestic industry, as mentioned above, the Designated Authority is required to evaluate the scope of the term "Domestic Industry" in the context of the domestic producers who are engaged in the manufacture of "like article" and any activity connected therewith. Rule 5 (a) clearly states that the Authority is required to examine the degree of support for, or opposition to the application expressed by the domestic producers of the "like article". The proviso further states that no investigation shall be initiated if the domestic producers expressly supporting the application account for less than 25% of the total production of the "like article" by the domestic industry.

25. It is clear from the above that for the determination of domestic industry, only the producers of "like article" have to be taken into account. The Authority, having already determined the scope of the term "like article" in para 18 above, is required to take into consideration the total production of only the "like article" i.e. metcoke of ash content up to and below 15% only for the purposes of determining the threshold limits of 25% and 50%. The authority, therefore, proceeds to determine, on a factual basis, as to which of the producers constitute the domestic industry of India:

Name of the company	Ash content	Production during period of investigation (in MT)
BLA Industries	Less than 15%	119337
Industries & Commerce Association	More than 15%	543603
Southern Fuel Ltd.	Less than 15%	10623
Bharat Coking Coal Ltd.	More than 15%	215500
Wellman Incandescent India Ltd.	Less than 15%	59425
Gujarat NRE Coke Ltd.	Less than 15%	50860

Durgapur Projects Ltd.	More than 15%	323701
Fertilizer Corpn. Of India	More than 15%	102000
Rashtriya Ispat Nigam Ltd. **	More than 15%	1895273
Steel Authority of India Ltd. **	Related to importer	9957431
Tata Iron & Steel Co. Ltd. **	Related to importer	2018800
Sesa Kembla Coke Co. Ltd. **	Related to importer	160647
Usha Udyog **	Related to importer	77283

Note - "*" above indicates those companies who produce metcoke primarily for captive consumption.

26. From the above table M/s SAIL, TISCO, SESA Goa and Usha Udyog happen to be importers/ related to importers of metcoke and, therefore, they have to be excluded from the scope of the term "Domestic Industry". It has been argued that for the purpose of exclusion, the producers should be "themselves" importers. The Authority observes that the definition of "Domestic Industry" under Rule 2(b) is abundantly clear that not only the producers who import themselves are to be excluded but also those who are related to such importers. The findings of the Authority in the preliminary notification regarding the status of SAIL, TISCO, SESA and Usha Udyog are, therefore, confirmed that they do not form a part of the "Domestic Industry" for the purpose of these investigations.
27. It has also been noticed that the members of ICA and RINL are producers of metcoke of above 15% ash content. Therefore, these units are not the producers of like articles for the purpose of these investigations. Subsequent to the disclosure of essential facts, it has been stated by the importers that it would not be correct to state that RINL is producing coke with ash content of above 15% in view of the fact that some tolerance is to be allowed in the stated figure of 15%. The Authority notes that the production figures of RINL and their average ash content was provided by RINL itself on a monthly basis. These figures clearly indicate that RINL, by its own admission, had never produced metcoke of less than or upto 15%. Moreover, the facts stated in the disclosure statement have not been disputed by RINL itself. The contention of the importer, therefore, cannot be accepted. This is without prejudice to the finding of the Authority that the production of RINL which is meant for captive consumption is not to be included for the purpose of either the determination of domestic industry or for the purpose of standing.
28. The Authority understands that BCCL, DPL, and FCI, are producers of high ash content coke. There is no evidence produced before the Authority that they produce LAMC (upto 15% ash content) which is a like article in this case. Hence, the Authority on the basis of best information available with it determines that BCCL, DPL and FCI do not form part of domestic industry.
29. The contention of the petitioners that RINL and SAIL should be considered as related as they are both under the administrative control of the Steel Ministry, cannot be accepted. After making necessary inquiries, the Authority is satisfied that these two companies are run by independent Boards of Directors and the Ministry of Steel has not exercised any kind of control specifically in the metcoke case.
30. The final position with regard to the producers who are being considered as a part of the "Domestic Industry" is as follows:

BLA	119337 MT
Southern Fuels	10623 MT
Weilman	59425 MT
Gujarat NRE	50860 MT
TOTAL	240245 MT

31. An issue has been raised that the production by the domestic industry for captive consumption should also form a part of the total domestic production as there is no

provision for exclusion of the same under the Indian law. In this context, the learned counsel for the exporters has also repeatedly mentioned that there is WTO advice with the Ministry indicating that the production meant for captive consumption should not be ignored for the purpose of determination of "Domestic Industry".

32. Subsequent to the disclosure, a number of importers have annexed a copy of a communication received from the Permanent Mission of India at Geneva (PMI) with regard to the issue of including the production meant for captive consumption for the purpose of standing. None of the parties has, however, enclosed copies of the letter dated 10th June, 1998, seeking clarification from the PMI. The said communication dated 20.7.98, which was submitted to the Authority on 10.8.98 (the last date of submitting response to the disclosure statement), reads as under:

"PERMANENT MISSION OF INDIA
GENEVA
No. GEN/PMI/WTO/...

20 JULY 98

TO: MR. R. PARTHASARTHY, EX.IA&AS
M/S LAKSHMI KUMAR & SRIDHARAN
FAX : 00-91-11-6197578

FROM: S. PRIYADARSHI, COUNSELLOR

Please refer to your letter dated 10 June 1998 addressed to Ambassador Narayanan regarding certain provisions of the Agreement on the implementation of anti-dumping measures.

As desired by Ambassador, I had spoken to the concerned officer in the WTO Secretariat who has clarified that while the Agreement does not provide clarity on whether domestic producers who produce only for captive consumption should be included while calculating the support for any anti-dumping application, the presumption has been that irrespective of the end use, all production shall be taken into account when calculating any specific percentage of support.

With regards,

Signed
(S. PRIYADARSHI)
COUNSELLOR"

33. The Authority sought details and certain clarifications from the Ambassador in the PMI about the source of such clarification and also the legal basis, economic rationale and the jurisprudence on the issue. A reply dated 11.8.98 was received from PMI and certain relevant extracts from the letter are reproduced below:

"This is in response to your fax message of yesterday.

It is my feeling that the question of inclusion or non-inclusion of production meant for captive consumption in determining 25% yardstick provided for in Article 5.4 of the Anti-dumping Agreement is a grey area in the Anti-dumping Agreement. One WTO Secretariat Officer as well as one eminent legal professional whom I have consulted today in the matter, have confirmed that the Anti-dumping Agreement is not at all clear on this aspect of the Agreement. I also understand that this issue has not been a subject for consideration in the dispute settlement process under the old GATT or the present WTO, at any point of time. Therefore, it is obvious that the issue is wide open and quasi-judicial authorities are entitled to interpret the provisions of the Agreement, in any manner they like as long as such an interpretation meets the criteria of reasonableness, consistency and good faith.

Regarding the message sent by Counsellor in the WTO Mission, I would like to clarify that in response to a specific request made for clarification he has sent this message on the basis of the informal consultations he has had with one particular WTO Secretariat officer. By no stretch of imagination can it be argued that this message of Counsellor in the WTO Mission constitutes an authoritative interpretation and that it is binding. In fact, I find that Mr. Priyadarshi has clearly indicated that WTO Secretariat had acknowledged that the Agreement itself does not provide clarity on whether the domestic producers who produce only for captive consumption should be included while calculating the support for any anti-dumping application."

"In the light of the above it is clear that the message of the Counsellor (WTO) conveying the presumption of a WTO Secretariat officer, that too with the preface that there is an absence of clarity in the Agreement, can have no binding value.

Therefore, you can proceed on the basis that there is no binding decision/jurisprudence on the question of including or excluding captive consumption while calculating support for an anti-dumping application."

34. Notwithstanding the fact that the Authority is not bound by the personal or official opinions of the WTO Secretariat officials, no legal or economic analysis, reasoning or case law has been cited to arrive at the said opinion. In this respect, no credence can be attached to the said clarification nor can it be said to have even any persuasive value. The Authority observes that, as per its consistent practice, production meant for captive consumption need not be included for the purpose of defining "Domestic Industry" or the standing of the petitioners. The Authority considers that goods meant for captive consumption do not enter into the markets where the merchant goods are competing with the alleged dumped goods. In any case, the Authority observes that in the instant case, there is no producer of metcoke of upto 15% ash content, who is otherwise eligible to be covered under the scope of "Domestic Industry". The Authority also observes that the practice of European Commission and the US authorities cited by the exporters' counsel that goods meant for captive consumption are not excluded, is not factually correct.
35. The Authority observes that the total production of metcoke of upto 15% ash content (like article) by the "Domestic Industry" is 240245 MT during the period of investigation. The petition has the support of the all producers who account for 100 per cent of the total production of the "like article" by the "Domestic Industry". The Authority therefore concludes that the petition has the requisite support as envisaged under the law.
36. An issue has been raised that the Authority has to determine the standing on the date of initiation and any subsequent support to the petition should not be taken into account. The Authority observes that even though it is required to determine the support of opposition to a petition at the time of initiation of investigations, such determination is based only on the basis of examination of the evidence available at that point of time. Further, the Authority should and can go into the issues of scope of "Domestic Industry" and "like article" only after the investigations are initiated. The details of whether any producer is also an importer of the alleged dumped goods can only be established after a proper investigation is initiated following the due process of law. Similarly, the precise scope of the term "like article" can also be determined after the Authority gets an opportunity to carry out detailed investigations, and after giving due opportunity to all the interested parties. On the basis of detailed information and an in-depth analysis, the scope of the terms "Domestic Industry" and "like article" is determined by the Designated Authority, which has a direct bearing on the standing issue. A final determination of any aspect at the pre-initiation stage itself is, therefore, not contemplated either in the Indian laws or in the GATT Agreement nor would such a process be consistent with the principles of natural justice.
37. In view of the above discussions, the Authority also holds that based on the information available to it at the time of initiation, the petitioners had the standing to file the petition on behalf of the domestic industry. As stated earlier, after redefining the scope of "like article" and admitting the argument of the importers/exporters that the high ash content metcoke

producers should be excluded, the Authority holds that the petition has the support of producers accounting for 100% of the production of "like article". On the date of initiation the petition was filed by M/s BLA Industries Ltd. And ICA and was supported by Southern Fuels Ltd. These producers collectively accounted for more than 25% of "Domestic Industry" known as producers of metallurgical coke at that point of time. As such, the petitioners had the standing to file the petition on behalf of the Indian "Domestic Industry" on the date of initiation of investigations.

F. NORMAL VALUE

This section has been divided into the following:

- Claims of the exporters
- Views of the petitioners
- Views of the exporters/importers
- Examination by the Authority

CLAIMS OF EXPORTERS

38. Shanxi Coal Import Export Group Corpn.: The said exporter has not submitted any other information after the preliminary findings were notified. Thus the claims of above exporter in the preliminary findings stand and there is no change.
39. Ningxia Xiacheng Import & Export Corpn.: The said exporter has not submitted any other information after the preliminary findings were notified. Thus the claims of the above exporter in the preliminary findings stand and there is no change.

40. China National Import/Exports Hebei Co.:

- 40.1. It is stated that their export sales are to traders. Their domestic sales are of manufacturer who supplied export cargo to India. The manufacturer is Shiziazhnang. It has also been stated that they are not selling this grade of coke to other country.
- 40.2. Price adjustments have been claimed on account of discount (penalty for quality deviations affected in invoice) commission, inland freight and handling charges in the export price to India. The exporter has submitted the agency agreement wherein the commission percentage as claimed is indicated. In support of inland freight the exporter has submitted invoice from Railways and a certificate from the Railway Bureau of Beijing, Shijiazhnang Station dated 9.7.98, wherein it is certified that during the period from April 96 to April 97, the freight rate has not changed. Regarding the handling charges the exporter has submitted invoice raised by handling agent. The exporter has revised its claim from **** to **** in respect of handling charges. Further, the domestic price has been shown as ****. The exporter has not claimed any deduction to arrive at the ex-factory price as they have stated that domestic customers take the delivery at the factory gate and bear all further expenses and the list price is only the base price, taxes and other additions are extra.
- 40.3. In support of domestic price claimed, the exporter has submitted copy of sales ledger for the relevant period. The exporter has submitted invoices for July 96, Oct 96 and Nov 96, Feb 97 to show the prevailing domestic price. Cost statement of the producer claiming that domestic sales were profitable which are certified by the CPA showing that the production and sales of coke of the concerned size are at profit has also been submitted.

41. China National Coal Industry:

- 41.1. The exporter has stated that there is no domestic sales and it is not exporting this grade of metcoke to any other country. It is also indicated that the company is not providing any other financial assistance to their customers and payments are usually

by an irrevocable letter of credit on sight payment terms. Hence no interest cost is incurred.

- 41.2. The company has further stated that it had exported four consignments to India during the period of investigation. Out of four consignments, three export consignments were purchased from company A and one was purchased from company B. In respect of export through company A, the exporter has revised its claim on inland freight and loading charges. In respect of exports through company B, no deduction is claimed as the port is stated to be located at the backyard of cokery.
- 41.3. The exporter has submitted the invoices in respect of inland freight and loading charges. Thus the ex-factory price in respect of exports is as under:-

(In US \$)

	Exports from Company A	Exports from Company B
Price	****	****
Inland freight	****	
Loading cost	****	
	****	****
	****	****

- 41.4. The exporters have submitted the domestic Invoice in respect of company A. The exporter has submitted invoices for the month of April 96, Dec 96 and March 97 and expressed inability to provide invoice for other months due to short time given. The exporter has also submitted the Profit & Loss Statement. It is observed that they are getting subsidy and also incurring losses. However it is not clear whether the exporter has adjusted the effects of subsidy. The exporter has however stated that coke oven gas is to be sold at prices fixed by Government and the Government of China subsidises the losses incurred on this count. The subsidy has nothing to do with Metcoke. The exporter has claimed that it has made profits on all the grades of coke. It has also claimed the domestic price of company A as ****, which establish no dumping. It is further claimed that in respect of company B, the domestic price is ****, and hence there is no dumping.

42. China North Industries Corpn.:

- 42.1. The exporter has stated that it had exported only one consignment of metcoke to India in Feb. 97. M/s Shanxi Linfex Ping Yang Cokery factory is the producer. The exporter has claimed that it has exported the consignment on C&F basis and has claimed price adjustment on account of discount/commission, inland freight, storage, loading cost, SGS inspection charges and ocean freight in the export price to India. It has submitted copy of agreement to claim commission. It has submitted one invoice showing the inland freight claimed. The exporter has submitted the copy of agreement showing ocean freight claimed. Evidence has also been furnished showing the claim on account of storage and loading cost. The ex-factory export price claimed is ****. Regarding domestic price, the exporter has submitted one invoice of Feb. 97 showing the domestic price. The exporter has further stated that it is not in a position to supply the details of domestic sales as the record of manufacturer had been taken over by the Government for investigation. The exporter has produced a letter from Shanxi People High Court in this regard. On the basis of this invoice, the domestic price claimed is ****. The exporter has thus claimed de-minimus dumping margin. It is also claimed that the cost of production is **** and the sales are above cost. In support of the cost claimed, the exporter has submitted a certificate by CPA showing the production cost.

43. China National Mineral Import & Export Corp. (Minmetal Group):

43.1. The exporter has claimed that Geng Yang Coking Plant produces coke and supplies its entire production to Minmetal, which is then exported to India or other countries. It is also claimed that the producer did not sell subject goods within China, and the export to third countries were not from the producer whose production was sold to India. Thus the exporter has proposed to discard the details of export to other countries. The exporter has further submitted that normal value by way of domestic price or by way of export price to third country is not available and therefore the same be constructed on cost of production basis. The exporter has claimed the price adjustment on account of inland freight, storage (warehouse), handling (loading from warehouse to berth) and SGS inspection charges on the export price to India. The exporter has also claimed that the sales are above cost. It has submitted a sheet showing cost calculation for the year 1996 certified by CPA that the cost is ****. It is claimed that producer sold the goods to Minmetal at ****, who in turn exported to India at ****, and thus there is no dumping. The exporter has submitted evidence in respect of deductions claimed from exports.

44. **Shanghai Pacific Chemical Corporation:** The exporter has claimed that it manufactures the coke. It is claimed that their cokery is at the backyard of the port and the coke produced is directly conveyed by belt to the port site where it is stored and loaded on the vessel. Thus there is no inland freight involved. The exporter has claimed price adjustment on account of storage charges in the export price to India and submitted some invoices claiming the storage charges. The export price on ex-factory basis is ****. The exporter has claimed that it is selling the product within China and has claimed deduction of VAT @ 17%, which is shown in the invoices also. It has been claimed that the delivery of coke for domestic sales is on ex-factory basis and the customer incurs the expenses for transporting the coke from the factory of the manufacturer's premises. No expenditure is incurred separately on account of packing, storage and handling in case of domestic sales. The exporter has claimed the domestic price on ex-factory basis after VAT as ****, as compared to the domestic price of ****. The exporter has thus claimed de-minimus dumping margin. The exporter has stated that the number of domestic invoices runs into more than 20000 and in view of large number of invoices and short time available, it has not been unable to trace out and make photocopies of all the invoices. The exporter has submitted a copy of its ledger showing the invoice wise sale of coke for May, June, August, Oct & Nov. 1996 and Jan. & March 1997 (corresponding to the eight months in which there were export transaction). The exporter has submitted all the invoice for the month of Oct 96 and sample invoices in respect of other months. The company has submitted its cost statement for 1996 and 1997, certified by Shanghai Region Certified Public Accountant and has claimed that it had made profits on production and sale of coke both in the year 1996 and 1997 and therefore domestic sales price reported within China should be considered viable and should be used for determination of the normal value.

45. Some exporters have submitted a few copies of the purchase invoices of coal. The English translation of these invoices is woefully inadequate in as much as the ash content of coal is also not given. The other commercial details have also not been translated. In any case, the Authority refrains from accepting any fresh evidence at this stage as it would be a denial of natural justice to the other side who would not have an opportunity to rebut any additional evidence at this late stage. As stated earlier, the exporters failed to provide sufficient evidence in support of their claims despite several opportunities.

46. Views Of Petitioners:

The views of the petitioners on Normal Value determination are as under:

46.1. The coal mining industry in China is primarily supported by the state as a means for generating employment. It is also largely unregulated and often illegal. The cost of coal is unrealistically low as labour and other social factors are totally ignored. Thus it makes the fundamental cost of coke unreliable. Selected article reveals that several thousand lives are lost over a year in coal mining activity.

- 46.2. There is a complex web of licensing requirement and thus all these companies are related and collectively involved in large scale of dumping.
- 46.3. China is a non market economy and In India Designated Authority has recognised China as a non market economy in several anti dumping cases. Mere submission of certain invoices in domestic transaction, does not suffice in proving that coke is sold domestically within China at free market rate. State, in China, still remain the owner of most enterprises and a complex web of licensing requirement is used to maintain total control. Thus normal value can not be taken on the basis of domestic sales. Chinese metcoke manufacture have neglected to provide the domestic price on coal and they seem to rely on reverse accounting of "normal value." Since normal value can not be accepted on the basis of domestic prices, it is to be constructed.
- 46.4. Coal accounts for over 70% of the cost of coke and thus accurate cost of coal is fundamental to any construction of price of coke. Best and most accurate method of doing so is when a country having abundant natural resources would pay for the same natural resources from other countries. Thus c.i.f. price of coal imported by China, should be taken as cost of coal.
- 46.5. As per the responses of exporters, there has been a 100% variation in the price of coke in China by different supplier. If they are selling coke at US\$ 33.8 PMT, the price of coal has to be free. None of the exporters have their own domestic sales but provided information of domestic sales from other producers. Some of the exporters have claimed deduction on VAT, whereas others have not. Thus the information submitted by exporters are incorrect and should not be taken into consideration. None of the exporters have submitted the price of coal. On the other hand, several attempts were made to derive the cost of coal by reverse calculation. This strengthen the view that price of coal be taken as the price at which Chinese and importing coal from Australia. In China, coal companies are selling coal below cost and thus domestic coal price in China are non reflective of fair cost and is cross-subsidised by Government in several cases.
- 46.6. The importers have not disputed that normal value may be computed by constructing the cost of production. They have opposed the workings as submitted by petitioner and inter alia, they have opposed, cost of coal as the landed price of imported Australian coal into China. The petitioner has never claimed that all the coal used for coke making in China is imported from Australia. It is not denied by importers that China has imported coking coal from Australia and Imports must necessarily make economic sense and thus the cost of Australian coal in China can be considered as the cost of coal in coke plants in China.
- 46.7. The petitioner have denied that cost of manufacturing in China is exaggerated. It is estimated in China based on competitive cost in India. Chinese accounting standards are not upto standard. Thus cost of production submitted by Chinese exporters can not be relied upon. Thus neither the cost of production nor domestic prices as submitted by Chinese exporters can be relied upon.
- 46.8. The importer have failed to account for "specific density of coke Vs coal." In layman terms, this means that more coal will fit into same size of bucket than coke and thus transportation cost of 1 tonne of coal will be cheaper than the transport cost of 1 tonne of coke. This ratio of coke is to coal is 1:1.81 on these basis, the price of coke produced in India would be cheaper as compared to Chinese coke.

47. Views of Exporters/Importers

- 47.1. The Authorities had concluded in the preliminary findings that none of the seven co-operating exporter/producer from the China had provided any evidence/clear evidence in support of deductions or domestic price structure. However this is incorrect. The findings of the Authority was contrary to the detailed submission and evidence made available to Authority by Exporters. The Authority had not issued

any deficiency letter to the exporters calling for any further evidence/clear evidence in respect of even one exporter. The exporters had expressed their "no objection to the verification of their claims at site in China." The findings to discard all responses on the ground of absence of evidence/clear evidence shows a pre-conceived decision to recommend provisional duties.

- 47.2. The determination of dumping margin of 118.53% and recommendation of an anti-dumping duty of Rs. 1800/- PMT is not clearly borne out by the facts and is arbitrary and illegal.
- 47.3. China has produced 1280 million tonnes of coal in 96-97 and has produced 80 million of coke as per petitioner. Thus the quantity of coal required for producing this coke is 120 million tonnes of coking coal which China has produced domestically. China imported 2.51 lacs tonnes of coking coal from international source for trial purpose which contributes 0.2% of coking coal used by China. Thus the import of coking coal by China during 1996-97 has been negligible when compared to its domestic production of coking coal. The import of 0.2% of coking coal can not be made the basis of calculation of normal value of Chinese coke as shown by applicant.
- 47.4. The price of imported LAMC from Australia and Japan are also similar to that of Chinese coke exported to India. When these are claimed non-dumped, the alleged dumping from China is not justified. The volume of imports from so called non dumped source is also not insignificant.
- 47.5. The petitioner's claim that domestic sale within China are not in the ordinary course of sale, is not supported by any evidence. Hence this submission deserves to be rejected.
- 47.6. The exporter in their responses have submitted their cost sheets showing the cost of coal, various expenses which should be taken while arriving at the cost of coke. The claim of the petitioner that cost of coal is unrealistically low as labour and other social cost are ignored, is incorrect.
- 47.7. The claim of petitioner that China is a non market economy is not correct. China has developed into a market economy since long. The evidence submitted by Chinese exporter support this. The Indian legislation on anti-dumping does not provide for the treatment of a country as "non market economic country". The assertion of the petitioner that Designated Authority had treated China as a non market economy in several anti-dumping cases is factually incorrect. Wherever there was no co-operation at all from Chinese exporters, the Authority had gone by the best information available and the said best information may be based on cost constructed either from those prevailing in India or in certain other countries.
- 47.8. There can not be two opinion that domestic invoices are the most formidable evidence of the domestic sales transaction. If invoices can not prove the transaction, it is highly improbable that any other documents can be relied upon. The contention of petitioner that mere submission of certain invoices of domestic transaction, will not suffice in proving that coke is sold domestically within China at free market rate, is not correct. Thus domestic price of coke should be considered in arriving at the normal value.
- 47.9. In the present case, co-operating exporters have made available the details of normal value, being sale within the domestic market in China, as also the cost of production to show that the domestic prices are viable. This being the case, the resort to constructed cost or to determine the normal value with reference to any other hypothetical factor is unwarranted.
- 47.10. PIMA has pointed out that even by considering the figures in petition, it can be established that there is no dumping by exporters from China. Assuming that FOB

cost of Chinese coal is same as that in Australia (in fact it is much lower), the cost of coal for a Chinese coking plant at its factory gate will be US\$ 18.02 (deduction from FOB of US\$ 51.02, US\$ 8 on account of stevedoring and US\$ 25 for inland transportation). The cost of coke at the conversion rate of 1.5 times would work out to be US\$ 27.03. If the manufacturing cost as indicated in petition, US\$ 29.17 is added, the cost of coke in China would work out to be US\$ 56.20 PMT. The export price has been more than this domestic cost. The cost shown by petitioner US\$ 206 PMT is highly exaggerated. One of the importer has also pointed out that, conversion cost of coal into coke is normally about Rs.450/- PMT and there is absolutely no scope to take the manufacturing cost at Rs. 1050/- PMT. The petitioner has claimed the ocean freight as US\$ 22, which in fact should be US\$ 17. Thus the c.i.f. value of metcoke should be US\$ 87 PMT and this is based upon petitioner own facts. The export price is about US\$97 on c.i.f. basis and thus there is no dumping.

- 47.11. Some of the importers have, however submitted that, on the basis of information available in the petition, the dumping margin works out to be Rs. 502/- and therefore the duty is liable to be reduced to Rs. 502/-. However it is submitted, that this is based on certain assumption and without admitting that any dumping is being done by Chinese exporters. It is also submitted that landed cost has not been calculated correctly and it requires revision.
- 47.12. The exporters have submitted that their response to questionnaire sent after the initiation of investigation contained all information required by Designated Authority to arrive at a prima facie view that such exporters are not dumping metcoke in India. The Authority could have supplemented this prima facie view by the verification at site of the exporter and producer as the exporter/producer had shown their willingness for such verification. The Authority had discarded the information on the basis that no evidence/clear evidence have been submitted. The Authority had also observed that it appeared that the goods have been sold by exporters who did not produce goods and it was not clear whether the claims made pertained to the exporter or to the producer and thus the Authority was prevented from determining the export price as the price of producers to the exporters was not available and the normal value of the producers can not be compared with the export price of the exporter. It is now submitted by the exporters that export of goods from China is to be made only by the organisation which hold an export licence. All producers do not hold export licence and hence sell their goods to the export companies holding an export licence who in turn export the goods to various countries. Thus the exporters had responded to the questionnaire and providing at the same time the details of the cost of production and the domestic sales of the producer to enable the Authority to determine the dumping margin for the export corporation and the connected producer. As it was not required to submit all the evidence, the exporters claims, that they submitted sample invoices and it was presumed that all the other invoices and evidence would be looked at by the Authority during verification. Regarding the submission of evidence to cost statement, it is argued by the exporter that, there was no requirement in the questionnaire to support the cost statement with any further evidence. The cost of product is a matter for verification site. Thus the exporters argued that levy of anti-dumping duty has caused serious prejudice to their interest.

48. Examination by the Authority:

- 48.1. The Authority notes that even though all the producers in China have adopted the same manufacturing process and technology, their claims with regard to cost of production of metcoke differ substantially. Considering the costs for each element of input for Shanghai Pacific at a notional point of 100, costs claimed by the other three producers/ exporters who have given figures/information in the format requested by the Authority has been indexed, which shows as follows:

	SHANGHAI PACIFIC	CHINA NORTH	CHINA NATIONAL	CHINA NATIONAL I/E
Raw Material	100	31.17	52.39	35.57
Direct Labour	100	63.33	63.33	80.33
Utilities	100	12.91	13.17	22.29
<u>Overheads:</u>				
-Manufacturing	100	1.51	10.54	0.00
-Depreciation	100	5.80	16.91	17.51
-Interest	100	6.74	157.87	21.91
Packing Costs	100	0.00	0.00	0.00
SGA	100	48.25	24.56	354.39
Less: By Products	100	0.00	0.00	0.00
Total Net Cost Of Production	100	58.79	89.49	66.19

Note: 1. Indexation for Special Tax not done as it is claimed by only one exporter

2. The table does not include information relating to other China PR exporters who have not furnished information in the prescribed format as above.

48.2. It is seen from the above that cost for no item of inputs is comparable amongst the four exporters analysed by the Authority. Moreover, the variations are also quite significant. It is also noted that while one exporter has claimed substantial cost towards "special tax" (M/s. China North), no other exporter has claimed any cost on this account. The claims of the exporters do not appear to be based on Generally Accepted Accounting Principles. The Authority had, therefore, requested detailed information on cost of production, for which a proforma was also provided to the exporters to enable them to furnish relevant information. However, none of the exporters furnished detailed costing information requested by the Authority. The argument of the exporters that their sales in the home market were above costs and the same is evident from the profits made by them (for which the exporters have furnished some evidence also) is also misleading. The Authority notes that one of the exporters has furnished information, which suggests that the exporter has claimed profits on the sales in the home market, while it has claimed substantial losses in the sales of by products. Authority had requested specific information on the following:

- Transaction-wise list of all sales made in China covering all sales and should be supported by the relevant invoices.
- Transaction-wise list of all exports made to India covering all sales supported by the relevant invoices. In case, the goods have not been exported directly by the exporter, matching information linking the exports with the prices at which goods have been exported was to be furnished, along with all relevant invoices raised on Indian Importers.
- Transaction-wise list of all exports made to countries other than India (country-wise) covering all sales supported by the relevant invoices.
- The basis of adjustments claimed from sales made in the home market or exports to India with reference to appendix 3A and 3B of the questionnaire supported by relevant evidence.

- Details on cost of production of metcoke as per proforma "I" enclosed with the letter sent to the exporters. In case any by-product is being recovered during production of metcoke, information was sought as per enclosed proforma, which included information on the following:
 - Name of the by-product
 - Total quantity of by-product generated
 - Utilisation of by-product generated giving therein separately (In volume and value) by-product consumed captively and sold outside
 - Balance of by-product in stock with the company, volume and value
 - Total production of metcoke
 - A copy of profit and loss account, balance sheet and such other financial statements to indicate the operations as well as financial performance of the company, for the last three years including the investigation period
- 48.3. It was mentioned that all information must be in English or accompanied by an English version. All documents should be certified by the Chief Executive of the company concerned as true, complete, correct and presenting true and fair view. All information and documents should also be certified by a practising Chartered Accountant as true, complete and correct.
49. The Authority notes that none of the exporters furnished above information in spite of specific request made by the Authority. The Authority is thus not in a position to satisfy itself whether the claim made by the exporter with regard to adjustment towards by-product is justified. The claim of the exporter on account of by-product recovery assumes importance in view of the arguments raised by the other interested parties. While the petitioner has furnished information suggesting that the recoveries on account of by-products does not exceed US \$ 8 (based on the recoveries made by one of the largest producers of metcoke in India having by-product recovery type manufacturing process), one of the importers has conceded that the recoveries does not exceed US \$ 3. The claim of the exporter is nowhere close to the claims made by other interested parties and the exporter has suppressed specific information requested by the Authority on this account. The exporter has thus not co-operated with the Authority in so far as material information requested by the Authority has not been furnished.
50. With regard to the argument that the Authority could have asked for information required before notifying the preliminary findings or the Authority could have verified the information at the premises of the exporters, the Authority observes that the purpose of sending questionnaire to the interested parties is to allow them to respond in the form and manner prescribed. There is no obligation on the Authority to point out deficiencies in the responses submitted, particularly when the Authority is required to notify the findings, preliminary or final, within the time limits prescribed.
51. The argument of the exporter that the Authority could have verified the claims made by the exporter cannot also be appreciated as the purpose of spot verification is to verify the information furnished by an interested party and not collection of information. In fact, Annex I to the Anti Dumping Agreement provides that the information should be collected prior to verification. Verification of information by the Authority at the premises of the exporters can not substitute submission of information by the interested parties. In fact, when the information requested has not been submitted in the form and manner prescribed, the verification visits may also not serve any useful purpose.
52. In view of the above, the Authority is constrained to disregard the claim of the exporter with regard to by-product recoveries. By-product recoveries have been provided on the basis of independent information available with the Authority, which is based on recoveries made by one of the largest producers of metcoke in India employing recovery type process. It is found, after making adjustment on account of recovery, that the cost of production of the exporter is significantly higher than the selling prices in the

home market. The selling prices in the home market, therefore, are not in the ordinary course of trade by reason of price and have to be disregarded.

53. In view of the foregoing, the Authority has determined the normal value based on the cost of production in accordance with Section 9A(1)c. The cost of production claimed by the exporter has been reworked after making adjustment for by-product recoveries. Due allowance has been made for the selling, general and administrative expenses on the basis of the expenses claimed by the exporter. Fair return has been provided @ 5% as per the consistent practice and in view of insufficient information from the exporters from China PR.
54. From the foregoing paragraphs the Authority observes that the exporters were required to submit adequate and sufficient information on export prices, domestic prices and costing while responding to the questionnaire. This information is essential to determine the normal value, export price and dumping margins. The Authority observed in the preliminary findings that information submitted by exporters was sketchy and insufficient and the Authority was not in a position to determine the normal value on the basis of such information.
55. After the issue of preliminary findings, five exporters out of seven exporters responded and submitted additional information on domestic prices, export prices and costing data. The Authority observed that even this information was grossly insufficient to determine the normal value in accordance with the Rules. Therefore, the Authority vide letter dated 30.6.98 (details already given in para 48.2) requested the exporters to provide necessary information as detailed in the letter. The Authority reiterated its requirements regarding furnishing of such information by the exporters in a subsequent letter. Thus, sufficient opportunity was provided to exporters for providing necessary information on several occasions.
56. Five exporters submitted information on 20.7.98 in response to letter dated 30.6.98 issued by the Authority. On examination, the Authority observed that information on prices, as asked for, was not provided. The Authority observes that critical information on costing data was also not submitted. As detailed in letter dated 30.6.98, the exporters were required to submit the costing information on raw material cost, utilities, appropriation and allocation of overheads for various products, cost sheet, balance sheet and profit & loss account, costing information of by-products. The Authority observes that none of the exporters has given sufficient details/evidence to verify the cost claimed by the exporters. Such details/evidence are of paramount importance as the cost on different items such as raw material, labour, overheads, and other expenses varies significantly in the cost data submitted by exporters and highlighted in para 48.1. The costing data is critical to determine whether the domestic price are above the cost or not. Under the Rules, if the domestic prices are below cost, such domestic price can not be accepted for the purpose of determination of normal value. It is also observed by the Authority that exporters/producers have claimed that they have made profits on sale of coke. However, the Authority notes that such exporters are incurring significant losses on the sales of by-products such as gas. The basis of allocation of cost between coke and such other by-products is not clear and the details, though specifically called for, have not been provided for. The Authority also notes that by-products generated per unit of coke and the details of such by-products are not submitted.
57. The Authority thus observes:
 - (a) The costing data submitted by various exporters are not comparable and therefore can not be relied upon.
 - (b) The complete information in respect of costing data are not submitted. For this purpose, as already detailed above in para 48.2, the Authority requested to submit data in the prescribed formats, which were neither adhered to nor the required information submitted.

- (c) Regarding by-products, none of the exporter has submitted the required information as detailed in letter dated 30.6.98. The exporters have claimed profits on sale of coke, but there are significant losses on other by-products and basis of allocation of cost is not submitted.

58. The Authority, however, has constructed cost of coke in China on the basis of information submitted by M/s Shanghai Pacific, who appears to be the largest producer and exporter of metcoke in China amongst those who have responded to the questionnaire. The Authority notes that even though M/s Shanghai has not provided sufficient information, it has submitted better information as compared to other exporters. Also as the largest producer, their costs can be considered representative of costs in this sector in China. Thus the Authority considers that the costing information submitted by M/s Shanghai Pacific as the "best available information" in the instant case and therefore can be considered for the purpose of determination of normal value on the basis of constructed cost of production. Thus while constructing the cost of production in China, the Authority accepts the raw material, labour and overheads cost as submitted by M/s Shanghai Pacific. It is however, observed that M/s Shanghai is recovering by-products, many of which are being sold at losses. In the absence of basis of allocation of cost and evidence/details, the cost allocated to by-products cannot be accepted as claimed by the exporter. The Authority attempted to find out the norms for recovery of by-products and notes that assuming the gross cost as 100, the information on recovery on by-products is as under:

	Claimed by Shanghai	SAIL	Importer	Kirk Othmer *
Gross cost	100	100	100	100
Less :				
By products	47.54	19.44	6.23	17.51
Coke	<u>52.46</u>	<u>80.56</u>	<u>93.77</u>	<u>82.49</u>

* Kirk Othmer Encyclopaedia on Chemical Technology.

59. The Authority, considering that recovery percentage in the case of SAIL is reasonable and reliable, allows the recovery on by-products in the cost as claimed by Shanghai. The constructed cost is thus calculated as under:-

	US\$
Raw material, utilities overheads and expenses	
As claimed by Shanghai	****
Less: by-products @ 19.44%	****
Total cost	<u>****</u>
Add reasonable profit @ 5%	****
Normal Value	****

60. Thus the Authority concludes that normal value of metcoke in China is ****.

61. Some interested parties have argued that the Authority is not justified to calculate the cost of coke on the basis of Imported Australian coal. It may be mentioned that the Authority has not calculated the cost on the basis of Australian coal.

62. The Authority has allowed adjustments in the export price to India as well as the export price at ex-factory level as claimed by the said exporter in order to maintain consistency in the calculations of all commercial costs.

63. DUMPING MARGIN: The comparison of normal value and the export price shows the dumping margin of 28.95%.

G. INJURY ANALYSIS**64. Submissions of Petitioner:**

- 64.1. There has been a reduced off-take of BLA coke, suppression of sales price, increase in stocks and closure of capacity. More than hundred workers have been retrenched. In Dhanbad, thousand of workers have lost their livelihood, and production in several units have come to a stand still. In the case of Wellman, the entire plant is closed down and company has been registered as sick by BIFR. Durgapur projects, Southern Fuels and Gujarat NRE have partially closed down their plants as well. Several companies have shelved indefinitely their expansion plans.
- 64.2. Domestic industry has the capacity, reserves and quality to meet the growth and demand. However their growth is almost stagnant for 4 years whereas the Chinese imports have grown up by 916% from 93-94 to 96-97. The growth of imports from other country is comparatively low at 173%. The increase in Chinese imports are on accounts of dumping. The domestic users have migrated from Indian metcoke to Chinese metcoke.
- 64.3. The Authority has levied anti-dumping duty at a lower rate. Instead of duty of Rs. 1800/- PMT the duty should have been Rs. 4147 i.e., 118.53% (Dumping margin in preliminary finding) of Rs. 3499 (c.i.f. export price).
- 64.4. The authority should levy the duty retrospectively. There is a clear history of dumping from China as China is appearing in many of the anti-dumping investigations causing injury to the domestic industry.
- 64.5. Injury is caused by imports from China. The import of coke from non-dumped sources is not causing injury as majority of such imports were by TISCO who is a captive consumer. The purchase from the "merchant coke" market by TISCO was minimal. Whereas the imports from other countries have remained stagnant, imports from China have grown significantly.

65. Views of Importers & Exporters On injury:

- 65.1. The injury analysis has not been done objectively. ICA (Dhanbad) do not form domestic industry and should be excluded from the injury analysis also. In the preliminary findings, there is no indication as to who are all the domestic manufactures whose economic indicators were taken into account.
- 65.2. The injury margin calculations of the petitioner are not correct. The cost claimed by the petitioner deserves careful scrutiny, and the saving that would result from an optimum blend of various type of coal by others should be taken into account. If such cost savings are also taken into account, as they ought to be, the injury margin will disappear. The injury margin worked out in the preliminary findings is on the higher side.
- 65.3. The user industry of metcoke is under severe strain and is operating currently at less than 50% of the installed capacity. The pig iron industry has reduced the prices. The cost of metcoke constitute about 40% of the cost of production of pig iron. Any increase in cost of LAMC is bound to increase the final cost of pig iron resulting in the inability of pig iron manufactures to sell their products. Any anti-dumping duty on LAMC will result in the complete closure of all the pig iron units and will result into loss of direct and indirect employment.
- 65.4. The cost of production by domestic industry is high as compared to others who are able to tap the by-products and produce electricity and steam. The petitioner are not recovering the volatile substance to produce valuable by products. This is the main reason for suffering the injury and not the alleged dumping from China.
- 65.5. The total availability of LAMC out of imported coal is less than 5 lac tonnes whereas the requirement is more than 2 million tonnes. Pig Iron Manufacturers have to

necessarily import and it does not make sense to impose duty on such huge volumes. Any protection to the domestic manufactures of LAMC will result in serious injury to the pig iron manufacturers.

- 65.6. There is no evidence to suggest or establish that any closure of units in India took place by reason of any alleged dumping of metcoke. The allegation made by petitioner are vague and are totally unsubstantiated.
- 65.7. Increase in import of Chinese coke was due to the increase in the requirement of met coke over the years. The allegation with regard to profitability of domestic industry and capacity utilisation are totally misconceived
- 65.8. The provisional anti-dumping duty @ Rs. 1800 PMT levied threatens the very survival of MBF industry. MBF capacity of over 3 million tonnes per annum has been set up during past 5 years involving an investment of Rs. 3000 crores and employment of over one lakh people. The impact of anti-dumping duty on cost of pig iron/steel works out to Rs. 1400. At this level, imports of pig iron are more attractive. This will spell closure for the pig iron producers and drain of foreign exchange for import of pig iron. Domestic metcoke can not be used by MBF for quality reasons, and thus anti-dumping duty does not really help the domestic coke producers.
- 65.9. It is submitted by importer that there is no injury to domestic industry. The production and capacity utilisation has increased and also the demand for LAMC has increased over the years. In fact, the production and sales are inadequate to meet the local demand. The installed capacity is inadequate to meet the demand. The import of LAMC by companies who are excluded for the purpose of domestic industry, should be excluded for injury purpose. It is also argued that there is no causal link between decline in market share and import of LAMC. Domestic manufacturer are able to recover their full cost of production along with reasonable profit and are able to obtain more than a fair selling price of the product.

INJURY ANALYSIS BY THE AUTHORITY

66. Under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, "taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles..." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
67. Annexure II(iii) under rule 11 supra further provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti Dumping investigation, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article, and cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
68. The Authority notes that the margin of dumping and quantum of imports from subject country are more than the limits prescribed above. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the export prices from the subject country were directly competing with the prices offered by the domestic industry in the Indian market.

69 For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such further indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II (iv) of the rules supra.

69.1 Volume and market share of dumped imports: The volume of dumped Chinese coke in absolute terms increased rapidly. The following tables will illustrate this:

Year	Tonnes
1993-94	79452
1994-95	562451
1995-96	964936
1996-97	741100

69.2. From the above it is observed that the import of Chinese coke into the Indian market has increased from 79452 tonnes in 93-94 to 741100 tonnes in 96-97, showing an increase of 834%. There is, however, a decline in the year 1996-97 over the previous year. The Authority observes that even though there is decline in the overall market in 1996-97, total import volumes from subject country have increased.

69.3. Market Share: The following table gives a summary of market share of low ash metcoke domestic producers as against that of dumped Chinese goods:

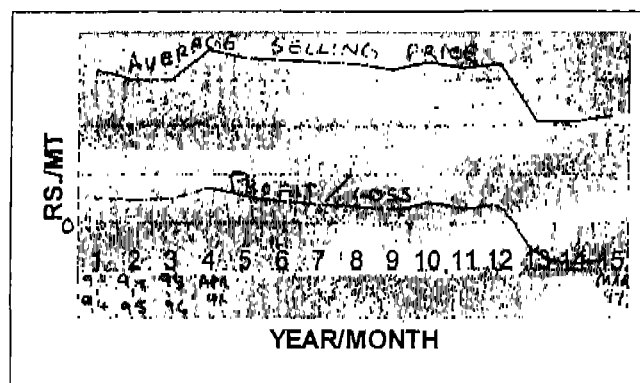
Year	96-97	95-96	94-95
Total market of metcoke in India (tonnes)	1244818	1415391	796922
Production of petitioners (BLA)	119337	115862	87512
Production of others	120908	122026	41345
Total production of "Domestic Industry"	240245	237888	128857
Market share of domestic producers	19.30%	16.8%	16.2%
Imports from China	741100	964936	562451
Market share of imports from China	59.5%	68.2%	70.6%
Imports from Countries (other than China)	263473	212567	105614
Market share of other countries	21.2%	15.0%	13.2%

69.4. Profitability of petitioners: It is observed that there is a decline in gross contributions of petitioner shown below:

Year	Cost of sales Rs. PMT	Selling price Rs. PMT	Contribution Rs. PMT
1994-95	****	****	****
1995-96	****	****	****
1996-97	****	****	****

It is also observed that in last quarter Jan-97, the petitioner has reduced their selling price to ****, whereas the cost of production was ****. Thus they incurred a loss of **** during the period. Analysis of average selling prices and profit/loss during the investigation period shows as under:

230451198



- 69.5. M/s. Wellman Incandescent India has stated that dumping from China has forced them to seek registration with Bureau of Industrial Finance and Reconstruction (BIFR), as their net worth is eroded due to accumulated losses. BIFR has passed an order on 5.5.98, wherein they have observed that one of the reasons cited by the company has been the dumping of goods from China. It is also observed that petitioner has shut down its 1/3 capacity with effect from April 97. The Authority further observes that M/s. Gujarat NRE Coke Ltd. had capacity utilisation of only 50.8% in 1996-97. Similarly, M/s Wellman Incandescent India showed a decline in their capacity utilisation from 63.65% in the year 1995-96 to 61.90% in 1996-97. Further, due to withdrawal of orders by customers, they had repeated closure of their plant causing heavy financial losses.

- 69.6. Increase in closing stock: There is a substantial increase in closing stock of metcoke of the petitioner which is as under:

Year	Stock of Coke (MT)
1993-94	1215
1994-95	3051
1995-96	13861
1996-97	13150

- 69.7. Domestic Industry's Capacity Utilisation: It is observed that the capacity utilisation of the petitioner is as under:

Year	Capacity utilisation
1994-95	62.51%
1995-96	82.76%
1996-97	85.24%

- 69.8. Retrenchment of workers - There is a decrease in the number of people employed and industry has retrenched 296 workers in 1996-97 and 295 workers in 1997-98 as part of their production capacity shut down.

H. CONCLUSION ON INJURY AND CAUSAL LINK

- 70 The circumstances warrant consideration of injury for imports of coke from China. The import of Metcoke has increased significantly in absolute terms from China over the years. Export of metcoke from China forced the domestic industry to keep its price of Metcoke to unremunerative levels and prevented the domestic industry from recovering its fair selling price resulting in decrease in profits/losses. Various indicators relating to domestic industry

such as average sales realisation, stock, and decline in profits/losses collectively and cumulatively establish that the "Domestic Industry" has suffered material injury.

71. In establishing that the material injury to the domestic industry has been caused by the imports from China, the Authority has considered that exports of metcoke from China forced the domestic industry to keep its price to unremunerative levels, and prevented it to recover its fair price, resulting in decrease in profits/losses.

I. INDIAN INDUSTRY INTERESTS AND OTHER ISSUES

72. Anti Dumping Duties are levied, in order to arrest dumping which causes injury to domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the domestic market. It aims to redress the unfair advantages gained by dumping practices and prevent the decline of the domestic industry. Imposition of such duties would not restrict imports from the subject countries nor would they affect the availability of the product to the consumers. Normally, fair competition on the Indian market is not reduced by the anti dumping measures, particularly if the levy of the anti dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry.
73. It is however recognised that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have an effect on the relative competitiveness of these products or industries producing such products.
74. The Authority in an Anti Dumping investigation is required to expressly investigate to establish the presence of dumping, material injury to the industry and the causal link of such injury from imports from the subject country. The effect on the relative competitiveness of any other industry if anti dumping duties are levied is beyond the purview of the Authority's investigation.
75. Hence, certain information brought to the notice of the Authority during such investigation concerning import of Met Coke from the Peoples Republic of China and said to affect the Indian Iron and Steel Industry have not been expressly commented upon or taken note of by the Authority in these findings. The Authority has only taken note of the imports of Met Coke from China PR and its effect on dumping, material injury to Indian producers of Like Article and accordingly recommended levy of anti dumping duties.
76. The information placed before the Authority by various sectors of the Industry and others is summarised below:-
- (a) The producers of Like Article in the "Domestic Industry" will not be able to meet the LAMC requirements of the user industries in India.
 - (b) LAMC is a base Raw Material widely consumed directly or indirectly by the Pig Iron Industry, SS Iron Casting Industry, Ferro Alloys Industry, Foundries having cupolas and the Base Metal Industry particularly Zinc. These industries, in the core sector of the Indian economy add significant value to a primary raw material, contribute to export earnings, account for substantial employment and fulfill the requirement of inputs for a variety of infrastructure and consumer durable industries. Imposition of high levies of duties have the effect of making these industries and related industry sectors uneconomic and uncompetitive. This view has also been supported by the Ministry of Steel, Govt. of India.
 - (c) The Pig Iron industry itself has a Rs.3000 crores investment and a Rs.1140 crores investment in the pipeline. There is a high order of investment from IDBI, IFCI, ICICI and UTI. The Ministry of Steel supported the establishment of the Pig Iron Industry and from a position of net importers of Pig Iron, India today produces 3 million tonnes of Pig Iron and has exported 1 million tonnes of pig iron worth US \$ 140 million in 1997-98. The industry employs 30,000 persons directly.

(d) The SS Iron Casting Industry has exported products worth US \$ 160 million in 1997-98.

(e) The provisional duty levied has led to the closure of Mini Blast Furnaces and such duties will cause irreparable damage to the Pig Iron industry. As a result the Indian industry would have to import Pig Iron instead of Met Coke.

77. The Authority has already observed that investigation into representations of various sectors of the Iron and Steel Industry is not within the purview of the Anti Dumping investigations concerning LAMC from China PR.

78. The Authority however notes that India's total requirements of Met Coke were met with imports (as per DGCIS data) to the extent of :-

12,37,359 Mt in 1996-97

20,15,169 Mt in 1997-98 (15,11,377 MT in April-Dec., 1997 and 5,03,792 MT in Jan-March, 1998)

79. The domestic industry as defined in Para 30 of this order was able to meet 19.42% of such requirements with a production of 240245 MT in 1996-97. The total installed capacity of domestic industry is 4,08,000 MT and even if there is full capacity utilisation they would be able to meet only 20.25% of industry requirements as per 1997-98 figures of import. Coal is imported from Australia, China PR and other countries for the production of LAMC. The total investments in this industry is just over Rs.100 crores approx. and it employs about 2100 persons. The industry caters only to the domestic market and does not export its product.

J. FINAL FINDINGS

80. The Authority in view of foregoing concludes that:

- Irrespective of the fact that the members of ICA can produce metcoke with less than 15% ash content, the Authority is inclined to agree with the exporters/importers that only metcoke with ash content of 15% and below is a like article to the metcoke imported from China PR.
- Based on the information available with the Authority at the time of initiation, the petitioner had the standing to file the petition on behalf of the domestic industry. The petitioner satisfied the criterion for standing at the time of preliminary findings, considering the scope of the "like article", as defined in the preliminary findings. Petitioner now has support of 100% of those producers production of whose constitutes "like article".
- The Authority has constructed the normal value of metcoke in China PR based on the information furnished by the co-operative exporters and the information available with the Authority in view of incomplete and insufficient response by the exporters/producers from China PR in spite of specific requests for information.
- Metcoke originating in or exported from China PR has been exported to India below its normal value.
- The domestic industry has suffered material injury.
- Injury has been caused to the domestic industry by the exports originating in or exported from the subject countries.

81. The Authority confirms the preliminary findings with regard to imposition of Anti-dumping duty and recommends imposition of definitive anti-dumping duties on all imports of metallurgical coke originating in or exported from the People's Republic of China. The anti-dumping duty shall be the difference between Rs. 4673 and the landed price of imports per MT.

82. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3 and 3A of the Customs Tariff Act, 1975.
- 83 Subject to above, the Authority confirms the preliminary findings dated 20.3.1998.
- 84 An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act Supra.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

